

राजीव शर्मा और गुरविंदर सिंह गिल जे, के समक्ष

हरियाणा राज्य- अभियोजक

बनाम

अरुण और अन्य- प्रतिवादीगण

हत्या संदर्भ No.03/2017

06 दिसंबर, 2018

“मृत्युदंड "एकान्त कारावास"-भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. एस. 73, 74, 363, 366-ए, 302,201,376-ए, 376-डी-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012-धारा 6-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 1 और 413-कारागार अधिनियम, 1894-धारा 30 और 59-पंजाब जेल नियमावली-अध्याय 21। मृत्युदंड की पुष्टि के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से प्राप्त हत्या का संदर्भ-एस. एस. के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ दोषियों द्वारा अपील भी की जाती है। आई. पी. सी. की धारा 366-ए, 302,377 और पॉस्को अधिनियम की धारा 6-मृत्युदंड का अधिरोपण भी अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया-एक आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा भी अपील की गई-अपीलकर्ताओं को 9 साल के अभियोजक के बाद देखा गया-उसका शव अगले दिन सुबह पाया गया-खुलासे के अनुसार उनसे बरामदगी की गई-कपड़ों की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जांच की गई-मौत का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना था-अपीलकर्ताओं को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा दी गई थी-पकड़ लिया गया-श्रंखला/चेन पूरी हो गई है-दोषसिद्धि बरकरार रखी गई-मौत की सजा को हिंसक नहीं कहा जा सकता है लेकिन इसे समाज की सामूहिक चेतना को कुचल दिया है-मौत की सजा को परिवर्तित कर दिया गया है।

वर्तमान मामले में उस श्रंखला को पूरा किया गया है। पीडब्लू-30 संपत्ति ने भी अरुण की पहचान की है। वह उनकी आवाज़ से आरोपी की पहचान कर सकती थी क्योंकि वह उसी इलाके में रहती थी। शिकायतकर्ता के परिवार और आरोपी के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। पीडब्लू-17 राजेंद्र के बयान के अनुसार अभियोजक का मृत लड़का खुली जगह में पाया

गया था। आवाज का नमूना भी मेल खाता है। कुछ मुद्दों पर जांच दोषपूर्ण है अपीलार्थियों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन Recoveries के मामले को प्रभावित नहीं किया गया है। अभियोजक के शरीर पर कई चोटें हैं क्योंकि अभियोजक का गला घोंटा गया था जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से विधिवत साबित हुआ था।

(पैरा 42) ने आगे कहा कि प्रश्न किए गए आवाज के नमूनों की आवाज वर्णक्रमीय जांच से पता चला है कि चिह्नित किए गए सवाल किए गए आवाज के नमूने उनके प्रारूप आवृत्ति वितरण, स्वर विन्यास, स्वर विन्यास की संख्या और आवाज ग्राम में अन्य सामान्य दृश्य विशेषताओं के संबंध में चिह्नित किए गए आवाज के नमूनों के समान थे। संभवतः आवाज नरेंदर की थी। इसी तरह श्रीमती सन्मति की आवाज़ को उनकी नमूना आवाज के समान पाया गया। अभियुक्तों को एमएलआर रिपोर्ट Ex.PW5/A, पीडब्लू5/बी, पीडब्लू5/सी के अनुसार संभोग करने में सक्षम पाया गया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।

(पैरा 42) ने आगे कहा कि हमारा विचार है कि यह मामला अपीलार्थियों को मौत की सजा देने के लिए "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले" के दायरे में नहीं आता है। हालांकि अंतिम राय Ex.PW22/R के अनुसार, मृत्यु हिंसक है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने समाज के प्रति सामूहिक चेतना को प्रभावित किया है। युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी लेकिन इसे वीभत्स हत्या नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 48) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी अरुण, राजेश और दीपक को दिनांक 18.01.2017 and 19.01.2017 के निर्णय और आदेश के तुरंत बाद एकांत कारावास में भेज दिया गया था।

(पैरा 49) ने आगे कहा कि पंजाब राज्य ने पंजाब जेल नियमावली नामक नियम बनाए हैं। अध्याय XXIX मौत की सजा पाए कैदियों से संबंधित है। इन नियमों को हरियाणा राज्य द्वारा अपनाया गया है।

(पैरा 51) ने आगे कहा कि पैरा 758 में यह प्रावधान है कि मृत्युदंड के तहत प्रत्येक कैदी को सजा के बाद जेल में आने के तुरंत बाद, उपाधीक्षक द्वारा या उसके आदेश से तलाशी ली जाएगी और उससे उन सभी वस्तुओं को लिया जाएगा जिन्हें उपाधीक्षक अपने कब्जे में रखना खतरनाक या अनुचित समझता है। प्रत्येक कैदी को अन्य सभी कैदियों के अलावा एक कोठरी में रखा जाना है, और दिन में और रात में एक गार्ड के प्रभार में रखा जाना है।

(पैरा 52)

इसके अलावा यह भी कहा गया कि पंजाब जेल नियमावली के पैराग्राफ से यह स्पष्ट है कि मौत की सजा पाए प्रत्येक कैदी को अन्य सभी कैदियों के अलावा एक कोठरी में रखा जाना है और उसे दिन और रात में एक विशेष गार्ड के प्रभार में रखा जाना है। अधीक्षक के अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति उसके साथ संवाद नहीं कर सकता है। मौत की सजा पाए कैदी को हर सुबह और शाम केवल आधे घंटे के लिए अपनी कोठरी के कोर्ट यार्ड में रहने की अनुमति है। सूर्यास्त से सूर्योदय तक रोशनी जलती रहती है ताकि कैदी हर समय निगरानी में रहे, हालांकि उसे रिश्तेदारों, दोस्तों, कानूनी सलाहकारों और अनुमोदित धार्मिक मंत्रियों के साथ साक्षात्कार के मामले में उचित संलिप्तता की अनुमति है।

(पैरा 73) ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने "कैदियों के साथ व्यवहार के लिए मानक न्यूनतम नियम" निर्धारित किए हैं जिन्हें "नेल्सन मंडेला नियम" कहा जाता है।" नियम 45 परिभाषित करता है कि एकान्त कारावास का उपयोग केवल असाधारण मामलों में अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा, जितना संभव हो उतना कम समय के लिए और स्वतंत्र समीक्षा के अधीन, और केवल एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण के अनुसार। यह किसी कैदी की सजा के आधार पर नहीं लगाया जाएगा। मानसिक या शारीरिक अक्षमता वाले कैदियों के मामले में एकांत कारावास के अधिरोपण को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जब इस तरह के उपायों से उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी।

(पैरा 75) ने आगे कहा कि ऊपर उद्धृत पैरा 368 के अनुसार, मृत्युदंड के तहत प्रत्येक दोषी को अन्य सभी कैदियों के अलावा एक कोठरी में रखा जाना है और उसे दिन और रात में एक विशेष गार्ड के प्रभार में रखा जाना है। उसे अपनी कोठरी के सामने बरामदे में रहने के लिए सुबह और शाम को केवल आधे घंटे की अनुमति है। इस अवधि के दौरान, दोषी को हथकड़ी लगाकर रहना पड़ता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मौत की सजा के तहत दोषी को एक अलग कोठरी में रखा जाना है। उसे बरामदे में रहने के लिए अपनी कोठरी से बाहर आने के लिए केवल आधे घंटे की अनुमति है। उसे प्रकाश की नज़रों के नीचे रखा जाता है। उसे हमेशा पहरेदारों की निगरानी में रखा जाना चाहिए।

(पैरा 86) ने आगे कहा कि जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, एक दोषी को एक अलग कोठरी में रखने से उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह उन्हें दिल की धड़कन (आराम करते समय तेज और/या तेज दिल की धड़कन की जागरूकता), डायफोरेसिस (अचानक

अत्यधिक पसीना आना), अनिद्रा, पीठ और अन्य जोड़ों में दर्द, दृष्टि में गिरावट, खराब भूख, वजन में कमी और कभी-कभी दस्त, सुस्ती, कमजोरी, कंपन (हिलना), ठंड लगना, पहले से मौजूद चिकित्सा समस्याओं का बढ़ना, चिंता, तनाव की भावनाओं से लेकर पूरी तरह से घबराए हुए पैनिक अटैक तक, लगातार निम्न स्तर का तनाव, चिड़चिड़ापन या चिंता, आसन्न मृत्यु का डर, पैनिक अटैक, अवसाद, कम मनोदशा से लेकर नैदानिक अवसाद तक, भावनात्मक सपाटपन/धुंधलापन-किसी भी 'भावनाओं' को रखने की क्षमता में कमी, भावनात्मक क्षमता (मनोदशा में बदलाव), निराशा, सामाजिक वापसी; गतिविधि या विचारों की शुरुआत में कमी; उदासीनता; सुस्ती, प्रमुख अवसाद, क्रोध, चिड़चिड़ापन से लेकर पूर्ण क्रोध, चिड़चिड़ापन और शत्रुता, खराब आवेग नियंत्रण, दूसरों के खिलाफ शारीरिक और मौखिक हिंसा के प्रकोप, स्वयं और वस्तुओं, अकारण क्रोध, कभी-कभी क्रोध के रूप में प्रकट होना, संज्ञानात्मक दीवारें बंद हो रही हैं), समय और स्थान में भटकाव, भिचारीकरण/अवास्तविकता, सभी पांच इंद्रियों को प्रभावित करने वाले मतिभ्रम, दृश्य, श्रवण, स्पर्श, घ्राण और स्वाद (कोशिका में दिखाई देने वाली वस्तुओं या लोगों का, या जब कोई वास्तव में बोल नहीं रहा होता है तो आवाजें सुनना), व्यामोह और मनोविकृति, जुनूनी विचारों से लेकर पूर्ण विकसित मनोविकृति तक, बार-बार और लगातार विचार (अफवाहें) अक्सर हिंसक और प्रतिशोधी चरित्र (जैसे। जेल कर्मचारियों के खिलाफ निर्देशित), पागल विचार-अक्सर उत्पीड़न, मनोविकृत प्रकरण या कहते हैं: मनोवैज्ञानिक अवसाद, सिज़ोफ्रेनिया, आत्म-क्षति और आत्महत्या आदि की स्थिति का कारण बनता है।

(पैरा 87) ने आगे कहा कि कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि एकांत कारावास का उपयोग केवल असाधारण मामलों में अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। यह किसी कैदी की सजा के आधार पर नहीं लगाया जाएगा। एकांत कारावास का अर्थ है अर्थपूर्ण मानव संपर्क के बिना एक दिन में 22 घंटे या उससे अधिक समय तक कैदियों को कैद करना। लंबे समय तक एकांत कारावास लगातार 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए एकांत कारावास को संदर्भित करेगा।

(पैरा 88) ने आगे कहा कि पंजाब जेल नियमावली में कहा गया है कि वार्डर किसी भी व्यक्ति को अधिकृत व्यक्ति के अलावा कैदी के पास जाने या उससे बात करने की अनुमति नहीं देगा। उन्हें एक दिन में 23 घंटे से अधिक समय तक पृथक-वास में रहना चाहिए। यह नेल्सन मंडेला के नियमों के खिलाफ है। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। उसे

एकांत कारावास में रखा गया है।

जब तक वह बरी नहीं हो जाता या उसे क्षमा नहीं कर दिया जाता या फांसी नहीं दी जाती,। ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कि मौत की सजा पाए दोषी को अनिश्चित काल के लिए अलग-थलग क्यों रखा जाना चाहिए जब तक कि वह अपने सभी संवैधानिक और कानूनी उपायों को समाप्त नहीं कर देता। यह दोषी को अत्यधिक पीड़ा, पीड़ा और चिंता का कारण बनता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) और 21 का उल्लंघन है। एक व्यक्ति, जिसे मौत की सजा भी सुनाई गई है, उसके पास कुछ विशेषाधिकार और अधिकार हैं जिन्हें औपनिवेशिक मानसिकता के कारण उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। पंजाब जेल नियमावली के प्रावधान अराजक, क्रूर और असंवेदनशील हैं।

(पैरा 89) ने आगे कहा कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए और दमनकारी और मनमाना नहीं होनी चाहिए। कानून न तो हिमनदीय होना चाहिए और न ही दूरस्थ। कानून सभ्यता का ढांचा और गारंटर होना चाहिए।

(पैरा 91) ने आगे कहा कि दोषी को उसके संवैधानिक, कानूनी और मौलिक अधिकारों के समाप्त होने से पहले हिरासत में अलग/एकांत कारावास में रखने की प्रथा कानून के अधिकार के बिना है। यह अतिरिक्त सजा होगी। यह उनके मूल मानवाधिकारों को प्रताड़ित करने और उनका उल्लंघन करने के बराबर भी है।

(पैरा 92) ने आगे कहा कि तदनुसार, हम हरियाणा राज्य में जेल अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रथा को समाप्त कर देते हैं, जिसमें निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद और उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि के बाद मौत की सजा पाए दोषी को अलग करने की प्रथा असंवैधानिक है। दोषी को तब तक अलग/अलग नहीं किया जाएगा जब तक कि मौत की सजा अंतिम, निर्णायक और अक्षम्य नहीं हो जाती जिसे किसी भी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा रद्द या रद्द नहीं किया जा सकता है। मृत्युदंड की सजा पाए दोषी को अलगाव/अलगाव में रखने की अवधि कम से कम संभव समय यानी 2 से 3 दिनों के लिए होनी चाहिए।

(पैरा 93)

विनोद घई, वरिष्ठ अधिवक्ता

अमृत S.Kang, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता

सी. आर. ए.-डी-98-डी. बी.-2017 और सी. आर. ए.-डी-104-डी. बी.-2017 में

गौरव महंता, अधिवक्ता

प्रीति अग्रवाल, अधिवक्ता

सी. आर. ए.-डी.-187-डी. बी.-2017 में अपीलार्थी के लिए

S.P.Yadav, अधिवक्ता

सी. आर. एम.-ए-993-एम. ए.-2018 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम अरुण और अन्य में आवेदक के लिए

शुभरा सिंह, एडिशनल। ए. जी. हरियाणा।

राजीव शर्मा, जे

(1) चूँकि कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न उपरोक्त हत्या के संदर्भ और अपीलों में शामिल हैं, इसलिए इन्हें एक साथ लिया जाता है और एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जाता है।

(2) वार्ड नं. 10, मंडी अटेली, जिला मोहिंदरगढ़ के निवासी 1. सुभाष चंद के पुत्र अरुण, 2. दीपक पुत्र महेंद्र, 3. राजेश पुत्र रोहताश, को सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल के निर्णय और आदेश दिनांक 18.01.2017/19.01.2017 के अनुसार, 2017 का हत्या संदर्भ (आईडी1) प्राप्त हुआ है।

(3) आपराधिक अपील सं। डी-98-डी. बी.-2017 को अरुण द्वारा प्राथमिकता दी गई है; आपराधिक अपील सं. राजेश द्वारा डी-104-डी. बी.-2017 और आपराधिक अपील सं. डी-187-डी. बी.-2017, दीपक द्वारा दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध, जिसमें अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366-ए, 302, 201, 376-ए, 376-डी (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था और मुकदमा चलाया गया था। अपीलार्थी दीपक को दोषी ठहराया गया और आई. पी. सी. की धारा 366-ए के तहत अपराध के लिए दो साल के लिए एस. आई. से गुजरने के लिए सात साल के लिए कठोर कारावास और Rs.10,000/- का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई। राजेश और अरुण के साथ दीपक को दोषी ठहराया

गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 1,000/- का जुर्माना लगाया गया और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध के लिए तीन साल के लिए एस. आई. से गुजरना पड़ा। दीपक, राजेश और अरुण को भी फांसी की सजा सुनाई गई जब तक कि वे मर नहीं जाते और प्रत्येक पर Rs.20,000/- का जुर्माना लगाया गया। अपीलार्थियों को दी गई मौत की सजा इस न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन थी।

(4) शिकायतकर्ता इंदु ने आपराधिक अपील नं (सी. आर. एम.-ए-993-एम. ए.-2018)। संजय चौधरी को बरी किए जाने के खिलाफ दरज की, सुनवाई की तारीख पर अपील दायर करने की अनुमति दी गई थी। याचिका पर योग्यता के आधार पर सुनवाई की गई है।

(5) संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 01.11.2014 लगभग 11.25 p.m बजे बलवान सिंह ए. एस. आई. एच. सी. जुगल किशोर और सिपाही अनिल कुमार के साथ पुराने बस स्टैंड अटेली के पास गश्त कर रहे थे। शिकायतकर्ता राकेश कुमार की पत्नी इंदु पेश हुई और एक आवेदन भेजा। आवेदन में किए गए कथन के अनुसार, उसकी लगभग 9 साल की बेटी (नाम नहीं बताया गया) शाम 5:30 बजे पड़ोसी भूखंड/plot में चूहे को छोड़ने गई थी। वह वापस नहीं आई। उन्होंने उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। उसकी बेटी की तलाश की जा सकती है। रुका को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। एफ. आई. आर. दर्ज की गई। याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी चिकित्सकीय जांच की गई। उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए। धारा 161 Cr.P.C के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जाँच रिपोर्ट तैयार की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बोर्ड की राय Ex.PW22/R है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट Exs.P22/B और PW22/C हैं। रिकवरी प्रभावित हुई। एफएसएल रिपोर्ट Ex.PW22/J, पीडब्लू22/के, पीडब्लू22/एन, पीडब्लू22/पी, पीडब्लू22/क्यू के माध्यम से प्राप्त की गई थी। जांच पूरी हो गई थी और सभी नोडल औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चालान रखा गया था। दो पूरक चालान भी लगाए गए।

(6) अभियोजन पक्ष ने 37 गवाहों से पूछताछ की। अपीलार्थियों के बयान भी धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए थे। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया है।

(7) अपीलार्थी अरुण, राजेश और दीपक को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत मौत

की सजा सुनाई गई; पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आई. पी. सी. की धारा 377 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि दीपक को आई. पी. सी. की धारा 366-ए के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई। इसलिए उनकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ ये अपीलें; विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल द्वारा मौत की सजा की पुष्टि के लिए मौत का संदर्भ; और संजय चौधरी को बरी करने के खिलाफ एक अपील है।

(8) अपीलार्थियों (दोषियों) की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा है।

(9) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने 18.01.2017/19.01.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश का समर्थन किया है।

(10) अपीलार्थी इंदु देवी की ओर से पेश विद्वान वकील एस. पी. यादव ने जोरदार तर्क दिया है कि संजय चौधरी को गलत तरीके से बरी कर दिया गया है।

(11) हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और निर्णय को पढ़ा है और बहुत सावधानी से रिकॉर्ड किया है।

(12) पीडब्लू-1 फूल कुमार ने घटना स्थल और पोस्टमॉर्टम जांच की सीडी को Ex.MO-1 और Ex.MO-2 के रूप में साबित किया है।

उन्होंने घटना स्थल की तस्वीरों को Ex.P1 से Ex.P6 के रूप में भी साबित किया।

(13) पीडब्लू-2 बिजेंद्र सिंह एस. आई. ने एक औपचारिक एफ. आई. आर. Ex.PW2/A. दर्ज की है।

(14) पीडब्लू-3 रणवीर सिंह एएसआई ने गवाही दी कि 04.11.2014 पर आरोपी दीपक ने एक बयान Ex.PW3/A दिया। उसके बयान के आधार पर, घटना के स्थान का सीमांकन किया गया था जहाँ से उसने अभियोजक को लुभाया था। अभियुक्त अरुण ने बयान Ex.PW3/B भी दिया। उस स्थान का भी सीमांकन किया गया था जहाँ अभियोजक का शव फेंका गया था। उसके बयान पर, मोटर साइकिल भी बरामद की गई थी। अभियुक्त राजेश ने बयान Ex.PW3/C भी दिया जिसके आधार पर घटना स्थल का भी सीमांकन किया गया था जहाँ शव फेंका गया था। अभियुक्तों को 03.11.2014 पर गिरफ्तार किया गया था।

(15) पीडब्लू-4 एच. सी. जुगल किशोर ने गवाही दी कि शव के पास से बेल्ट के साथ नीले रंग की एक पतलून, एक अंडरवियर और हरे और पीले रंग की चप्पल बरामद की गई। इन्हें कब्जे में ले लिया गया। दीपक पुलिस दल को उस स्थान पर ले गया जहाँ मृतक को वह बहला-फुसलाकर ले गया था। उस स्थान का सीमांकन Ex.PW4/B के माध्यम से किया गया था। जिस स्थान पर चूहे का जाल छोड़ा गया था, उसका सीमांकन भी Ex.PW4/C के माध्यम से किया गया था। जिस स्थान पर शव फेंका गया था, उसका सीमांकन भी आरोपी दीपक द्वारा ज्ञापन/memo no. Ex.PW4/E के माध्यम से किया गया था। उसने सभी ज्ञापनों/memos पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह आरोपी राजेश और अरुण ने पुलिस दल का नेतृत्व किया और क्रमशः Ex.PW4/F, Ex.PW4/G और Ex.PW4/H, Ex.PW4/K के माध्यम से शव को फेंकने की घटना और स्थान की ओर इशारा किया। सोफे से कुछ कपड़े भी बरामद किए गए। कैलोड्रोपिस पौधे (आक पौधा) की कुछ खून से सना पत्ते भी कब्जे में ले लिए गए।

(16) पीडब्लू-5 Dr.Ashish राव ने अपीलार्थियों की चिकित्सकीय जांच की थी। अभियुक्त दीपक के संबंध में उसकी राय के अनुसार, यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था कि व्यक्ति संभोग करने के लिए सक्षम नहीं था। उन्होंने राजेश की भी जांच की। उनकी राय के अनुसार, यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था कि व्यक्ति संभोग करने के लिए सक्षम नहीं था। उन्होंने अरुण से भी पूछताछ की। उनकी राय के अनुसार, यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था कि व्यक्ति संभोग करने के लिए सक्षम नहीं था। उन्होंने संजय चौधरी की चिकित्सकीय जांच भी की।

(17) पीडब्लू-6 स्वरूप सिंह ज़रूरी गवाह हैं। उनके अनुसार, वह उबले हुए अंडे बेचते थे और आमलेट बनाते थे। अपीलार्थी कभी अंडे या आमलेट खाने के लिए उसके पास नहीं आया था। विद्वान लोक अभियोजक/सरकारी वकील द्वारा उन्हें शत्रुतापूर्ण/hostile घोषित किया गया और उनसे जिरह की गई।

(18) पीडब्लू-7 ब्रह्म प्रकाश इंस्पेक्टर ने आंशिक रूप से जांच की है
मामला।

(19) पीडब्लू-8 योगेश कुमार एएसआई ने बयान दिया कि 04.11.2014 पर, महेंद्र सिंह एस. आई./एस. एच. ओ. ने अपीलार्थियों के फोन का कॉल विवरण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

(20) पीडब्लू-9 मनोज कुमार ने बयान दिया कि भालेंद्र यादव ने आरोपी अरुण, दीपक और राजेश द्वारा किए गए इकबालिया बयानों की वीडियोग्राफी की एक सीडी मलखान सिंह एस. आई./एस. एच. ओ. को सौंप दी। इस सीडी को Ex.PW9/A के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया था।

(21) पीडब्लू-10 सोमबीर, पीडब्लू-11 अनिल कुमार, पीडब्लू-12 समय सिंह, पीडब्लू-13 ईएसआई रोहताश सिंह, पीडब्लू-14 जय प्रकाश और पीडब्लू-15 मुकेश कुमार औपचारिक गवाह हैं।

(22) पीडब्लू-16 कलेक्टर एक भौतिक गवाह है। उनके अनुसार, वह 1991 से रतन लाल एंड कंपनी के शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में काम कर रहे थे। दिनांक 01.11.2014 पर अपीलार्थी राजेश शराब की दुकान पर आया और उससे लगभग शाम 7 बजे आधा खरीदा। वह दैनिक ग्राहक था।

(23) पीडब्लू-17 राजेंद्र ने अपदस्थ/बताया कि वह अन्य निवासियों के साथ लड़की की तलाश कर रहा था। लड़की का शव रात 9:30 बजे खुली जमीन में मिला।

(24) पीडब्लू-19 राजेश यादव ने पदच्युत किया कि 01.11.2014 पर उनके भतीजे निशांत का लगान समारोह था। उन्हें शत्रुhostile गवाह घोषित कर दिया गया था। उन्होंने बयान Ex.PW19/A का खंडन किया है। हालाँकि उन्होंने वार्ड नं.10. कि घटितघटना को कबूल किया है

(25) पीडब्लू-20 अशोक कुमार औपचारिक गवाह हैं।

(26) सरदार सिंह के बेटे पीडब्लू-21 बिजेंद्र ने अपदस्थ कर दिया/बयान दिया

कि वह एक फोटोग्राफी की दुकान चला रहा था। उन्होंने अशोक कुमार के घर पर लगान समारोह की वीडियोग्राफी की थी।

(27) पीडब्लू-22 Dr.Jagmohan ने पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट Ex.PW22/B साबित की। उन्होंने Ex.PW22/R पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए हैं।

(28) पीडब्लू-23 मलखान सिंह ने बयान दिया है कि संपति और नरेंद्र सिंह को आवाज के नमूने देने के लिए कहा गया था। उन्होंने धारा 161 Cr.P.C के तहत संपति के बयान दर्ज

किए थे। आरोपी संजय चौधरी का पॉलीग्राफ परीक्षण किया गया था। उन्होंने रिपोर्ट Ex.PW22/F और Ex.PW22/G को भी साबित किया। उन्होंने स्थान का सीमांकन भी कराया और अक्स शाजरा तैयार किया।

(29) पीडब्लू-24 बहलेंदर यादव ने बयान दिया कि यह मामला टीवी चैनल में रिपोर्ट किया गया था। प्रेस संवाददाताओं को पुलिस द्वारा डीएसपी (मुख्यालय), नारनौल के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया गया था। तीनों आरोपी अरुण, दीपक और राजेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वीडियो Ex.MO-9 के माध्यम से तैयार किया गया था। उन्होंने अदालत में अपीलार्थियों की पहचान की है। तीनों व्यक्तियों ने अलग-अलग अपना इकबालिया बयान दिया था।

(30) पीडब्लू-25 प्रदीप कुमार ने गवाही दी कि उन्होंने अभियोजक की तलाश में भाग लिया था। वह एक खाई में नग्न अवस्था में पाई गई।

(31) पीडब्लू-26 इंदु अभियोजक की माँ है। उसने शिकायत पर हस्ताक्षर Ex.PW26/A की पहचान की थी।

(32) पीडब्लू-27 एसआई बलवान सिंह ने बयान दिया कि पीडब्लू-26 ने उनके समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने जाँच की कार्यवाही का संचालन किया। मृतक के कपड़े कब्जे में ले लिए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल, नारनौल भेज दिया गया। अभियुक्तों को एस. आई. महेंद्र सिंह ने गिरफ्तार किया। उनके पास से मोबाइल बरामद किया गया। उन्होंने मोबाइल फोन की पहचान की जिसे 03.11.2014 पर आरोपी से जब्त कर लिया गया था। उन्होंने उन फोनों की भी पहचान की जो संजय चौधरी के कब्जे में लिए गए थे।

(33) पीडब्लू-28 सुरेंद्र सिंह ने संजय चौधरी की पॉलीग्राफिक परीक्षण रिपोर्ट को Ex.PW22/P साबित किया है।

(34) पीडब्लू-29 नरेंद्र एक भौतिक/ज़रूरी गवाह है। उसने गवाही दी कि वह खाली भूखंड/plot की ओर चला गया था। उन्होंने देखा कि अभियोजक प्लॉट नं. करने जा रहा है। एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। मृतक की माँ ने उसकी बेटी के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। उसने उसे बताया कि उसने उसे हाथ में चूहे का जाल लिए जाते देखा था और उसके पीछे एक लड़का आया। शव सुबह 6 बजे मिला। उसने अदालत में अरुण की पहचान

की। उसने अदालत में दीपक की पहचान भी की। उसने अदालत में राजेश की पहचान भी की। अभियुक्तों ने स्थानों का सीमांकन करवा लिया था। उसने अभियुक्त द्वारा किए गए इकबालिया बयान पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि उनकी उपस्थिति में किसी से पूछताछ नहीं की गई थी। पूरक चालान दाखिल करने के बाद उन्हें आगे की जांच के लिए भी बुलाया गया था। उसने अपनी आवाज़ के साथ-साथ आरोपी राजेश के पिता रोहताश की आवाज़ की पहचान की। उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना दिया था।

(35) पीडब्लू-30 संपत्ति ने गवाही दी कि वह घर में मौजूद थी। लगभग 3 बजे वह एक खाली भूखंड/plot की ओर प्रकृति के आह्वान/मल त्यागने का जवाब देने गई थी। उसने लड़कों की आवाज़ सुनी कि उन्होंने एक गंभीर अपराध किया है। वह अपने घर वापस आ गई। उसने अभियुक्तों में से एक अरुण की पहचान की। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। उनकी आवाज का नमूना नरेंद्र के साथ लिया गया था। विद्वान लोक अभियोजक/सरकारी वकील द्वारा उसे शत्रुतापूर्ण/hostile घोषित किया गया और उससे जिरह की गई। उनका सामना वीडियो Ex.PW23/A द्वारा दिए गए उनके बयान से किया गया था।

(36) पीडब्लू-31 महेंद्र सिंह ने बयान दिया कि उन्होंने बलवान सिंह से पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया था। उसने अरुण, राजेश और दीपक को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों से पूछताछ की गई। उन्होंने खुलासा करने वाले बयान दिए। उन्होंने मोबाइल फोन के कॉल विवरण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया। अभियुक्तों द्वारा वसूली की गई। सोफे सेट और लोहे के ड्रम को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मोटर साइकिल भी बरामद की गई। पीडब्लू-31 महेंद्र सिंह को वापस बुला लिया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि 06.11.2014 पर संजय चौधरी की रिमांड की मांग के लिए आवेदन दिया गया था। आरोपी संजय चौधरी द्वारा न तो कोई बरामदगी की गई और न ही उससे पूछताछ के दौरान कोई नया तथ्य सामने आया।

(37) पीडब्लू-33 अमित को पूरक चालान दाखिल करने के बाद जांच के लिए बुलाया गया था। उन्होंने पदच्युत किया कि 12.02.2016 पर वह अपनी माँ और पीडब्लू काका के

साथ उनके घर में मौजूद थे। राजेश के पिता रोहताश उनके घर आए। काका, रोहताश और उनकी माँ संपत्ति एक-दूसरे से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने मोबाइल सिम में रोहताश, संपत्ति और काका की बातचीत को रिकॉर्ड किया। अपनी जिरह में उन्होंने स्वीकार किया था कि वह आवाज रिकॉर्ड करने में विशेषज्ञ नहीं थे।

(38) पीडब्लू-35 प्रीतम @तिलू ने अपदस्थ किया कि वह 12.02.2016 पर पुलिस स्टेशन गया था। उन्होंने बातचीत की रिकॉर्डिंग के बारे में अपना बयान दिया।

(39) पीडब्लू-36 अशोक कुमार ने स्थल योजना Ex.PW36/A तैयार की थी।

(40) पीडब्लू-37 अमितोश कुमार ने रिपोर्ट Ex.PW37/A और पीडब्लू 37/बी को साबित किया है।

(41) ऊपर चर्चा किए गए बयानों की चर्चा से जो बात सामने आती है, वह यह है कि अभियोजक की आयु 9 वर्ष थी। वह शाम 5:30 बजे चूहे को छोड़ने के लिए अपने घर से निकली। वह वापस नहीं आई। उसकी माँ पुलिस के पास गई। उसका शव अगले दिन सुबह 6 बजे बरामद किया गया। अपीलार्थियों को अदालत में पीडब्लू-29 नरेंद्र द्वारा मान्यता दी गई थी। उसने अपीलकर्ताओं में से एक को लड़की का पीछा करते हुए भी देखा था। लड़की को एक कमरे में रखा गया था। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने पीडब्लू-16 कलेक्टर के बयान के अनुसार शराब का सेवन किया। अपीलकर्ताओं ने वसूली के आधार पर बयान दिये, कपड़े आदि को एफ. एस. एल. जांच के लिए भेजा गया था। इन रिपोर्टों को विधिवत साबित किया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पीडब्लू-22 Dr.Jagmohan द्वारा साबित की गई है। उन्होंने अंतिम राय Ex.PW22/R भी साबित कर दी है। Ex.PW22/R के अनुसार मृत्यु का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना था। बोर्ड ने बलात्कार की संभावना के बारे में राय दी है जो दिनांकित 27.01.2015 रिपोर्ट द्वारा विधिवत समर्थित है। मृत्यु हिंसक प्रकृति की थी। पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित चोटें दर्ज की गईं:- “स्तरी रोग संबंधी बाहरी परीक्षा दाएँ लैबिया मेजरा पर मौजूद नील 3x2 सेमी संदूषण, बाएँ पेरिनियल क्षेत्र पर मौजूद 5 x 4 सेमी आकार का संदूषण/नील। 8 x3 आकार का एक घर्षण चिह्न। दाएँ नितंब के बीच में मौजूद है। बाईं जांघ के पीछे के हिस्से पर एक सफेद चिपचिपा पदार्थ मौजूद था जिसे खुरचाया गया और नमूना लिया गया।

आंतरिक परीक्षा क्रमशः उच्च योनि, निचली योनि और गुदा क्षेत्र से 3 स्वाब और 3 स्मीयर तैयार किए गए थे।

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

आंतरिक जाँच पर प्रति योनि हाइमेन रक्तस्राव टूट गया था योनि छिद्र फैला हुआ था और उंगली पर प्रवेश कर रहा था।

गर्भाशय और एडेनेक्सा का निरीक्षण करने पर पेट खोलने पर, गर्भाशय आकार, आकार और स्थिरता में सामान्य पाया गया और एडेनेक्सा स्पष्ट था।”

सात बाहरी चोटें थीं। मृत्यु और पोस्टमॉर्टम जांच के बीच का संभावित समय 24 घंटे के भीतर था।

(42) वर्तमान मामले में श्रृंखला पूरी हो गई है। पीडब्लू-30 संपत्ति ने भी अरुण की पहचान की है। वह उनकी आवाज़ से आरोपी की पहचान कर सकती थी क्योंकि वह उसी इलाके में रहती थी। शिकायतकर्ता के परिवार और आरोपी के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। पीडब्लू-17 राजेंद्र के बयान के अनुसार अभियोजक का मृत लड़का खुली जगह में पाया गया था। आवाज का नमूना भी मेल खाता है। कुछ मुद्दों पर जांच दोषपूर्ण है लेकिन अपीलार्थियों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। पीडब्लू-37 अमितोष कुमार ने रिपोर्ट Ex.PW37/A को साबित कर दिया है और पीडब्लू37/बी. पीडब्लू-30 सनपति ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है, लेकिन मौके पर अपीलार्थियों की उपस्थिति के संबंध में भौतिक पहलुओं पर मामले को साबित किया है। अपीलार्थियों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर वसूली की गई है। पोस्टमॉर्टम के अनुसार अभियोजक के शरीर पर कई चोटें हैं) योनि की परत टूटा हुआ था। x आकार के तीन घर्षण थे। 75 से. मी., 75 से. मी x। 75 सेमी और। 75 x. 75 गर्दन के दाईं ओर और गर्दन के बाईं ओर सेंटीमीटर। 75 x. 75 सेमी संदूषण/नील और 2 x। 75 गर्दन पर सेमी घर्षण मौजूद था। दाहिनी लैबिया मेजरा पर 3 x 2 सेमी का संदूषण/नील था। बाएँ पेरिनियल क्षेत्र पर 5 x 4 सेमी आकार का एक संदूषण मौजूद था। दाहिने नितंब के बीच में 8 x 3 सेमी आकार का घर्षण का निशान मौजूद था। योनि का छिद्र फैला हुआ था। अभियोजक का गला घोंटा गया जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से विधिवत साबित हुआ। पी. डब्ल्यू.-26 इंदु द्वारा एफ़. आई. आर. की सामग्री को विधिवत साबित किया गया है। Ex-प्रदर्शनी 3 ए (अंडरवियर), Ex-प्रदर्शनी-4 ए (अंडरवियर), Ex- प्रदर्शनी-5 ए (अंडरवियर), Ex-प्रदर्शनी-5 बी (प्यूबिक हेयर) और Ex-प्रदर्शनी-6 ए (अंडरवियर) पर मानव वीर्य का पता चला।

हालांकि, वीर्य का पता Ex-प्रदर्शनी-1 ए (उच्च योनि स्मीयर), Ex-प्रदर्शनी-1 बी (निम्न योनि स्मीयर), Ex-प्रदर्शनी-1 ई (गुदा स्मीयर), Ex-प्रदर्शनी-1 डी (उच्च योनि स्वेब), Ex-प्रदर्शनी-1 ई (निम्न योनि स्वेब), Ex-प्रदर्शनी-1 एफ (गुदा स्वेब) पर नहीं लगाया

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

जा सका। रक्त का पता Ex.PW22/J के अनुसार Ex-प्रदर्शनी-1a (उच्च योनि स्मीयर), प्रदर्शनी-1b (निम्न योनि स्मीयर), प्रदर्शनी-1e (गुदा स्मीयर), प्रदर्शनी-1d (उच्च योनि स्वेब), प्रदर्शनी-1e (निम्न योनि स्वेब), प्रदर्शनी-1f (गुदा स्वेब), प्रदर्शनी-2 (शर्ट) और प्रदर्शनी 8 (पत्तियों) पर लगाया गया था। प्रदर्शनी-8 (पत्तियों) पर Ex.PW22/K के अनुसार रक्त का पता लगाया गया था। प्रदर्शनी-1a (अंडरवियर) पर मानव वीर्य का पता लगाया गया था। हालांकि, पी. डब्ल्यू. 22/एन. के अनुसार, प्रदर्शनी-1 (बी) (जीन्स) और प्रदर्शनी-2 (चप्पल) पर वीर्य का पता नहीं लगाया जा सका। Ex.PW37/A के अनुसार, विचाराधीन श्रवण परीक्षा में क्यू-1 (1) (ए) को चिह्नित किया गया था और Sh.Narender चिह्नित प्रदर्शनी एस-1 (1) (ए) की नमूना आवाज से पता चला कि प्रश्रित आवाज चिह्नित प्रदर्शनी क्यू-1 (1) (ए) उनकी भाषाई और ध्वन्यात्मक विशेषताओं के संबंध में नमूना आवाज चिह्नित प्रदर्शनी एस-1 (1) (ए) के समान थी। प्रश्न किए गए आवाज के नमूनों की आवाज वर्णक्रमीय परीक्षा से पता चला कि चिह्नित किए गए सवाल किए गए आवाज के नमूने उनके प्रारूप आवृत्ति वितरण, स्वर विन्यास, स्वर विन्यास की संख्या और अन्य सामान्य दृश्य विशेषताओं के संबंध में चिह्नित किए गए आवाज के नमूनों के समान थे। संभवतः आवाज नरेंद्र की थी। इसी तरह संपत्ति की सवालिया आवाज़ को उनकी नमूना आवाज के समान पाया गया। अभियुक्तों को एमएलआर रिपोर्ट Ex.PW5/A, पीडब्लू5/बी, पीडब्लू5/सी के अनुसार संभोग करने में सक्षम पाया गया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।

(43) बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्युदंड केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब आजीवन कारावास का विकल्प पूरी तरह से अपर्याप्त हो, और इसलिए निर्विवाद रूप से बंद कर दिया गया हो, अर्थात् यदि यह एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष है। बिगड़ती परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

1 (1980) 2 एस. सी. सी. 684

(44) सी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य ।

मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य 2

संबंधित अपील ने सजा और आनुपातिक विचारों के सामाजिक प्रभाव को निर्धारित किया है,

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

जब दुर्लभतम नियम के सिद्धांत को लागू किया जाना है । उनके लॉर्डशिप्स ने आगे कहा है कि दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा दी जा सकती है यदि किसी समुदाय की "सामूहिक अंतरात्मा" इतनी हैरान है कि मौत की सजा ही एकमात्र विकल्प है । "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला" तब आता है जब दोषी समाज के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एक खतरा और खतरा होगा । उनके अधिपत्य भी निम्नानुसार रहे हैं:-

“87. माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय ने बचन सिंह में सूचीबद्ध उत्तेजक कारकों से परे "दुर्लभतम से दुर्लभतम" सूत्रीकरण का विस्तार उन मामलों में किया जहां एक समुदाय की "सामूहिक अंतरात्मा" इतनी हैरान है कि वह न्यायिक शक्तियों के धारकों से अपेक्षा करेगा कि वे मृत्युदंड को बनाए रखने के संबंध में उनकी व्यक्तिगत राय के बावजूद मृत्युदंड दे सकते हैं, और कहा कि इन मामलों में ऐसा दंड लगाया जाना चाहिए । लेकिन इस मामले में पीठ/bench ने इस बात को रेखांकित किया कि किसी मामले में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जाना चाहिए । न्यायालय ने आगे कहा कि ध्यान में रखे जाने वाले प्रासंगिक कारक अपराध के उद्देश्य, या अपराध करने का तरीका, या अपराध की असामाजिक या घृणित प्रकृति हो सकते हैं, जैसे कि:

((i) हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की जाती है ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो ।

((ii) किसी विशेष जाति, समुदाय या इलाके के बड़ी संख्या में व्यक्तियों की हत्या की जाती है ।

((iii) एक निर्दोष बच्चे की हत्या; एक असहाय महिला की हत्या की जाती है ।

91. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आपराधिक कानून में प्रत्येक प्रकार के दोष के अनुसार सजा प्रदान करने में आनुपातिकता के नियम का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है ।

(2 (2010) 9 एस. सी. सी. 28)

समाज पर न्यायसंगत दंड न देने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपराधिक आचरण। "दुर्लभतम मामला" तब आता है जब एक दोषी समाज के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एक खतरा और खतरा होगा। जहाँ कोई अभियुक्त किसी भी क्षण के

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

उकसावे पर कार्य नहीं करता है और वह जानबूझकर नियोजित अपराध में लिप्त हो जाता है और उसे सावधानीपूर्वक निष्पादित करता है, ऐसे भयानक अपराध के लिए मौत की सजा सबसे उपयुक्त सजा हो सकती है।

92. आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। इसलिए, अदालत को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि मौत की सजा ही एकमात्र ऐसी सजा होगी जो किसी दोषी को दी जा सकती है। अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या कोई अन्य सजा पूरी तरह से अपर्याप्त होगी और मामले में कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियां क्या होंगी। हत्या हमेशा गलत होती है, हालाँकि, क्रूरता, दुष्टता और शैतानी प्रकृति की डिग्री प्रत्येक मामले में भिन्न होती है। जिन परिस्थितियों के तहत हत्याएं होती हैं, वे भी मामले-दर-मामले अलग-अलग होती हैं और उन परिस्थितियों को तय करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक फॉर्मूला नहीं हो सकता है जिनके तहत मौत की सजा दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, यह न केवल अपराध की प्रकृति है, बल्कि अपराधी की पृष्ठभूमि, उसका मनोविज्ञान, उसकी सामाजिक स्थिति, अपराध करने के लिए उसकी मानसिकता और समाज पर वैकल्पिक सजा लगाने का प्रभाव भी प्रासंगिक कारक हैं।”

(45) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य रवीन्द्र कुमार पाल @दारा सिंह बनाम भारत गणराज्य केस में मृत्युदंड लागू करने के सिद्धांतों की व्याख्या की। उनके अधिपत्य भी निम्नानुसार रहे हैं:-

“90. हालाँकि निचली अदालत ने दारा सिंह को मौत की सजा सुनाई, लेकिन उच्च न्यायालय ने पूरी सामग्री पर विचार करने और यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है, मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, माची सिंह बनाम पंजाब राज्य और केहर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा मृत्युदंड देने के संबंध में सिद्धांतों को अच्छी तरह से तय किया गया है। उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने पर, सामान्य नियम आजीवन कारावास की सजा और दुर्लभतम

मामलों में से दुर्लभतम के लिए सजा देना है ।

91***.क्या कोई मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले के अंतर्गत आता है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए और अदालत को उकसाने के साथ-साथ कम करने वाली परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा और यह निष्कर्ष

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

निकालना होगा कि क्या अपराध के बारे में कुछ असामान्य था जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मौत की सजा का आह्वान करता है । हालाँकि, इस अधिनियम को किए हुए 12 साल से अधिक समय बीत चुका है, हमारी राय है कि पहले के पैरा में चर्चा की गई तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । ”

(46) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य मोहम्मद.मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम बिहार राज्य 4 के मामले में मृत्युदंड लागू करने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों पर चर्चा की । उनके अधिपत्य भी निम्नानुसार रहे हैं:-

“23. यह सामान्य बात है कि मौत की सजा केवल ऐसे मामले में दी जा सकती है जो दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है, लेकिन इस परेशान करने वाले मुद्दे को तय करने के लिए कोई कठोर और त्वरित नियम और मापदंड नहीं है । इस न्यायालय के पास उन मामलों पर विचार करने का अवसर था जिन्हें दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम कहा जा सकता है और हालांकि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कुछ व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इस संबंध में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई कठोर और त्वरित सूत्र निर्धारित नहीं किया गया है । अपराध इतनी अलग और विशिष्ट परिस्थितियों में किए जाते हैं कि इस मुद्दे को तय करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करना असंभव है । फिर भी यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि इस प्रश्न का निर्णय लेने में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निर्णायक नहीं है ।

24*. इसके अलावा, अपराध का क्रूर और जघन्य होना ही पैमाने को मौत की सजा की ओर नहीं मोड़ता है । जब अपराध को अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण तरीके से किया जाता है ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा किया जा सके और जब समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा भयभीत हो जाए, तो उसे मौत की सजा की ओर झुकना पड़ता है । लेकिन यह अंत नहीं है । यदि ये कारक मौजूद हैं तो अदालत को यह देखना होगा कि क्या अभियुक्त समाज के लिए एक खतरा है और इसके शांतिपूर्ण और

सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए खतरा बना रहेगा। अदालत को आगे की पूछताछ करनी होगी और यह विश्वास करना होगा कि दोषी ठहराए गए आरोपी का पुनर्वास नहीं किया जा सकता है और वह आपराधिक कृत्यों को जारी रखेगा। इस तरह से परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों में मौत की सजा पर विचार करते हुए एक बैलेंस शीट तैयार की जानी चाहिए और एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जाना चाहिए। जब तक कानून में मौत की

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

सजा का प्रावधान है और जब समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा भयभीत होती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि न्यायिक शक्ति के धारक अपनी व्यक्तिगत राय को आहत नहीं करते हैं और मौत की सजा नहीं देते हैं। ये व्यापक दिशा-निर्देश हैं जो इस न्यायालय ने मृत्युदंड लगाने के लिए निर्धारित किए हैं।

4 (2011) 5 एस. सी. सी. 317

25. जब हम जो देखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले का परीक्षण करते हैं, तो हमारी राय है कि हाथ में मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी लगभग 43 वर्ष की आयु का एक परिपक्व व्यक्ति है। उन्होंने विश्वास का पद संभाला और एक सुनियोजित और पूर्व नियोजित तरीके से इसका दुरुपयोग किया। उसने लगभग 7 साल की लड़की को सुपारी खरीदने के लिए भेजा और उसके कुछ मिनट बाद अपनी शैतानी और विचित्र इच्छा को पूरा करने के लिए उस दुकान की ओर बढ़ा जहाँ उसे भेजा गया था। लड़की की उम्र लगभग 7 साल पतली और 4 फीट ऊँची थी और ऐसा बच्चा सामान्य स्थिति में वासना पैदा करने में असमर्थ था। अपीलार्थी ने बच्चे का विश्वास जीता था और वह अपीलार्थी की इच्छा को नहीं समझ पाई थी जो इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि जब उसे अपीलार्थी द्वारा ले जाया जा रहा था तो कोई विरोध नहीं किया गया था और निर्दोष बच्चे को अपीलार्थी की वासना का शिकार बनाया गया था।

26. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बच्चे के चेहरे, नाखूनों और शरीर पर विभिन्न चोटें दिखाई देती हैं। ये चोटें उस वीभत्स तरीके को दर्शाती हैं जिसमें उसके साथ बलात्कार किया गया था। अपराध का शिकार एक निर्दोष बच्चा होता है जिसने एक बहाना भी नहीं दिया, हत्या के लिए उकसाने से भी कम। एक छोटे बच्चे के प्रति ऐसी क्रूरता भयावह है। अपीलार्थी इतना नीचे गिर गया था कि निर्दोष, असहाय और रक्षाहीन बच्चे पर अपना राक्षसी स्वभाव छोड़ दिया। इस कृत्य ने निस्संदेह समुदाय के अत्यधिक आक्रोश को आमंत्रित किया था और समाज की सामूहिक अंतरात्मा को चौंका दिया था। उनकी अपेक्षाको शक्ति प्रदान करने

वाले प्राधिकरण से न्यायनिर्णयन मृत्युदण्ड देना है जो स्वाभाविक और तार्किक है। हमारी राय है कि अपीलार्थी समाज के लिए एक खतरा है और ऐसा ही बना रहेगा और उसे सुधारा नहीं जा सकता है। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है और निचली अदालत ने सही तरीके से मौत की सजा सुनाई थी जिसकी उच्च न्यायालय ने सही पुष्टि की थी।

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

(47) शत्रुघ्न चौहान और एक अन्य बनाम के मामले में

भारत संघ और अन्य 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य ने निम्नलिखित सिद्धांतों को दोहराया:-

“90. इसलिए, सुनील बत्रा मामले 38 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एकांत कारावास, भले ही मामूली रूप से शांत और संशोधित किया गया हो, जेल अधिनियम की धारा 30 द्वारा "मौत की सजा के तहत" कैदियों के लिए स्वीकृत नहीं है। धारा 30 (2) के तहत महत्वपूर्ण अभिनिर्णय यह है कि कोई व्यक्ति "मौत की सजा के तहत" नहीं है, भले ही सत्र न्यायालय ने उसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन मौत की सजा सुनाई हो। वह "मौत की सजा के तहत" नहीं है, भले ही उच्च न्यायालय पुष्टि या नए सिरे से अपीलीय दंड द्वारा, मौत की सजा लागू करता है, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील होने की संभावना है या स्थानांतरित की गई है या लंबित है। भले ही इस न्यायालय ने मृत्युदंड दिया हो, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 30 में उन्हें तब तक शामिल नहीं किया गया है जब तक कि राज्यपाल और/या संविधान द्वारा अनुमत राष्ट्रपति को दया याचिका का निपटारा नहीं किया गया है। बेशक, एक बार जब राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया जाता है, और आगे के आवेदन पर, अधिकारियों द्वारा फांसी पर कोई रोक नहीं होती है, तो व्यक्ति मौत की सजा के तहत होता है। उस अंतराल के दौरान, वह धारा 30 (2) में निर्दिष्ट अभिरक्षा अलगाव को आकर्षित करता है, जो प्रावधान को सौंपे गए सुधारात्मक अर्थ के अधीन है। "मृत्युदंड के तहत" होने का अर्थ है "अंततः निष्पादन योग्य मृत्युदंड के तहत होना"।

91. त्रिवेणीबेन 23 में भी, इस अदालत ने कहा कि एक कैदी को एकांत कारावास में रखना सुनील बत्रा 38 में दिए गए फैसले के विपरीत है और यह "अतिरिक्त और अलग" सजा देने के बराबर होगा जो कानून द्वारा अधिकृत नहीं है। यह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि

न्यायिक पक्ष पर स्थायी निर्णय के बावजूद, वास्तविक कार्यान्वयन प्रावधान वास्तविकता से बहुत दूर हैं। हम इस अवसर पर जेल अधिकारियों से सुनील बत्रा 38 में फैसले के वास्तविक इरादे को समझने और लागू करने का आग्रह करते हैं।

"5 2014 (3) एससीसी 1

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

(48) हमारा विचार है कि यह मामला अपीलार्थियों को मौत की सजा देने के लिए "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले" के दायरे में नहीं आता है। हालांकि अंतिम राय Ex.PW22/R के अनुसार, मृत्यु हिंसक है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने समाज के प्रति सामूहिक चेतना को प्रभावित किया है। युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी लेकिन इसे वीभत्स हत्या नहीं कहा जा सकता है।

(49) हालांकि, निर्णय से अलग होने से पहले, हमें अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा सूचित किया गया था कि अपीलार्थी अरुण, राजेश और दीपक को निर्णय और दिनांक 18.01.2017 & 19.01.2017 के आदेश के तुरंत बाद एकांत कारावास में भेज दिया गया था।

(50) इस विकास को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न अधिनियमों के अनुसार 'मौत की सजा पाए कैदी' शब्द का अर्थ लगाने के पूरे दायरे में जाना आवश्यक है।

कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 30 इस प्रकार है:-

“मृत्युदंड के तहत कैदी-”(1) मृत्युदंड के तहत प्रत्येक कैदी, सजा के बाद जेल में आने के तुरंत बाद, जेलर द्वारा या उसके आदेश से तलाशी ली जाएगी और उससे उन सभी वस्तुओं को लिया जाएगा जिन्हें जेलर अपने कब्जे में छोड़ना खतरनाक या अनुचित समझता है।

(2) ऐसे प्रत्येक कैदी को अन्य सभी कैदियों के अलावा एक कोठरी में रखा जाएगा और दिन और रात में एक गार्ड के प्रभार में रखा जाएगा।”

(51) धारा 59 राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने का अधिकार देती है। पंजाब राज्य ने पंजाब जेल नियमावली नामक नियम बनाए हैं। अध्याय XXIX मौत की सजा पाए कैदियों से संबंधित है। इन नियमों को हरियाणा राज्य द्वारा

अपनाया गया है।

(52) पैराग्राफ 758 में प्रावधान है कि मृत्युदंड के तहत प्रत्येक कैदी को सजा के बाद जेल में आने के तुरंत बाद, उपाधीक्षक द्वारा या उसके आदेश से तलाशी ली जाएगी, और उससे वे सभी सामान लिए जाएंगे जिन्हें उपाधीक्षक अपने कब्जे में रखना खतरनाक या अनुचित समझता है। कैदी को अन्य सभी कैदियों के अलावा एक कोठरी में रखा जाना है, और उसे दिन में और रात में एक गार्ड के प्रभार में रखा जाना है।

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

(53) पैराग्राफ 759 में प्रावधान है कि प्रत्येक कोठरी जिसमें मौत की सजा पाए दोषी को, ऐसे दोषी को रखे जाने से पहले, उपाधीक्षक या नियुक्त अन्य अधिकारी द्वारा जाँच की जानी है।

(54) पैराग्राफ 760 में प्रावधान है कि निष्पादन के लिए निर्धारित तिथि, वह अवधि जिसके भीतर याचिका भेजी जानी चाहिए और मामले में याचिका का परिणाम, उप अधीक्षक द्वारा दोषी कैदी को सूचित किया जाना है।

(55) पैराग्राफ 761 में प्रावधान किया गया है कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक एक अच्छी रोशनी हर कोठरी के कटे हुए दरवाजे के सामने जलती रहती है जिसमें एक दोषी कैदी को कैद किया जाता है ताकि वह हर समय निगरानी में रहे।

(56) पैराग्राफ 764 में सुरक्षा के लिए आवश्यक वार्डरों की संख्या का प्रावधान है।

(57) पैराग्राफ 767 में प्रावधान है कि दोषी कैदी को (जब तक कि उसके खिलाफ कोई विशेष कारण न हो, जो कारण अधीक्षक द्वारा अपनी पत्रिका में दर्ज किए जाने चाहिए), प्रत्येक सुबह और शाम को आधे घंटे के लिए अपनी कोठरी के प्रांगण में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन एक बार में केवल एक ऐसे कैदी को ही ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(58) पैराग्राफ 769 में प्रावधान है कि दोषी कैदी की दिन में दो बार तलाशी ली जानी है।

(59) पैराग्राफ 770 आहार और सावधानी बरतने का प्रावधान करता है।

(60) पैराग्राफ 771 के अनुसार दोषी कैदी को किताबों और तंबाकू का उपयोग करने की अनुमति है।

(61) कुछ अपवाद हैं जो महिला दोषियों के लिए बनाए गए हैं। जेल के अधिकृत आगंतुकों के

अलावा कोई भी व्यक्ति अधीक्षक से लिखित आदेश के बिना या उनके साथ कैदी के साथ संवाद नहीं कर सकता है।

(62) पैराग्राफ 782 निष्पादन के समय वार्डर गार्ड और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल प्रदान करता है। अधीक्षक केवल निष्पादन के लिए जिम्मेदार होता है।

(63) दोषी कैदी के वयस्क पुरुष रिश्तेदारों और अधिकतम 12 तक के सम्मानित पुरुष वयस्कों को महानिरीक्षक की मंजूरी के तहत जेल के अंदर या फांसी के घेरे में फांसी देखने

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

के लिए भर्ती किया जा सकता है, बशर्ते कि महानिरीक्षक, अपने विवेक से, पैराग्राफ 786 के अनुसार पूरी तरह से या किसी विशेष व्यक्ति को प्रवेश देने से इनकार कर सकता है।

(64) पैराग्राफ 784 में प्रावधान है कि फांसी नवंबर से फरवरी के महीनों में सुबह 8 बजे और मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर में सुबह 7 बजे और मई से अगस्त के महीनों में सुबह 6 बजे दी जाएगी। अधीक्षक और उपाधीक्षक फांसी से कुछ मिनट पहले दोषी कैदी से उसकी कोठरी में मिलेंगे। अधीक्षक को वारंट में नामित कैदी की पहचान करने और कैदी को स्थानीय भाषा में वारंट का अनुवाद पढ़ने की आवश्यकता होती है।

(65) भारतीय दंड संहिता की धारा 73 और 74 निम्नानुसार हैं:- “73-एकान्त कारावास-जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसके लिए इस संहिता के तहत न्यायालय को उसे कठोर कारावास की सजा देने की शक्ति है, तो न्यायालय अपनी सजा के माध्यम से आदेश दे सकता है कि अपराधी को निम्नलिखित पैमाने के अनुसार कारावास के किसी भी हिस्से या भाग के लिए एकांत कारावास में रखा जाएगा, जिसमें उसे पूरी तरह से तीन महीने से अधिक की सजा नहीं दी गई है, अर्थात्-एक महीने से अधिक का समय नहीं अगर कारावास की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी; दो महीने से अधिक का समय अगर कारावास की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी और एक साल से अधिक नहीं होगी; तीन महीने से अधिक का समय अगर कारावास की अवधि एक साल से अधिक नहीं होगी।

74. एकान्त कारावास की सीमा-एकान्त कारावास की सजा को निष्पादित करने में, ऐसा कारावास किसी भी मामले में एक समय में चौदह दिनों से अधिक नहीं होगा, जिसमें ऐसी अवधि से कम अवधि के एकांत कारावास की अवधि के बीच का अंतराल नहीं होगा और जब दिया गया कारावास तीन महीने से अधिक होगा, तो एकान्त कारावास दिए गए पूरे कारावास

के किसी भी एक महीने में सात दिनों से अधिक नहीं होगा, जिसमें ऐसी अवधि से कम अवधि के एकांत कारावास की अवधि के बीच का अंतराल नहीं होगा।”

(66) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 में प्रावधान है कि जब सत्र न्यायालय/sessions court मौत की सजा सुनाता है, तो कार्यवाही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, और सजा तब तक निष्पादित नहीं की जाएगी जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। सजा सुनाने वाला न्यायालय दोषी व्यक्ति को वारंट के तहत जेल हिरासत में देगा।

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

(67) धारा 368 सजा की पुष्टि करने या दोषसिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है।

(68) धारा 371 में प्रावधान है कि सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए मामलों में, उच्च न्यायालय का उचित अधिकारी, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश दिए जाने के बाद, बिना किसी देरी के, उच्च न्यायालय की मुहर के तहत आदेश की एक प्रति भेजेगा और अपने अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सत्र न्यायालय को भेजेगा।

(69) धारा 413 में यह प्रावधान है कि जब मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए किसी मामले में, सत्र न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय का पुष्टिकरण या आदेश प्राप्त होता है, तो वह वारंट जारी करके या ऐसे अन्य कदम उठाकर, जो आवश्यक हों, ऐसे आदेश को प्रभावी बनाएगा।

(70) धारा 415 उच्चतम न्यायालय में अपील के मामले में मौत की सजा के निष्पादन को स्थगित करने से संबंधित है।

(71) भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने का अधिकार देता है।

(72) अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने का अधिकार देता है।

(73) पंजाब जेल नियमावली के पैराग्राफ से यह स्पष्ट है कि मौत की सजा पाए प्रत्येक कैदी को अन्य सभी कैदियों के अलावा एक कोठरी में रखा जाना है और उसे दिन और रात में एक विशेष गार्ड के प्रभार में रखा जाना है। अधीक्षक के अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति

उसके साथ संवाद नहीं कर सकता है। मौत की सजा पाए कैदी को हर सुबह और शाम केवल आधे घंटे के लिए अपनी कोठरी के कोर्ट यार्ड में रहने की अनुमति है। सूर्यास्त से सूर्योदय तक रोशनी जलती रहती है ताकि कैदी हर समय निगरानी में रहे, हालांकि उसे रिश्तेदारों, दोस्तों, कानूनी सलाहकारों और अनुमोदित धार्मिक मंत्रियों के साथ साक्षात्कार के मामले में उचित संलिप्तता की अनुमति है।

(74) वाशिंगटन यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी द्वारा प्रकाशित लेखक स्टुअर्ट ग्रासियन के एक लेख "साइकियाट्रिक इफेक्ट्स ऑफ सोलिटरी कॉन्फिनमेंट" में, लेखक

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

ने एकांत कारावास के पूरे सरगम और दोषियों को इसके वैज्ञानिक नुकसान को निम्नानुसार बताया है:

एकान्त कारावास-अर्थात् न्यूनतम पर्यावरणीय उत्तेजना और सामाजिक संपर्क के लिए न्यूनतम अवसर के साथ दिन के सभी, या लगभग सभी के लिए एक कोठरी में अकेले एक कैदी का कारावास-गंभीर मनोरोग संबंधी नुकसान का कारण बन सकता है। यह वास्तव में लंबे समय से ज्ञात है कि पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तेजना के गंभीर प्रतिबंध का मानसिक कार्यप्रणाली पर गहरा हानिकारक प्रभाव पड़ता है; यह मुद्दा रोगियों के कई समूहों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है, उदाहरण के लिए, गहन देखभाल इकाइयों में रोगी, लंबे समय तक कर्षण की आवश्यकता से स्थिर रीढ़ के रोगी, और अपने संवेदी उपकरण की हानि वाले रोगी (जैसे आंख-पैच या श्रवण-बाधित रोगी)। यह मुद्दा सैन्य स्थितियों, ध्रुवीय और पनडुब्बी अभियानों और अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में आपराधिक व्यवहार से निपटने के साधन के रूप में लंबे समय तक कारावास और एकांत कारावास की शुरुआत करने में विश्व में अग्रणी था। "कारागार प्रणाली" संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार फिलाडेल्फिया में, उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुई, सामाजिक रूप से विचलित व्यवहार वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की संभावना के बारे में महान सामाजिक आशावाद की भावना का एक उत्पाद है। अमेरिकियों को अपनी "जेल प्रणाली" पर काफी गर्व था और उन्होंने विदेशों से महत्वपूर्ण आगंतुकों को उन्हें देखने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित किया।

3 यह प्रणाली, जिसे मूल रूप से "फिलाडेल्फिया प्रणाली" के रूप में लेबल किया गया था, में कारावास के साधन के रूप में एकान्त कारावास पर लगभग एक विशेष निर्भरता

शामिल थी और कई यूरोपीय जेल प्रणालियों में, जो अमेरिकी मॉडल का अनुकरण करती थी, दोषसिद्धि के बाद और मुकदमे से पहले के बंदियों के लिए भी कारावास का प्रमुख तरीका बन गया।

4 वास्तव में परिणाम विनाशकारी थे। इस तरह से हिरासत में लिए गए कैदियों के बीच मानसिक गड़बड़ी की घटनाएँ और इस तरह की गड़बड़ी की गंभीरता इतनी अधिक थी कि व्यवस्था नापसंद हो गई और अंततः इसे छोड़ दिया गया। इस प्रक्रिया के दौरान नैदानिक साहित्य का एक प्रमुख निकाय विकसित हुआ जिसने कारावास की ऐसी कठोर स्थितियों से उत्पन्न मनोरोग संबंधी गड़बड़ी का दस्तावेजीकरण किया।

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

5 प्रतिमानात्मक मनोरोग संबंधी गड़बड़ी एक उत्तेजित भ्रमित करने वाली स्थिति थी, जो अधिक गंभीर मामलों में थी।

एक फ्लोरीड प्रलाप की विशेषताएँ, जो गंभीर भ्रमित, व्यामोहपूर्ण और मतिभ्रमपूर्ण विशेषताओं की विशेषता है, और तीव्र आंदोलन और यादृच्छिक, आवेगपूर्ण, अक्सर आत्म-निर्देशित हिंसा द्वारा भी। इस तरह की गड़बड़ी अक्सर बीमारी होती थी। इसके अलावा, एकांत कारावास के परिणामस्वरूप अक्सर पहले से मौजूद मानसिक स्थिति में गंभीर वृद्धि होती है। यहां तक कि उन कैदियों में भी जो एकांत कारावास के परिणामस्वरूप मानसिक बीमारी विकसित नहीं करते थे, इस तरह के कारावास ने लगभग अनिवार्य रूप से अलग-थलग कारावास की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक दर्द को लागू किया और अक्सर व्यापक जेल वातावरण के लिए सफलतापूर्वक अनुकूलन करने की कैदी की क्षमता को काफी बाधित कर दिया। यह दुखद और अत्यधिक परेशान करने वाला दोनों है कि एकान्त कारावास के साथ उन्नीसवीं शताब्दी के अनुभव के सबक को आज जेल में आवास और मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि, वास्तव में, एकान्त कारावास के कारण होने वाला मनोरोग संबंधी नुकसान एक सौ साल पहले बहुत स्पष्ट हो गया था। वास्तव में, 1890 तक, इन री मेडले के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एकांत कारावास के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर मनोरोग संबंधी नुकसान को मान्यता दी: यह एकान्त कारावास का मामला नहीं है।कैदी की सुरक्षा के बारे में केवल एक महत्वहीन विनियमन। [ई] अनुभव [एकांत कारावास की कारागार प्रणाली के साथ] ने प्रदर्शित किया कि इसके लिए गंभीर आपत्तियां थीं। एक छोटी सी कैद के बाद भी, काफी संख्या में कैदी एक अर्ध-घातक स्थिति में गिर गए, जिससे उन्हें जगाना असंभव था, और

अन्य हिंसक रूप से पागल हो गए; अन्य, फिर भी, आत्महत्या कर ली; जबकि जो लोग अग्निपरीक्षा को बेहतर तरीके से सहन करते थे, उनमें आम तौर पर सुधार नहीं किया गया था, और ज्यादातर मामलों में समुदाय की किसी भी बाद की सेवा के लिए पर्याप्त मानसिक गतिविधि ठीक नहीं हुई थी। 7 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम श्री मेडले के लिए काफी नाटकीय थे। श्री मेडले को अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। हत्या के समय लागू कोलोराडो क़ानून के तहत उसे काउंटी जेल में लगभग एक अतिरिक्त महीने की कैद के बाद फांसी दी गई होगी। लेकिन श्री मेडले के अपराध और उनके मुकदमे के बीच के अंतराल में कोलोराडो विधायिका ने एक नया क़ानून पारित किया था जिसमें दोषी

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

हत्यारे को जेल में डालने के बजाय जेल में डालने का आह्वान किया गया था। उसकी फांसी से पहले के महीने के दौरान राज्य की जेल में एकांत कारावास में। 8 दुर्भाग्य से, जब विधायिका ने नया कानून पारित किया तो उसने एक बिरजिंग क्लॉज की अनुमति दिए बिना पुराने कानून को रद्द कर दिया, जो पुराने क़ानून के तहत श्री मेडले को सजा देने की अनुमति देता। 9 श्री मेडले ने नए कानून के तहत अपनी सजा की अपील करते हुए तर्क दिया कि इस नए कानून के तहत सजा पुराने कानून के तहत सजा की तुलना में इतनी अधिक बोझिल थी कि उसे पूर्व कार्योत्तर रूप से लागू किया जा सके। 10 सर्वोच्च न्यायालय उनसे सहमत था, भले ही उसने साथ ही यह स्वीकार किया कि यदि श्री मेडले को नए कानून के तहत सजा नहीं दी गई थी, तो उन्हें बिल्कुल भी सजा नहीं दी जा सकती थी। 11 इसके बावजूद, अदालत ने माना कि एक महीने के एकांत कारावास की इस अतिरिक्त सजा को नजरअंदाज करना बहुत गंभीर था; अदालत ने श्री मेडले को एक स्वतंत्र व्यक्ति घोषित कर दिया, और उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया। 12 एकान्त कारावास के गहन मनोरोग प्रभावों के बारे में नाटकीय चिंताएँ बीसवीं शताब्दी तक चिकित्सा साहित्य और समाचार दोनों में जारी रही हैं। सोवियत संघ और कम्युनिस्ट चीन के राजनीतिक कैदियों-और विशेष रूप से कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिकी युद्ध कैदियों के "मस्तिष्क धुलाई" के बारे में उठाए गए खतरे ने संवेदी अभाव और सामाजिक अलगाव के प्रभावों के बारे में चिकित्सा और वैज्ञानिक साहित्य के एक प्रमुख निकाय को जन्म दिया, और सामाजिक अलगाव जिसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल था। 13 इस साहित्य के साथ-साथ मेरी अपनी टिप्पणियों ने प्रदर्शित किया है कि पर्यावरण और सामाजिक उत्तेजना के पर्याप्त स्तर से वंचित व्यक्ति जल्द ही पर्यावरण के प्रति पर्याप्त सतर्कता और ध्यान बनाए रखने में असमर्थ हो जाएंगे। वास्तव में, यहाँ तक कि कुछ दिनों के

एकांत कारावास भी अनुमानित रूप से इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम (ई. ई. जी.) पैटर्न को मूर्छा और प्रलाप की एक असामान्य पैटर्न विशेषता की ओर बदल देगा। यह तथ्य आश्चर्यजनक नहीं है। अधिकांश व्यक्तियों ने एक समय या किसी अन्य समय, कम से कम संक्षिप्त रूप से, तीव्र एकरसता और अपर्याप्त पर्यावरणीय उत्तेजना के प्रभावों का अनुभव किया है। ऐसी स्थिति में अपेक्षाकृत कम समय के बाद भी एक व्यक्ति के मानसिक आघात या "कोहरे" में उतरने की संभावना होती है, जिसमें सतर्कता, ध्यान और एकाग्रता सभी बाधित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, एक समय के बाद, व्यक्ति को संसाधित करने में तेजी से असमर्थ हो जाता है। उत्तेजना, और अक्सर इस तरह की उत्तेजना के लिए "अति प्रतिक्रियाशील" हो जाता है। उदाहरण के लिए, अचानक शोर या एक हल्के जार का चमकना व्यक्ति को उसकी

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

मूर्छा से बाहर निकाल देता है और अत्यधिक अप्रिय हो जाता है। समय के साथ उत्तेजना की अनुपस्थिति के कारण जो भी उत्तेजना उपलब्ध होती है वह हानिकारक और चिड़चिड़ी हो जाती है। इस तरह की मूर्छा में व्यक्ति किसी भी उत्तेजना से बचते हैं, और धीरे-धीरे खुद में और अपने स्वयं के मानसिक कोहरे में वापस चले जाते हैं। पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया की पर्याप्त स्थिति के लिए एक ध्यान सेट को प्राप्त करने और बनाए रखने की क्षमता और ध्यान बदलने की क्षमता दोनों की आवश्यकता होती है। एकान्त कारावास में सतर्कता और एकाग्रता में कमी दो संबंधित असामान्यताओं की ओर ले जाती है: ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, और ध्यान बदलने में असमर्थता। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता (ध्यान प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए) को एक प्रकार की विघटनकारी मूर्छा के रूप में अनुभव किया जाता है—एक मानसिक "कोहरा" जिसमें व्यक्ति ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है, और उदाहरण के लिए, जब वह पढ़ने या सोचने का प्रयास करता है तो उसे समझ या याद नहीं कर सकता है। ध्यान बदलने में असमर्थता के परिणामस्वरूप एक प्रकार की "सुरंग दृष्टि" होती है जिसमें व्यक्ति का ध्यान अटक जाता है, लगभग हमेशा किसी अत्यधिक अप्रिय चीज़ पर, और जिसमें वह उस मामले के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता है; इसके बजाय, वह उस पर जुनूनी रूप से केंद्रित हो जाता है। ये जुनूनी व्यस्तताएँ विशेष रूप से परेशान करने वाली हैं। एकान्त कारावास में व्यक्ति आसानी से किसी विचार में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ को मामूली या जलन महसूस होती है, किसी पड़ोसी कोशिका से आने वाली कोई आवाज़ या गंध, या, शायद सबसे अधिक, किसी शारीरिक संवेदना से। इससे प्रताड़ित होकर ऐसे लोग इस पर ध्यान देना बंद नहीं कर पाते हैं। एकान्त कारावास में साधारण उत्तेजनाएँ अत्यधिक अप्रिय हो जाती हैं और छोटी-छोटी जलनें

भयावह हो जाती हैं। इस तरह के कारावास में रहने वाले व्यक्ति सामान्य रूप से महत्वहीन उत्तेजनाओं और छोटी-मोटी चिड़चिड़ाहटों के कारण बढ़ते आंदोलन और व्यामोह का केंद्र बन जाते हैं। मैंने एकांत कारावास में अनगिनत व्यक्तियों की जांच की है जो कुछ मामूली, लगभग अदृश्य शारीरिक संवेदना में जुनूनी रूप से व्यस्त हो गए हैं, एक ऐसी संवेदना जो समय के साथ चिंता में बदल जाती है, और अंत में एक सर्व-उपभोग, जीवन-धमकी वाली बीमारी में बदल जाती है। इस तरह के पर्यावरणीय प्रतिबंधों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को दिन की सतर्कता और रात की नींद के सामान्य पैटर्न को बनाए रखना मुश्किल लगता है। वे अक्सर खुद को अपने बिस्तर का विरोध करने में असमर्थ पाते हैं दिन के दौरान-अपनी मूर्छा के लकवाग्रस्त प्रभाव का विरोध करने में असमर्थ-और फिर भी रात में किसी भी आरामदायक नींद में असमर्थ। सार्थक गतिविधि की कमी कृत्रिम प्रकाश के निरंतर संपर्क

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

और प्राकृतिक दिन के उजाले का अनुभव करने के कम अवसर के प्रभाव से और बढ़ जाती है। और एक सामान्य दिन-रात की नींद के चक्र को बनाए रखने में व्यक्ति की कठिनाई अक्सर रात के समय अंधेरे और शांत पर लगातार घुसपैठ से बदतर हो जाती है, जैसे कि स्टील के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनके चेहरे पर फ्लैशलाइट चमकती है, और इसी तरह। अलग-अलग व्यक्तियों पर एकांत कारावास के प्रभावों में पर्याप्त अंतर हैं। जो लोग सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं, वे अक्सर सूक्ष्म तंत्रिका संबंधी या ध्यान की कमी विकार के साक्ष्य वाले या किसी अन्य भेद्यता वाले व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति फ्लोरीड साइकोटिक प्रलाप की स्थितियों से पीड़ित होते हैं, जो गंभीर मतिभ्रम, भटकाव और यहां तक कि असंगतता और तीव्र आंदोलन और व्यामोह से चिह्नित होते हैं। इन मनोवैज्ञानिक विक्षोभों में अक्सर एक असंबद्ध चरित्र होता है, और इस तरह से प्रभावित व्यक्ति अक्सर भ्रमित मनोविकृति के दौरान हुई घटनाओं को याद नहीं करते हैं। आम तौर पर, अधिक स्थिर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति और अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति और व्यवहार को संशोधित करने की अधिक क्षमता वाले व्यक्ति और मजबूत संज्ञानात्मक कार्यशीलता वाले व्यक्ति कम गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। हालांकि, इन सभी व्यक्तियों को अभी भी कुछ हद तक मूर्खता, सोचने और एकाग्रता में कठिनाइयाँ, जुनूनी सोच, आंदोलन, चिड़चिड़ापन और बाहरी उत्तेजनाओं (विशेष रूप से हानिकारक उत्तेजनाओं) को सहन करने में कठिनाई का अनुभव होगा। इसके अलावा, हालांकि इन कैदियों द्वारा पीड़ित कई तीव्र लक्षण एकांत कारावास की समाप्ति पर कम होने की संभावना है, कई-जिनमें कुछ ऐसे भी शामिल हैं जो एकांत में कारावास के दौरान खुले तौर पर मानसिक रूप से बीमार नहीं हुए थे-इस तरह के

कारावास के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से नुकसान होगा। यह नुकसान आम तौर पर सामाजिक संपर्क की निरंतर असहिष्णुता से प्रकट होता है, एक बाधा जो अक्सर कैदी को जेल में सामान्य आबादी के व्यापक सामाजिक वातावरण में सफलतापूर्वक पुनः समायोजित करने से रोकती है और शायद अधिक महत्वपूर्ण रूप से, अक्सर कैद से रिहा होने पर व्यापक समुदाय में फिर से एकीकृत होने की कैदी की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करती है। ऐसी कठोर परिस्थितियों में रखे गए कई कैदी इस तरह के कारावास के परिणामस्वरूप वे बेहद मनोवैज्ञानिक नुकसान या तनाव का सामना कर रहे हैं, उसे स्वीकार करने से डरते हैं। एकान्त कारावास में कैदियों की यह अनिच्छा इस धारणा की प्रतिक्रिया है कि इस तरह का कारावास अधिकारियों द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से "उन्हें तोड़ने" का एक स्पष्ट प्रयास है, और मेरे अनुभव में, अधिक गंभीर हो जाता है जब कैदी अपने कारावास की कठोरता का अनुभव करता है जो स्वाभाविक रूप से उचित प्रतिक्रिया के उचित परिणाम के बजाय शक्ति

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

के मनमाने प्रयोग का परिणाम है। इसके अलावा, एकांत कारावास में, मानसिक स्वास्थ्य जांच साक्षात्कार अक्सर एक निजी सेटिंग के बजाय सेल फ्रंट पर आयोजित किए जाते हैं, और कैदी आम तौर पर इस तरह के साक्षात्कार के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक संकट का खुलासा करने के लिए काफी अनिच्छुक होते हैं क्योंकि इस तरह की बातचीत अनिवार्य रूप से आसपास की कोठरी में अन्य कैदियों द्वारा सुनी जाती है, जिससे उन्हें अपने साथी कैदियों के सामने संभावित कलंक और अपमान का सामना करना पड़ता है।

D. संवेदी प्रतिबंध और एकान्त कारावास के प्रति प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक

इस क्षेत्र में बाद के अधिकांश शोधों ने चरों को चित्रित करने का प्रयास किया जो इन भिन्न परिणामों की व्याख्या कर सकते हैं। इन चरों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: i) अवधारणात्मक अभाव की विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर, और ii) ऐसी स्थितियों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों के बीच पहले से मौजूद व्यक्तित्व के कार्य में अंतर।

1. अलगाव की अलग-अलग स्थितियाँ

शोध में आमतौर पर उद्धृत किए गए कारकों में से एक संवेदी अभाव की तीव्रता और अवधि थी। अधिक गंभीर संवेदी प्रतिबंध, हानिकारक उत्तेजना की उपस्थिति, और संवेदी अभाव अनुभव की लंबी अवधि सभी प्रतिकूल मनोरोग परिणामों के बढ़ते जोखिम से जुड़े हुए हैं।

मेरे अनुभव में, विभिन्न जेल एकांत कारावास सेटिंग्स में कैदियों द्वारा अनुभव की जाने वाली स्थितियों में आम तौर पर कुछ समानताएं होती हैं (लगभग पचास से अस्सी वर्ग फुट की एक कोठरी; कोठरी में बंद लगभग बाईस और डेढ़ घंटे प्रति दिन; यार्ड व्यायाम का लगभग एक घंटा प्रति दिन, प्रत्येक सप्ताह सात दिनों में से पांच), अन्य मामलों में स्थितियां काफी भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ कोशिकाओं में बंद दरवाजे होते हैं, जो जालीदार स्टील के दरवाजों की तुलना में बेहतर वेंटिलेशन, ध्वनि संचरण और बाहरी वातावरण के साथ दृश्य संबंध की अनुमति देते हैं; ठोस स्टील के दरवाजे सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक होते हैं-विशेष रूप से जब वे या तो टिका होते हैं या दीवार से लगभग कोई वायु अंतराल के साथ बंद हो जाते हैं। इसके अलावा, यात्रा की मात्रा और परिस्थितियों, पठन सामग्री और टेलीविजन की उपलब्धता आदि के संबंध में प्रशासनिक शर्तें ऐसे सभी कारक हैं जो संस्थान से संस्थान में और यहां तक कि किसी दिए गए संस्थान के भीतर भी समय-समय

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

पर भिन्न होते हैं।

2. अलगाव अनुभव का अनुमानित उद्देश्य

ऊपर वर्णित कारकों के अलावा, अलगाव के प्रभाव को निर्धारित करने में एक और महत्वपूर्ण कारक अलगाव का कथित इरादा प्रतीत होता है। प्रयोगात्मक शोध ने प्रदर्शित किया है कि एक व्यक्ति जो संकेत प्राप्त करता है जो उसे अलगाव की स्थिति का अनुभव करने के लिए संभावित रूप से खतरनाक बनाता है, अलगाव के अनुभव के लिए प्रतिकूल मनोरोग प्रतिक्रियाओं को विकसित करने की अधिक संभावना है। इसके विपरीत, यदि विषय के पास यह मानने का कारण है कि स्थिति सौम्य होने की संभावना है तो वह इसे सहन करने या इसका आनंद लेने की अधिक संभावना रखेगा। अलगाव को अच्छी तरह से सहन करने वाले विषयों के बाद के समूह में, कई ने सुखद या कम से कम गैर-खतरनाक दृश्य कल्पना, कल्पना और मतिभ्रमपूर्ण अनुभवों की सूचना दी। “उसका मन भटकना शुरू कर सकता है, दिवास्वप्नों में संलग्न हो सकता है, अपने परिचर जीवंत सचित्र छवियों के साथ सम्मोहक श्रद्धा में फिसल सकता है। ..हो सकता है कि वह चुपचाप यौन या अन्य सुखद विचार रख रहा हो।”

यह निष्कर्ष शायद आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि संवेदी प्रतिबंध अवधारणात्मक गड़बड़ी और भ्रम पैदा करते हैं जो मतिभ्रम पैदा करने वाली दवाओं द्वारा उत्पादित लोगों के समान हैं, और स्पष्ट रूप से, जबकि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में

कहा जा सकता है कि उन्होंने इस तरह के मतिभ्रम, मनोविकृत जैसे अनुभवों से गुजरने के लिए स्वेच्छा से काम किया है, लेकिन मतिभ्रम पैदा करने वाली दवाओं द्वारा प्रेरित अनुभव के समान अनुभव से गुजरने के लिए मजबूर होना लगभग समान रूप से भयानक होना चाहिए।

3. प्रतिक्रिया में व्यक्तिगत अंतर

कई अध्ययनों से पता चला है कि व्यक्तियों के बीच उनकी क्षमता के संबंध में बहुत भिन्नता है। वे संवेदी प्रतिबंध की दी गई स्थिति को सहन करें। यह परिवर्तनशीलता ऐसी अलगाव स्थितियों के विषाक्त प्रभाव की प्रकृति में आगे की अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद करती है, और इस तथ्य की आश्चर्यजनक पुष्टि प्रदान करती है कि पर्यावरणीय उत्तेजना का इस तरह का अभाव, विशेष रूप से जब लंबी अवधि का होता है, मस्तिष्क के कामकाज के लिए विषाक्त होता है और मूर्छा और प्रलाप के लक्षणों का कारण बनता है। आम तौर पर,

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

परिपक्व, स्वस्थ व्यक्तित्व वाले और कम से कम औसत बुद्धि वाले व्यक्ति इस तरह की अलगाव स्थितियों के प्रतिगामी खिंचाव और अवधारणात्मक घुसपैठ को सहन करने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर, आदिम या मनोरोगी कार्यप्रणाली या सीमा रेखा संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले व्यक्ति, आवेगग्रस्त व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति जिनका आंतरिक भावनात्मक जीवन अराजक या भयभीत है, विशेष रूप से इस तरह के अलगाव के लिए गंभीर मनोरोगी प्रतिक्रियाओं के लिए जोखिम में हैं। इसके अलावा, इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि, प्रतिबंधित पर्यावरणीय उत्तेजना की स्थिति में, पहले से मौजूद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शिथिलता प्रतिकूल मनोरोग प्रतिक्रियाओं और अत्यधिक प्रलाप के विकास के लिए एक प्रमुख पूर्वनिर्धारित कारक है। उदाहरण के लिए, नेत्र शल्य चिकित्सा (नेत्र-पैच वाले रोगियों) के बाद दृश्य अभाव से पीड़ित रोगियों के एक अध्ययन में, पहले से मौजूद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शिथिलता वाले रोगियों में प्रलाप/दिमाकी अश्लिषा के लक्षण विकसित होने का विशेष रूप से उच्च जोखिम पाया गया। इसके अलावा, पहले से मौजूद व्यक्तित्व विकार या मनोसामाजिक कार्यप्रणाली में कमी की उपस्थिति कर्मचारियों के प्रति असमर्थ भय, व्यामोह, आंदोलन और तर्कहीन आक्रामकता के बढ़ते जोखिम से जुड़ी थी। इसके अलावा, व्यक्ति कभी-कभी ऐसी स्थितियों के संपर्क में आ सकते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कामकाज में हानि का कारण बनती हैं। ऐसी स्थितियाँ-विशेष रूप से यदि वे व्यक्ति की सतर्कता की स्थिति को खराब करती हैं (उदाहरण के लिए, नींद की कमी, असामान्य

नींद-जागने के चक्र, या शामक दवा का उपयोग) प्रलाप/दिमाकी अशिलिथा के विकास के लिए व्यक्ति की भेद्यता को काफी बढ़ा देगी। शल्य चिकित्सा के बाद के रोगियों के बीच प्रलाप और तथाकथित "आई. सी. यू. मनोविकृति" इस घटना के उदाहरण हैं। एकान्त कारावास में कैदियों द्वारा अनुभव की जाने वाली विशिष्ट कठिनाइयों में से एक असामान्य नींद जागने का चक्र और खराब नींद है।

III. निष्कर्ष 44

एकांत में कारावास से जुड़े पर्यावरणीय उत्तेजना और सामाजिक अलगाव का प्रतिबंध मानसिक कार्यप्रणाली के लिए आश्चर्यजनक रूप से विषाक्त है, जो अवधारणात्मक और संज्ञानात्मक हानि और भावात्मक गड़बड़ी से जुड़ी एक मूर्खतापूर्ण स्थिति पैदा करता है। अधिक गंभीर मामलों में, इतने सीमित कैदियों में फ्लोराइड प्रलाप विकसित हो गया है-तीव्र आंदोलन, भय और अव्यवस्था के साथ एक भ्रमित मनोविकृति। लेकिन वे कैदी भी जो

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक लचीला हैं, अनिवार्य रूप से इस तरह के कारावास के परिणामस्वरूप गंभीर मनोवैज्ञानिक दर्द का सामना करते हैं, विशेष रूप से जब कारावास लंबा होता है, और विशेष रूप से जब व्यक्ति इस कारावास को शक्ति और धमकी के मनमाने अभ्यास के उत्पाद के रूप में अनुभव करता है। इसके अलावा, इस तरह के कारावास के कारण होने वाले नुकसान के परिणामस्वरूप लंबे समय तक या स्थायी मनोरोग संबंधी अक्षमता हो सकती है, जिसमें विकार भी शामिल हैं जो जेल से रिहा होने पर कैदी की व्यापक समुदाय में फिर से शामिल होने की क्षमता को गंभीर रूप से कम कर सकते हैं।

लंबे समय तक एकांत कारावास में रखे गए कई कैदी निस्संदेह समुदाय के लिए एक खतरा हैं और उनकी हिरासत में रखे गए सुधार अधिकारियों के लिए एक खतरा हैं। लेकिन कई लोगों के लिए वे एक खतरा इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे बहुत निर्दयी हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे अस्थिर, आवेग-ग्रस्त और आंतरिक रूप से अव्यवस्थित हैं।

जैसा कि इस कथन में पहले उल्लेख किया गया है, आधुनिक समाजों ने सामाजिक रूप से विचलित व्यवहार के बीच एक मौलिक नैतिक विभाजन किया जिसे बुरे इरादे के उत्पाद के रूप में देखा जाता था, और ऐसा व्यवहार जिसे बीमारी के उत्पाद के रूप में देखा जाता था। फिर भी यह विभाजन कभी भी उतना सरल नहीं रहा जितना पहली नज़र में लगता है। सामाजिक रूप से विचलित व्यवहार को वास्तव में इरादे के एक स्पेक्ट्रम के साथ वर्णित किया जा सकता है। एक छोर पर वे हैं जिनका व्यवहार पूरी तरह से "सहायक" है-निर्दयी,

सावधानीपूर्वक नियोजित और तर्कसंगत; दूसरे पर वे व्यक्ति हैं जिनका सामाजिक रूप से विचलित व्यवहार अनियंत्रित भावनात्मक आवेग, आंतरिक अराजकता और अक्सर मनोरोग या तंत्रिका संबंधी बीमारी का परिणाम है।

यह एक बड़ी विडंबना है कि जब कोई व्यक्ति कारावास के स्तर से गुजरता है-न्यूनतम से मध्यम से अधिकतम सुरक्षा संस्थानों तक, और फिर इन संस्थानों के एकांत कारावास खंड तक-कोई भी सबसे बेरहमी से गणना करने वाले अपराधियों की उप-आबादी में गहराई से और गहराई से गुजरें। इसके बजाय, विडंबनापूर्ण और दुखद रूप से, व्यक्ति उन लोगों के पास वापस आता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं और अक्सर गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार होते हैं। जिन कानूनों और प्रथाओं ने इस त्रासदी को स्थापित किया है और इसे कायम रखा है, वे सामान्य मानव शालीनता की किसी भी भावना को गहराई से आहत करते हैं।

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

एपेन्डिक्स बी:

सोवियत संघ के साथ नौवीं शताब्दी का जर्मन अनुभव 1854 और 1909 के बीच कैदियों के बीच मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी के विषय पर जर्मन चिकित्सा साहित्य में सैंतीस लेख प्रकाशित हुए, जिसमें वर्षों के काम और कई सैकड़ों मामलों का सारांश था। इस साहित्य की एक प्रमुख समीक्षा 1912 में प्रकाशित हुई थी। इन मनोवैज्ञानिक बीमारियों के एटियोलॉजी में पहचाना जाने वाला एकल सबसे महत्वपूर्ण कारक एकांत कारावास था। वास्तव में, जेल मनोरोग के विषय पर पहली रिपोर्ट हाले में जेल के मुख्य चिकित्सक डेलब्रुक की थी, जिसमें मानसिक गड़बड़ी की आवृत्ति अंत में इतनी अधिक थी कि इसने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। डेलब्रुक की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि लंबे समय तक पूर्ण अलगाव का शरीर और दिमाग पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है और ऐसा लगता है कि यह कैदियों को मतिभ्रम के लिए पूर्वनिर्धारित करता है और एकांत कारावास को तत्काल समाप्त करने की सलाह देता है। 1863 में गुत्श ने एकान्त कारावास से उपजे मनोविकृति के 84 मामलों की सूचना दी और स्पष्ट मतिभ्रम और उत्पीड़न संबंधी भ्रम, आशंका, मनोप्रेरक उत्तेजना, सिंड्रोम की अचानक शुरुआत और एकान्त कारावास की समाप्ति पर तेजी से सुधार का वर्णन किया। इनमें से कई व्यक्तियों में "आत्मघाती और उन्मादी प्रकोप" विकसित हुए।" 1871 में, तीव्र प्रतिक्रियाशील मनोविकृति के पंद्रह

मामलों पर एक रिपोर्ट में, जिनमें से कुछ स्पष्ट रूप से एकांत में कैद होने के कुछ घंटों के भीतर हुए थे, रीच ने मोटर उत्तेजना की ओर ले जाने वाली गंभीर चिंता के अलावा मतिभ्रम और उत्पीड़न संबंधी भ्रम का वर्णन किया-"वह रोगी शोर मचाता है, चिल्लाता है, उद्देश्यहीन रूप से दौड़ता है, नष्ट कर देता है और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देता है।" 132 उन्होंने इन लक्षणों के साथ एक तीव्र भ्रमित स्थिति, लक्षणों की अचानक समाप्ति, ठीक होने और बाद में भूलने की बीमारी और, मनोविकृति की घटनाओं का भी वर्णन किया। एक सांख्यिकीय सारांश में, नेचट ने 1891 में वाल्डहेम में जेल के "पागल विभाग" में 186 कैदियों के नैदानिक मूल्यांकन पर रिपोर्ट की और निष्कर्ष निकाला कि इस विभाग में कुल कैदियों में से आधे से अधिक एकांत कारावास के लिए प्रतिक्रियाशील अभिव्यक्तियों के कारण थे। इनमें से अधिकांश कैदी एकांत में दो साल के कारावास के भीतर पागल हो गए। 1884 में सोमर ने 111 मामलों की सूचना दी जिसमें एकांत कारावास से जुड़ी एक तीव्र, प्रतिक्रियाशील, मतिभ्रमपूर्ण, चिंतित, भ्रमित स्थिति का वर्णन किया गया था, इन रोगियों के "उत्तेजित प्रकोप" और "द्वेषपूर्ण हमलों" पर जोर दिया

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

गया था। उनके रोगियों की बीमारी एकाग्रता में कठिनाई और मामूली "अकथनीय" बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति अतिसंवेदनशीलता के साथ शुरू हुई। इन "संवेदी की प्राथमिक गड़बड़ी (यानी, पाँच इंद्रियों)" को "प्राथमिक मतिभ्रम" की ओर ले जाने के रूप में देखा गया, जो अधिक संख्या में हो गए, जिसमें अंततः श्रवण, दृश्य और घ्राण मतिभ्रम शामिल थे और अंततः भयप्रद उत्पीड़न भ्रम के साथ शामिल हो गए।

1889 में किर्न ने फ्रीबर्ग में काउंटी जेल में कैदियों के बीच मनोविकृति के 129 मामलों का वर्णन किया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उनमें से पचास मामलों में, "एकांत कारावास को निश्चित रूप से एटियोलॉजिकल कारक माना जा सकता है, (और ये) एक निश्चित विशेषता की छाप दिखाते हैं" जिसमें कई क्षेत्रों में उत्पीड़न संबंधी भ्रम और मतिभ्रम (श्रवण, दृश्य घ्राण, स्पर्श) शामिल हैं। उन्होंने यह भी नोट किया कि ये लक्षण अक्सर रात में दिखाई देते हैं: [रोगी रात में अचानक मतिभ्रमपूर्ण अनुभवों से आश्चर्यचकित हो जाता है जो एक चिंतित उत्तेजना लाते हैं। ये अभिव्यक्तियाँ अब से स्थिर हो जाती हैं, कई मामलों में केवल रात में होती हैं, दूसरों में दिन में भी होती हैं। ध्यान देने वाले रोगियों को पहले कभी-कभी अपने कानों में एक गुनगुनाते हुए और गूँजते हुए, अप्रिय शोर और निष्क्रिय आवाज़ें सुनाई देती हैं जिन्हें वे तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि वे अच्छी तरह से अलग-अलग आवाज़ें और अलग-अलग शब्द और वाक्य नहीं सुन लेते।

.....दृश्य मतिभ्रम बहुत जीवंत हैं ।

1888 में मोएली ने "वोरबेरीडेन" का वर्णन किया-जिसे "अनुमानित उत्तरों के लक्षण" के रूप में भी जाना जाता है । " दस साल बाद गांसर ने साहित्य में एक सिंड्रोम को स्पष्ट करने में योगदान दिया जिसमें मोएली का लक्षण शामिल थे । । जैसा कि एरीती बताती हैं, गांसर सिंड्रोम/एक तरह का दिमाकी लक्षण सर्वविदित हो गया-वास्तव में, जेल के मनोरोगों पर साहित्य के पूरे शरीर का लगभग एक संहिताकरण । गांसर ने लक्षणों का एक व्यापक और अच्छी तरह से स्पष्ट संश्लेषण प्रदान किया, जिनमें से अधिकांश का वर्णन पहले कहीं और किया गया था । उन्होंने जिस सिंड्रोम का वर्णन किया, उसमें (वोरबेरीडेन के अलावा) जीवंत दृश्य और श्रवण संबंधी मतिभ्रम, चेतना का एक अलग धुंधलापन, "एक सपने के रूप में" लक्षणों की अचानक समाप्ति और "धुंधली चेतना की अवधि के दौरान घटनाओं के लिए कमोबेश पूरी तरह से भूलना शामिल था । " गांसर का सबसे मूल विवरण सिंड्रोम के भीतर "हिस्टेरिकल स्टिगमाटा" का था, जिसमें रूपांतरण के लक्षण, विशेष रूप से कुल

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

एनाल्जेसिया शामिल थे । कुछ जर्मन लेखक यह नोट करने में विफल रहे कि क्या वे जिन कैदियों का वर्णन कर रहे थे, उन्हें एकांत कारावास में रखा गया था और दुर्भाग्य से, गांसर इनमें से एक थे, केवल यह कहते हुए कि उनके कैदी मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे थे । हालांकि, लैंगार्ड ने 1901 में, मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे आरोपी कैदियों की टिप्पणियों पर भी रिपोर्ट करते हुए, उत्पीड़नकारी भ्रम के साथ एक तीव्र हिंसक मतिभ्रम का वर्णन किया और विशेष रूप से कहा कि 45 यह सिंड्रोम विशेष रूप से उन लोगों के बीच हुआ जो एकांत कारावास में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे थे । इसके अलावा 1901 में रेक्के ने इसी तरह मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों के बारे में बताया और गांसर द्वारा वर्णित पूर्ण सिंड्रोम का वर्णन किया, जिसमें वोरबेरीडेन भी शामिल था; उन्होंने विशेष रूप से एकल कारावास को सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार बताया । उन्होंने अपने मामलों को उदासीनता के साथ शुरू होने, "ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, सोचने में असमर्थता की भावना" और यहां तक कि नकारात्मकता, मूर्खता और उत्परिवर्तन सहित कैटाटोनिक विशेषताओं की ओर बढ़ने के रूप में वर्णित किया । उसी वर्ष लिखी गई एक अन्य रिपोर्ट में, स्क्लयर ने साठ मामलों के इतिहास पर रिपोर्ट की, जिनमें से उन्होंने 21 की पहचान एकांत कारावास के कारण होने वाले तीव्र जेल मनोविकृति के रूप में की । जबकि वोरबेरीडेन का उल्लेख नहीं किया गया था, गांसर और रेके द्वारा वर्णित अधिकांश अन्य लक्षण थे, जिनमें भारी चिंता और भयभीत श्रवण और दृश्य मतिभ्रम शामिल थे; गंभीर मामलों में, गंध, स्वाद और "सामान्य

संवेदना" के साथ-साथ उत्पीड़न भ्रम, मूर्खतापूर्ण आंदोलन और हिंसा, भ्रम और भटकाव। मनोविकृति तेजी से विकसित हुई, कभी-कभी एकांत कारावास में कैद होने के घंटों के भीतर। 150 कैटाटोनिक लक्षणविज्ञान को भी नोट किया गया था। जर्मन साहित्य ने केवल उन कैदियों के बारे में बताया जिन्हें कुल मनोवैज्ञानिक लक्षणविज्ञान का नुकसान उठाना पड़ा। जिनमें से कुछ को अस्पतालों या जेलों के "पागल विभागों" में देखा गया था; इस प्रकार, इन रिपोर्टों में आम तौर पर केवल सिंड्रोमल अभिव्यक्तियों का वर्णन किया गया था जो खुले तौर पर मनोविकृति के स्तर तक बढ़ गए थे। हालाँकि, जर्मन रिपोर्टें एकांत कारावास से जुड़े एक विशेष, चिकित्सकीय रूप से अलग करने योग्य मनोरोग सिंड्रोम के अस्तित्व को शक्तिशाली रूप से प्रदर्शित करती हैं। इन कई रिपोर्टों ने एक सिंड्रोम का वर्णन किया जिसमें शामिल थे:

1. भारी मुक्त-तैरती चिंता।

2. "संवेदक की गड़बड़ी", जिसमें शामिल हैं -क. बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

अतिसंवेदनशीलता; और

बी. कई क्षेत्रों में ज्वलंत मतिभ्रम (श्रवण, दृश्य, घ्राण, स्वाद और स्पर्श संबंधी तौर-तरीकों सहित); कुछ रिपोर्टों में, ये सरल "प्राथमिक" मतिभ्रम के रूप में शुरू हुए और जटिल, निर्मित मतिभ्रम में आगे बढ़े।

3. उत्पीड़क भ्रम, अक्सर सह-अस्तित्व वाले जटिल मतिभ्रम को शामिल करते हैं।

4. तीव्र भ्रमित अवस्थाएँ। कुछ रिपोर्टों में इन्हें सरल असावधानी और एकाग्रता में कठिनाई के साथ शुरुआत के रूप में देखा गया था। अन्य में, शुरुआत को अचानक बताया गया था। भ्रमित स्थिति और भटकाव को कई रिपोर्टों में एक असंबद्ध, स्वप्न जैसी स्थिति के समान वर्णित किया गया था, जिसमें कभी-कभी नकारात्मकता और उत्परिवर्तन सहित एक कैटाटोनिक मूर्छा की विशेषताएं शामिल होती हैं; और, ठीक होने पर, भ्रमित स्थिति की घटनाओं के लिए एक अवशिष्ट भूलने की स्थिति छोड़ देता है। गांसर और अन्य लोगों ने इस उलझनपूर्ण स्थिति के दौरान हिस्टेरिकल रूपांतरण के लक्षण देखे।

5. वोरबेरीडेन: यह एक दुर्लभ खोज थी, जिसे ज्यादातर एक भ्रमित, मतिभ्रमपूर्ण स्थिति के संयोजन में वर्णित किया गया था।

6. मोटर उत्तेजना, जो अक्सर अचानक, हिंसक विनाशकारी विस्फोटों से जुड़ी होती है।

7. बीमारी की विशेषता पाठ्यक्रमःक. शुरुआत को कुछ लेखकों द्वारा अचानक के रूप में वर्णित किया गया था, जैसा की संवेदी एकाग्रता में गड़बड़ी या असावधानी के साथ शुरू होने वाली प्रगति से शुरू होता है

बी. कई मामलों में, एकान्त कारावास की समाप्ति पर तीव्र लक्षणों का तेजी से ह्रास।

जर्मन रिपोर्ट आम तौर पर उन कैदियों पर आधारित थी जिन्हें उनकी मानसिक बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके विपरीत, वालपोल अध्ययन में बताई गई जनसंख्या को अत्यधिक मनोरोग स्थिति द्वारा पूर्वनिर्धारित नहीं किया गया था। इसके बावजूद, जर्मन चिकित्सकों द्वारा बताए गए सभी प्रमुख लक्षण वालपोल आबादी में देखे गए, सिवाय वोरबेरीडेन और हिस्टेरिकल रूपांतरण लक्षणों के। इसके अलावा, वालपोल आबादी में अलगाव सिंड्रोम के कम गंभीर रूप देखे गए, जिनमें शामिल हैं:

- अवधारणात्मक विकृतियाँ और अवधारणात्मक स्थिरता का नुकसान, कुछ मामलों में मतिभ्रम के बिना।
- संदर्भ के विचार और व्यामोहपूर्ण विचार स्पष्ट भ्रम से कम हैं।
- आदिम आक्रामक कल्पनाओं का उद्भव जो अहंकार-विकृत बने रहे और वास्तविकता-परीक्षण के साथ संरक्षित रहे।
- स्पष्ट दिशाहीनता और भ्रमित स्थिति की कमी से स्मृति और ध्यान में गड़बड़ी।
- बड़े पैमाने पर विघटनकारी प्रतिगमन के बिना विकेंद्रीकरण का अनुभव।

चूंकि गांसर की रिपोर्ट बीसवीं शताब्दी के साहित्य के एक बहुत बड़े निकाय की स्पष्ट स्मृति बन गई है, इसलिए गैर-जेल आबादी में गांसर सिंड्रोम की टिप्पणियों का वर्णन करने वाले साहित्य की समीक्षा करना भी दिलचस्प है। इनमें से कई रिपोर्ट इस सिंड्रोम से पीड़ित मनोरोग अस्पतालों में रोगियों के अध्ययन हैं। चूंकि इन रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसलिए उनकी स्थिति का अधिक व्यापक मूल्यांकन और परीक्षण प्राप्त करना संभव था। कई रिपोर्टों में अध्ययन किए गए अधिकांश रोगियों को लंबे समय से खड़े हिस्टेरिकल रूपांतरण लक्षणों से पीड़ित होने के रूप में वर्णित किया गया है; आवेग, बचपन की विकृति और असामाजिक व्यवहार को भी आमतौर पर वर्णित किया गया था। इन निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि असामाजिक व्यवहार और मनोरोगी व्यक्तित्व विकार का आदिम हिस्टेरिकल व्यक्तित्व विकार के साथ घनिष्ठ संबंध हो सकता है, एक ऐसा संबंध

जिसे अन्य लेखकों द्वारा भी वर्णित किया गया है ।

(75) संयुक्त राष्ट्र ने "कैदियों के साथ व्यवहार के लिए मानक न्यूनतम नियम" निर्धारित किए हैं जिन्हें "नेल्सन मंडेला नियम" कहा जाता है । " नियम 45 परिभाषित करता है कि एकांत कारावास का उपयोग केवल असाधारण मामलों में अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा, जितना संभव हो उतना कम समय के लिए और स्वतंत्र समीक्षा के अधीन, और केवल एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण के अनुसार । यह किसी कैदी की सजा के आधार पर नहीं लगाया जाएगा । मानसिक या शारीरिक अक्षमता वाले कैदियों के मामले में एकांत कारावास के अधिरोपण को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जब इस तरह के उपायों से उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी ।

(76) अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन द्वारा एक अच्छी तरह से शोध किए गए लेख "ए डेथ बिफोर डाइंग, सोलिटरी कन्फिनमेंट ऑन डेथ रो" में, लंबे समय तक एकांत कारावास के निम्नलिखित विनाशकारी प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है:-

“अनुभवजन्य शोध लगातार दर्शाता है कि अलगाव के अधीन कैदियों को शारीरिक यातना के कारण होने वाले कई समान लक्षणों का सामना करना पड़ता है । 7

शोध से पता चलता है कि एकांत कारावास के अधीन लोग विभिन्न प्रकार की नकारात्मक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति अतिसंवेदनशीलता;
- अवधारणात्मक विकृतियाँ और मतिभ्रम;
- चिंता और घबराहट में वृद्धि;
- उत्पीड़न का डर; आवेग नियंत्रण की कमी; • गंभीर और पुराना अवसाद;
- भूख की कमी और वजन घटाना;
- दिल की धड़कन;
- वापस लेना; प्रभाव और उदासीनता को कम करना;
- खुद से बात करना;
- सिरदर्द; • नींद की समस्याएँ;

- भ्रमित विचार प्रक्रियाएँ;
- बुरे सपने;
- चक्कर आना;
- आत्म-विच्छेदन; और
- एकान्त कारावास में केवल सात दिनों के बाद ई. ई. जी. गतिविधि में गिरावट सहित मस्तिष्क कार्य के निम्न स्तर । ”

(77) "विल्किंसन बनाम ऑस्टिन" के मामले में, 2005 के यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के मामले में, न्यायमूर्ति कैनेडी ने निम्नानुसार राय दी:-

“[ए] एक कैदी के जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित और निगरानी की जाती है । कैदियों को अपनी कोठरी में 23 घंटे प्रति दिन रहना चाहिए, जिसका माप 7 गुणा 14 फीट है । कक्ष में हर समय एक प्रकाश रहता है ।और एक कैदी जो सोने के लिए प्रकाश को बचाने का प्रयास करता है, वह आगे discipline.Incarceration [सुपरमैक्स में] के अधीन होता है जो अत्यधिक अलगाव का पर्याय है । ओहायो की किसी भी अन्य जेल के विपरीत ।[कक्षों में धातु के ठोस दरवाजे होते हैं जिनके किनारों और तल पर धातु की पट्टियाँ होती हैं जो अन्य कैदियों के साथ बातचीत या संचार को रोकती हैं । सभी भोजन अकेले लिए जाते हैं । ...भेंट के अवसर यह कहना उचित है कि कैदी लगभग किसी भी पर्यावरणीय या संवेदी उत्तेजना और लगभग सभी मानव संपर्क से वंचित हैं । ... [पी] फीता । ..यह एक अनिश्चित अवधि के लिए है, जो केवल एक कैदी की सजा तक सीमित है । ”

(78) सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में

अन्य 6 माननीय उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपतियों ने समझाया है कि 'मौत की सजा के तहत कैदी' शब्द का अर्थ केवल वे कैदी हो सकते हैं जिनकी मौत की सजा अंतिम, निर्णायक और अक्षम्य हो गई है जिसे किसी भी न्यायिक या संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा रद्द या रद्द नहीं किया जा सकता है । दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसे निष्पादित करने और निष्पादित करने के कर्तव्य के साथ आरोपित प्राधिकरण को किसी भी बाहरी प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए । उनके अधिपतियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) और 21 के साथ जेल अधिनियम

की धारा 366 (2) और धारा 30 (2) की भी व्याख्या की है। उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं:-

(6 ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1675)

“102. जेल अभिरक्षा में यह 'सुरक्षित रखना' जेलर का सीमित अधिकार क्षेत्र है। दोषी को कारावास की सजा नहीं दी जाती है। उसे एकांत कारावास की सजा नहीं दी जाती है। वह अभिरक्षा में एक अतिथि है, मेजबान-जेलर की सुरक्षा में तब तक रहता है जब तक कि स्थलीय विदाई का अंतिम समय उसे ठहराव पर नहीं ले जाता। यह अधीक्षक के हाथों में ट्रस्टीशिप है, सही मायने में कारावास नहीं। धारा 366 (2) दंड प्रक्रिया संहिता (जेल अभिरक्षा) और प्रपत्र 40 (सुरक्षित रूप से रखने के लिए) इस अवधारणा को रेखांकित करते हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के साथ पठित धारा 53 के तहत कारावास की सजा के अभाव से प्रबलित है। यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि यदि 'दोषी' पुरुषों को शारीरिक या मानसिक यातना से नुकसान पहुंचाया जाता है तो कानून ऐसा करना बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि चोट और सुरक्षा स्पष्ट रूप से दुश्मन हैं। और एक बार जेल के भीतर कारावास और सुरक्षित रखने के बीच इस गुणात्मक अंतर को समझने के बाद, जेलर की शक्ति सौम्य हो जाती है। बत्रा और उनके जैसे अन्य लोग हर प्राणी आराम और सांस्कृतिक सुविधा के हकदार हैं जो दयालु सुरक्षा का तात्पर्य है। बिस्तर और तकिया, मानव जाति के साथ व्यापार करने का अवसर, मंदिरों में पूजा करने का अवसर, यदि कोई हो, तो खेल, किताबें, समाचार पत्र, लेखन सामग्री, परिवार के सदस्यों से मिलना और जीवन की सभी अच्छी चीजें, जब तक जीवन चलता है और जेल की सुविधाएं मौजूद हैं। वार्ड को पिंजरे में डालने और उसे आघात पहुंचाने के लिए एक छिपे हुए अवसर में सुरक्षित रखने को विकृत करना कानून की हिरासत के साथ विश्वासघात करना है। सुरक्षित अभिरक्षा का अर्थ यह नहीं है कि वंचित किया जाए, अलग-थलग किया जाए, जेल जीवन के लेंटन भोज से निर्वासित किया जाए और कष्ट दिए जाएं जैसे कि वार्ड को लगभग-पागलपन से पीड़ित करके संरक्षकता को सबसे अच्छा पूरा किया गया हो। हो सकता है कि जेल अधीक्षक के पास जेल के उपयोग का बहाना हो, और हो सकता है कि वह हमारे संविधान के अलंघनीय मूल्यों से निर्दोष हो। शायद, पेशेवर प्रशिक्षण और जेल संस्कृति में कुछ गड़बड़ है। शायद, वह अनजाने में परमेश्वर की मदद करने के अपने मिशन की कल्पना करता है! 'जिसे भगवान नष्ट करना चाहते हैं, वह पहले पागल कर देते हैं। क्योंकि, लंबा अलगाव इंदिरियों को तब तक परेशान करता है जब तक कि आत्मा पागलपन के पड़ोस में समाप्त नहीं हो जाती। सुरक्षित रखने का अर्थ है अपने शरीर और मन को उचित स्थिति में रखना। उसके दिमाग को

प्रताड़ित करना असुरक्षित रखना है। उनके व्यक्तित्व की चोट सुरक्षित नहीं है। इसलिए, धारा 366 सी. आर. पी. सी. किसी भी ऐसे कार्य को मना करती है जो व्यक्ति के शरीर और दिमाग को बाधित करता है। उसका मांस और उसकी आत्मा को कुचलना सुरक्षित नहीं है, चाहे वह कुछ भी हो।

XXXXXXXXXXXX

114. एक दोषी 'मौत की सजा के तहत' होता है जब, और केवल तभी, जब मृत्युदंड कप और हॉट के बीच किसी भी पर्ची के बिना कानून की स्वचालित प्रक्रिया द्वारा संचालित होता है। अब्दुल अज़ीज़ बनाम कर्नाटक 44 और डी. के. शर्मा बनाम एम. पी. राज्य 45 में इस न्यायालय के निर्णय, हालांकि इस बिंदु पर सीधे तौर पर नहीं, इस तर्क को सही होने का दृढ़ता से सुझाव देते हैं।

XXXX

XXXX

XXXX

120. निष्कर्ष अनिवार्य रूप से यह है कि बत्रा, या उस मामले में, उनके जैसे अन्य लोगोंको "मौत की सजा के तहत" व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उन्हें अन्य कैदियों से अलग नहीं रखा जा सकता है। न ही उसे कठोर कारावास की सजा दी जाती है और इसलिए उसे कठोर परिश्रम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। वह हिरासत में है क्योंकि अदालत ने मौत की सजा की पुष्टि होने तक जेल प्राधिकरण को सजा पाए व्यक्ति को हिरासत में रखने का आदेश दिया है। ठोस परिणाम स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

XXXXXXXXXXXX 223 | धारा 30 की उप-धारा (2) के संदर्भ में "मृत्युदंड के तहत कैदी" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल वह कैदी हो सकता है जिसकी मृत्युदंड की सजा अंतिम, निर्णायक और अक्षम्य हो गई है जिसे किसी भी न्यायिक या संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा रद्द या रद्द नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसे निष्पादित करने और निष्पादित करने के कर्तव्य के साथ आरोपित प्राधिकरण को किसी भी बाहरी प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य बनाम सिंधी उर्फ रमन के थोड़े अलग संदर्भ में यह कहा गया था कि मौत की सजा के तहत एक आरोपी व्यक्ति का मुकदमा सत्र न्यायालय में कार्यवाही की समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होता है क्योंकि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मौत की सजा उच्च

न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन है। एक सक्षम अदालत द्वारा निष्पादन योग्य सजा पारित किए जाने तक एक मुकदमे को समाप्त नहीं माना जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के संदर्भ में शेख अब्दुल अज़ीज़ बनाम कर्नाटक राज्य में कहा गया था कि एक अभियुक्त दूसरी हत्या के समय आजीवन कारावास की सजा के तहत नहीं हो सकता है जब तक कि वह वास्तव में ऐसी सजा से गुजर रहा है या कानूनी रूप से एक न्यायिक रूप से अंतिम सजा मौजूद है जिसे वह सजा में जीवन की सांस लेने के लिए एक अलग आदेश की आवश्यकता के बिना देने के लिए बाध्य है जो अन्यथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत छूट के कारण मृत था। इसलिए, कैदी को केवल तभी मौत की सजा के तहत कहा जा सकता है जब मौत की सजा न्यायिक जांच से परे हो और किसी अन्य प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना प्रभावी हो। तब तक जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है, उसे धारा 30, उप-धारा (2) के संदर्भ में मृत्युदंड के तहत कैदी नहीं कहा जा सकता है। हम आशा करते हैं कि यह व्याख्यात्मक प्रक्रिया धारा 30 की उप-धारा (2) में निहित यातना और यातना को काफी हद तक दूर करेगी, जिससे इस तरह के कारावास की अवधि कम हो जाएगी।

XXXXXXXXXXXXX 224। तब ऐसे कैदी को कारावास में रखने की प्रकृति क्या है जिसे सत्र न्यायाधीश द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है और सजा के समय से लेकर सजा स्वतः निष्पादन योग्य होने तक कोई अन्य सजा नहीं दी जाती है? सी. आर. पी. सी. की धारा 366 (2) अदालत को दोषी व्यक्ति को सजा देने में सक्षम बनाती है जिसे वारंट के तहत जेल हिरासत में मौत की सजा दी जाती है। वारंट में यह निहित है कि कैदी को न तो साधारण और न ही कठोर कारावास दिया जाता है। उप-धारा (2) धारा 366 को लागू करने के पीछे का उद्देश्य कैदी को तब उपलब्ध कराना है जब सजा को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। उसे जेल की हिरासत में रखा जाना है। लेकिन यह अभिरक्षा साधारण या कठोर कारावास से पीड़ित एक दोषी की अभिरक्षा से कुछ अलग है। उसे जेल हिरासत में रखा जा रहा है ताकि जब भी वह स्थिति उत्पन्न हो उसे सजा के निष्पादन के लिए उपलब्ध कराया जा सके। सजा निष्पादन योग्य होने के बाद उसे दिन और रात की निगरानी के साथ अन्य कैदियों के अलावा एक कोठरी में रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ भी, जब तक कि विशेष परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं, उसे अन्य कैदियों की दृष्टि और ध्वनि के भीतर होना चाहिए और उनके साथ भोजन करने में सक्षम होना चाहिए।

225. यदि मृत्युदंड के तहत कैदी को जेल हिरासत में रखा जाता है, तो उस पर जेल अधिकारी द्वारा जेल के अपराधों को छोड़कर दंडात्मक निरोध नहीं लगाया जा सकता है।।

जब कोई कैदी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 (2) के तहत जेल हिरासत के वारंट के तहत प्रतिबद्ध होता है और यदि उसे एकांत कारावास में रखा जाता है जो कि आईपीसी की धारा 73 द्वारा निर्धारित सजा है, तो यह एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा देने के बराबर होगा जो अनुच्छेद 20 (2) का उल्लंघन होगा। लेकिन चूंकि कैदी को एकांत कारावास में नहीं रखा जाना है और जिस अभिरक्षा में उसे धारा 30 (2) के तहत रखा जाना है, जैसा कि हमारे द्वारा व्याख्या की गई है, वह एकांत कारावास में निरोध को रोक देगा, इसलिए उस पर दूसरी सजा देने की कोई संभावना नहीं है और इसलिए, धारा 30 (2) अनुच्छेद 20 का उल्लंघन नहीं है।

XXXXXXXXXXXX228 | अनुच्छेद 21 के तहत चुनौती धारा 30 की उप-धारा (2) की हमारी व्याख्या पर विफल होनी चाहिए। जेल में बंद व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दंडात्मक निरोध द्वारा काफी हद तक कम हो जाती है। निवारक निरोध में भी इसमें कटौती की जाती है। यदि काफी हद तक कटौती की जाती है, तो कैदियों के साथ घूमने, मिलाने, मिलने, बात करने, साझा करने, कंपनी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन

होगी, जब तक कि कटौती को कानून का समर्थन न हो। धारा 30 की उप-धारा (2) उस प्रक्रिया को स्थापित करती है जिसके द्वारा इसे कम किया जा सकता है, इसे हमारी व्याख्या के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 में "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति में "कानून" शब्द की व्याख्या मेनका गांधी के मामले में इस अर्थ में की गई है कि कानून सही, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए, न कि मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी। अन्यथा यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी और अनुच्छेद 21 की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। यदि यह मनमाना है तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। एक बार जब धारा 30 (2) को हमारे द्वारा किए गए तरीके से पढ़ा जाता है, तो इसका अप्रिय तत्व मिटा दिया जाता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मनमाना है या कानून के अधिकार के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित है।”

(79) श्रीमती के मामले में। त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य और अन्य 7 समान मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके नेतृत्व ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक मामला अंतिम निर्णय से पहले किसी भी अदालत में लंबित है, तब तक जिस व्यक्ति की निंदा की गई है या जिसे मौत की सजा सुनाई गई है, उसके पास भी आशा की किरण है और वह ऐसा नहीं करता है। उस मानसिक यातना को सहें जो एक व्यक्ति को तब होती है जब वह जानता है कि उसे फांसी दी जानी है लेकिन वह कयामत के दिन का इंतजार करता है।

उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं:-

(7 1989 (1) एससीसी 678)

“16. इस न्यायालय में भी हालांकि कोई विशिष्ट नियम प्रतीत नहीं होता है, लेकिन आम तौर पर इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि यह तर्क दिया गया था कि हमारे सामने यह संदर्भ-पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ/bench लंबे समय के अंतराल के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। हम नहीं जानते कि इस संदर्भ को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया जा सका, सिवाय इसके कि आम तौर पर पाँच न्यायाधीशों की पीठ/bench प्रदान करने की कठिनाई सर्वविदित है, लेकिन आम तौर पर यह उम्मीद की जाती है कि इस न्यायालय में भी जिन मामलों में मृत्युदंड शामिल है, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी सुनवाई की जाएगी और जल्द से जल्द निपटाया जाएगा, लेकिन इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि जब तक मामला अंतिम निर्णय से पहले किसी भी अदालत में लंबित है, तब तक उस व्यक्ति को भी उम्मीद की किरण है जिसे दोषी ठहराया गया है या जिसे मौत

की सजा सुनाई गई है। इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि वह उस मानसिक यातना का सामना करता है जिसे एक व्यक्ति तब करता है जब वह जानता है कि उसे फांसी दी जानी है, लेकिन वह कयामत के दिन का इंतजार करता है। इसलिए मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के सवाल पर विचार करते समय जिस देरी पर विचार किया जा सकता है, वह केवल शीर्ष अदालत द्वारा निर्णय सुनाए जाने की तारीख से ही हो सकती है, यानी जब न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।”

(80) ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 8 वें संस्करण में, "एकान्त कारावास" शब्द को "अलग कारावास" के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक कैदी को अन्य लोगों तक बेहद सीमित पहुंच प्रदान करता है।”

(81) "शब्द और वाक्यांश, स्थायी संस्करण, खंड 39" में, 'एकान्त कारावास' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“'एकान्त कारावास' द्वारा सजा की प्रणाली की विशिष्टताओं में कैदी को सभी मानव समाज से पूरी तरह से अलग करना और काफी आकार की कोठरी में उसे इस तरह से कैद करना था कि वह किसी भी इंसान के साथ सीधा संभोग या दृष्टि न कर सके और न ही कोई रोजगार या निर्देश। (लीच बनाम व्हिटबेक, 115 N.W.253,254),(151 माइक। 327, री मेडले), (10 एस. सी. टी.), (384, 134 यू. एस. 160,33 एल. एड.

835.)में परिभाषा को उद्धृत करना और अपनाना है

“निकट कारावास "और" एकान्त कारावास "एक ही तरह की सजा नहीं देते हैं। यद्यपि "एकान्त कारावास" में "निकट कारावास" शामिल हो सकता है, एक अपराधी को "एकान्त कारावास" के अधीन किए बिना "निकट कारावास" में रखा जा सकता है।” “कारावास "और" निकट कारावास "का समान रूप से अर्थ है ऐसी अभिरक्षा, और केवल ऐसी अभिरक्षा, जो कैदी के शव को उसके निष्पादन के लिए निर्धारित दिन पर सुरक्षित रूप से पेश करेगी। रूनी बनाम स्टेट ऑफ नॉर्थ डकोटा, एन. डी., 25 एस. सी. टी. 264, 266, 196 यू. एस. 319,49 एल. एड. 494, 3 Ann.Cas। 76.”

(82) लेख में शीर्षक के तहत "क्या मृत्युदंड के लिए मृत्युदंड की आवश्यकता है? नोट्रे डेम लॉ स्कूल द्वारा प्रकाशित माराह एस. मैकलियोड द्वारा लिखित "द हार्म ऑफ लेजिस्लेटिव साइलेंस", विद्वान लेखक ने अपने लेख में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें पूर्व-निष्पादन कारावास की अवधि बढ़ाना शामिल है, (ए) क्या दोषी को अक्षम करने के लिए मौत की सजा

आवश्यक है?(ख) क्या दोषी के पुनर्वास के लिए मौत की सजा आवश्यक है? (ग) क्या प्रतिशोधात्मक न्याय के लिए मृत्युदंड आवश्यक है? और (घ) क्या दूसरों को अपराध से रोकने के लिए मृत्युदंड आवश्यक है? निम्नानुसार:-

परिचय

मृत्युदंड पर जीवन की तुलना यातना से की गई है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने इंग्लैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीगत आरोपों का सामना करने के लिए एक यूरोपीय नागरिक को प्रत्यर्पित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि इस जोखिम के कारण कि वह व्यक्ति अमानवीय परिस्थितियों में वर्जीनिया की मौत की सजा तक सीमित हो जाएगा। वर्जीनिया जैसे राज्यों में, मौत की सजा पाए कैदियों को वर्षों तक एकांत कारावास में रखा जाता है और अक्सर दशकों तक उनके निष्पादन तक एक ऐसी स्थिति होती है जो इतनी गंभीर होती है कि, हाल के राजधानी मामले में न्यायमूर्ति एंथनी कैनेडी के शब्दों में, यह कैदियों को "पागलपन के किनारे पर ला सकता है, शायद पागलपन के लिए"। कई विद्वानों और न्यायाधीशों ने मौत की सजा को बर्बर और क्रूर बताते हुए हमला किया है; कुछ ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि मौत की सजा पाए कैदियों को उनकी अपील छोड़ने और फांसी के लिए "स्वेच्छा से" प्रेरित किया जा रहा है क्योंकि मौत की सजा पर जीवन मौत से भी बदतर है। वास्तव में, 1976 से फांसी दिए गए कैदियों में से दस प्रतिशत से अधिक ने फांसी के

लिए स्वेच्छा से काम किया है।

यदि कैदियों को हफ्तों या महीनों के भीतर फांसी दी जाती है, जैसा कि वे दो सौ साल पहले थे, तो मौत की सजा पर इस तरह का ध्यान नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आज, मौत की सजा पाने वाले कैदी औसतन साढ़े पंद्रह साल तक फांसी की प्रतीक्षा करते हैं।

समय की मात्रा हैं जो अन्य कैदियों को गंभीर अपराधों के लिए सजा के रूप में सीमित किया जाता है। आज मौत की सजा पाए लगभग 3,000 कैदियों में से, फांसी दिए जाने की तुलना में प्राकृतिक कारणों से मरने की अधिक संभावना है। निष्पादन में देरी ने मृत्युदंड को अपेक्षाकृत त्वरित निष्पादन से मृत्युदंड की न्यायिक सजा और जेल में जीवन के करीब कुछ की वास्तविक सजा में बदल दिया है। मौत की सजा पर रहने का अलगाव और अलगाव इन कैदियों पर उनके लंबे समय तक वास्तविक कारावास के कारण होने वाली पीड़ा को बढ़ाता है। एकांत कारावास के कारण होने वाले अनूठे नुकसान हाल ही में गहन अध्ययन और

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

मीडिया के ध्यान का केंद्र बन गए हैं, जिसमें इसके दुर्बल करने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों के आधार पर एकांत कारावास के उपयोग को समाप्त करने के लिए कॉल किया गया है।

फिर भी मौत की सजा, और आमतौर पर इसमें जो अलगाव शामिल होता है, उसे अक्सर मौत की सजा के एक अपरिहार्य प्रशासनिक पहलू के रूप में माना जाता है। जिस हद तक विद्वानों और अदालतों ने मौत की सजा पर ध्यान केंद्रित किया है, उन्होंने मुख्य रूप से इसकी कठोरता और इसके अपंग मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर आपत्ति जताई है। किसी ने भी इस तथ्य को चुनौती नहीं दी है कि जेल प्रशासकों ने बिना किसी विधायी जनादेश के मौत की सजा स्थापित करने का विकल्प चुना है। अभी हाल ही में, वर्जीनिया के एक मामले में आयोजित चौथे सर्किट में कहा गया है कि "वर्जीनिया में मौत की सजा मौत की सजा पर पूर्व कारावास है।" अदालत ने कहा कि, "वर्जीनिया कानून यह आदेश देता है कि मृत्युदंड की सजा मिलने पर मृत्युदंड के लिए दोषी ठहराए गए सभी व्यक्तियों को स्वतः ही मृत्युदंड तक सीमित कर दिया जाए। उनके द्वारा किए गए अपराध और उन्हें मिली सजा के कारण। वास्तव में, हालांकि वर्जीनिया और अन्य जगहों पर मौत की सजा पाए कैदियों को स्वचालित रूप से और स्थायी रूप से मौत की सजा के लिए भेजा जाता है, कुछ क्षेत्राधिकारों में वैधानिक कानून द्वारा मौत की सजा की आवश्यकता होती है। वर्जीनिया में,

और अधिकांश राज्यों में, मौत की सजा केवल जेल नीति के रूप में लागू की जाती है। मृत्युदंड विद्वान डेविड गारलैंड के शब्दों में, मृत्युदंड "एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें कोई विशिष्ट कानूनी अधिकार नहीं है।"

यह अनुच्छेद पहली बार मौत की सजा स्थापित करने के लिए जेल प्रशासकों के अधिकार को संबोधित करता है। विश्लेषण मौत की सजा स्थापित करने के निर्णय की प्रकृति पर विचार के साथ शुरू होता है, और निष्कर्ष निकालता है- के प्रचलित धारणाएँ-कि मृत्युदंड को प्रशासनिक कारणों से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बजाय, इसे केवल सजा के तर्क के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। यह निष्कर्ष अनुच्छेद में दूसरे और अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाता है, जो यह है कि अकेले विधानसभाएं मौत की सजा की आवश्यकता के लिए सक्षम हैं।

मृत्युदंड के निर्णय की प्रकृति को समझने के लिए, अनुच्छेद पूछता है कि असमर्थता, पुनर्वास, प्रतिशोध और निरोध के पारंपरिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस तरह के कारावास से क्या संभावित उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। इनमें से पहला, अक्षमता, मौत की सजा के लिए प्राथमिक प्रशासनिक तर्क पर बारीकी से नज़र रखता है, जो कि जेल सुरक्षा

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

है।

बढ़ते सबूतों ने इस दावे को कमजोर कर दिया है कि जेल की सुरक्षा के लिए मौत की सजा की आवश्यकता है। सबसे शक्तिशाली सबूत मिसौरी से आता है, जिसने बीस साल पहले मौत की सजा को समाप्त कर दिया था। मिसौरी द्वारा मौत की सजा को समाप्त करने के बाद, और उनके उचित हिरासत स्तर को निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने मौत की सजा पाने वाले कैदियों का मूल्यांकन करना शुरू करने के बाद, यह पता चला कि उनमें से अधिकांश को अलगाव की आवश्यकता नहीं थी। और एक अनुवर्ती अध्ययन से पता चला कि मिसौरी में मौत की सजा के उन्मूलन के बाद, मौत की सजा पाए कैदियों ने उसी संस्थान के कैदियों की तुलना में कम हिंसक दुराचार किया, जिन्हें कम सजा दी गई थी। मिसौरी के अनुभव-और जेल हिंसा के अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि सभी मौत की सजा पाए कैदियों की मौत की सजा पर स्वचालित और स्थायी अलगाव कई कैदियों के लिए पर्याप्त अनावश्यक पीड़ा की ओर ले जाता है।

हालाँकि, मौत की सजा पाए सभी कैदियों को अलग-थलग करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा तर्क की कमी का मतलब यह नहीं है कि मौत की सजा को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अगला अनुच्छेद इस बात पर विचार करता है कि क्या मौत की सजा पुनर्वास, प्रतिशोध या निवारण के उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। यह निष्कर्ष निकालता है कि मृत्युदंड को बनाए रखने के लिए प्रतिशोध और प्रतिरोध प्रशंसनीय कारण हैं। प्रतिशोधात्मक न्याय के एक अधिवक्ता का तर्क हो सकता है कि जिन कैदियों ने सबसे खराब अपराध किए हैं, उन्हें ऐसी स्थितियों में रखा जाना चाहिए जो उनके अपराधों की गंभीरता को दर्शाती हैं। निरोध की खोज दूसरों को इस उम्मीद में मौत की सजा का समर्थन करने के लिए प्रेरित कर सकती है कि संभावित राजधानी हत्यारे क्रूर मौत की सजा की स्थितियों की निश्चितता से डरेंगे, भले ही वे भविष्य में लंबे समय तक फांसी की संभावना को कम कर सकें।

यहाँ मुद्दा यह नहीं है कि मौत की सजा को इन कारणों से बनाए रखा जाना चाहिए, बल्कि केवल यह है कि ये सजा के उद्देश्य संभावित कारण प्रदान करते हैं कि क्यों कुछ लोग इसे संरक्षित करना चाहते हैं।

एक बार जब कोई यह स्वीकार कर लेता है कि सजा के कारणों से मौत की सजा बरकरार रखी जा सकती है, तो जांच इस बात पर होनी चाहिए कि किसे निर्णय लेना चाहिए। केवल विधायिकाएँ ही यह तय करने के लिए उपयुक्त हैं कि कम से कम तीन कारणों से मौत की

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

सजा बरकरार रखी जाए या नहीं। सबसे पहले, विधायिकाओं के पास नैतिक प्रश्नों का उत्तर देने में लोकतांत्रिक वैधता का सबसे बड़ा दावा है जो किसी भी अनुभवजन्य रूप से सही उत्तर को स्वीकार नहीं करते हैं—जैसे कि प्रतिशोधात्मक दंड की उचित मात्रा या पहली जगह में प्रतिशोध या प्रतिरोध का पीछा करना। दूसरा, शक्तियों का पृथक्करण केवल विधायिकाओं को सजा निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। तीसरा, वैधता के सिद्धांत को संतुष्ट करने के लिए सजा के पूर्व वैधानिक प्राधिकरण की आवश्यकता है। इन तीन विचारों में से प्रत्येक मृत्यु पंक्ति को बनाए रखने से पहले विधायी अभेद्यता को व्यक्त करने की मांग करता है। इसके अलावा, विधायिकाओं को केवल जेल प्रशासकों को मौत की सजा स्थापित करने की शक्ति सौंपने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कई राज्यों में, शक्तियों के संवैधानिक पृथक्करण के तहत सजा देने की शक्ति अप्राप्य है। और उन राज्यों में भी जहां इस तरह के प्रतिनिधिमंडल की अनुमति दी जा सकती है, अनुच्छेद में तर्क दिया गया है कि जेल प्रशासकों को मौत की सजा का निर्णय सौंपना बुद्धिमानी नहीं होगी। जेल प्रशासकों के लिए मौत की सजा को केवल इसलिए बनाए रखना चुन सकते हैं क्योंकि इस तरह की प्रतिबंधात्मक अभिरक्षा उनके लिए निष्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करना और उसकी देखरेख करना मनोवैज्ञानिक रूप से आसान बनाती है, न कि वैध उद्देश्यों के लिए।

पूर्वगामी तर्क मृत्युदंड की यथास्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अदालतों को कम से कम उन राज्यों में, जहां शक्तियों का सख्त पृथक्करण बना हुआ है, मौजूदा मौत की सजा वाली नीतियों को अधिकार से बाहर और अमान्य ठहराने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद विधानमंडल यह चुन सकते हैं कि मृत्युदंड को संरक्षित करने के लिए कानून बनाए जाएं या नहीं। कुछ लोग मौत की सजा को बहाल नहीं करने का फैसला कर सकते हैं, शायद इसकी क़रूरता या इसके खर्च के कारण। अन्य लोग सजा सुनाने वाले अधिकारियों को केवल कुछ गंभीर मामलों में या केवल सीमित समय के लिए मौत की सजा देने के लिए अधिकृत करने का निर्णय ले सकते हैं।

कुछ लोग विधायी गतिरोध के कारण कुछ नहीं करेंगे। अवैध प्रशासनिक कार्रवाई की यथास्थिति के लिए ये सभी परिणाम स्वीकार्य और बेहतर होंगे। कुछ लोग विधायी विकल्प के लिए इस तर्क पर आपत्ति कर सकते हैं। दो मुख्य आपत्तियों की सबसे अधिक संभावना प्रतीत होती है। एक तर्क के विस्तार पर जाता है: क्या विधायिकाओं से जेल प्रशासकों द्वारा अन्य सभी निर्णयों का सूक्ष्म प्रबंधन करने की अपेक्षा की जाएगी? यह आपत्ति प्रशासकों के अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर जेल के फैसलों में हस्तक्षेप करने के लिए एक वैध

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

अनिच्छा को दर्शाएगी। लेकिन मौत की सजा की नियुक्ति जेल प्रशासकों द्वारा किए गए अधिकांश या सभी निर्णयों से महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न होती है। तीन विशेषताएँ आम तौर पर मृत्यु पंक्ति को अलग करती हैं: इसकी स्थिरता, इसकी स्पष्ट अधिरोपण और इसकी गंभीरता। इन तीन विशेषताओं से पता चलता है कि मौत की सजा जेल प्रशासकों द्वारा ठीक से किया गया विकल्प क्यों नहीं है, हमें क्यों परवाह करनी चाहिए, और विधायिकाओं को मौत की सजा पर शक्ति को फिर से आवंटित करने से नियमित जेल नियमों की श्रृंखला का सूक्ष्म प्रबंधन क्यों नहीं होगा।

दूसरी संभावित आपत्ति विधायी चयन के लिए एक तर्क के परिणामों पर जाती है: क्या विधायक जेल प्रशासकों की तुलना में कम मानवीय नहीं होंगे? विलियम स्टंटज़ ने प्रसिद्ध रूप से आपराधिक कानून की रोगजनक राजनीति और राजनेताओं की अपराध पर कठोर दिखने के लिए हमेशा कठोर दंड लगाने की प्रवृत्ति की खोज की। हालाँकि, यह आपत्ति सजा के निर्धारण में सार्वजनिक विचार-विमर्श और लोकतांत्रिक वैधता के महत्व, शक्तियों के पृथक्करण द्वारा लगाई गई सीमाओं और सजा निर्धारित होने पर वैधानिक प्राधिकरण की वैधता की आवश्यकता के सिद्धांत की अनदेखी करती है। ये महत्वपूर्ण विचार विधायी चयन के परिणामों पर निर्भर नहीं करते हैं।

परिणामवादी आलोचना भी अपनी शर्तों पर गलत हो सकती है। मौत की सजा के संबंध में अधिक लोकतांत्रिक निर्णय अधिक अमानवीयता का कारण नहीं बन सकते हैं।

उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक रूप से, विधायिकाओं ने निष्पादन के अधिक मानवीय तरीकों को अपनाया है। यह कल्पना करना मुश्किल होगा कि जेल प्रशासकों की तुलना में विधायिकाएं मौत की सजा के संबंध में काफी कठोर हैं। और भले ही कुछ राजनेता मानवीय चिंताओं को नजरअंदाज कर दें, वे निश्चित समय के लिए मौत की सजा को समाप्त करने के लिए सहमत हो सकते हैं। क्योंकि अभिरक्षा प्रतिबंध (विशेष रूप से एकान्त कारावास) उच्च लागत लगाता है। मौत की सजा वाले आवास की लागत प्रति कैदी प्रति वर्ष लगभग 100,000 डॉलर अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार, विधायिकाएँ कई कारणों से मौत की सजा को समाप्त कर सकती हैं, वित्तीय के साथ-साथ मानवीय भी।

B. वर्तमान मृत्यु पंक्ति की शर्तें

मौत की पंक्ति में मौत की सजा पाए कैदियों को अलग करना और उन्हें अन्य कैदियों से दूर "एक अलग बाड़े" में रखना शामिल है। आज, लगभग सभी इकतीस मृत्युदंड वाले राज्य

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

(साथ ही संघीय सरकार और सेना) अपने मृत्युदंड वाले कैदियों को अलग करते हैं। उन क्षेत्राधिकारों में, मौत की सजा पाए कैदियों को गैर-राजधानी कैदियों से दूर एक इकाई या स्तर में रखा जाता है, हालांकि कुछ राज्यों में उन्हें अस्थायी रूप से अलग किए गए गैर-राजधानी कैदियों के साथ रखा जा सकता है जिन्हें सामान्य जेल आबादी से भी हटा दिया जाता है।

मौत की पंक्ति में अलगाव से अधिक शामिल है, हालांकि, अधिकांश राज्य मौत की सजा पाने वाले कैदियों पर प्रतिबंध लगाते हैं जो उन्हें मानव बातचीत से अलग करते हैं। ये प्रतिबंध विभिन्न रूपों में आते हैं, जैसे कि एकल-व्यक्ति कक्ष में अलगाव, संचार को रोकने के लिए ठोस दीवारों और दरवाजों से बंद कक्षों में कारावास, भोजन के दौरान अलगाव (कक्ष में अकेले लिया जाता है), व्यायाम के दौरान अलगाव (एकल-व्यक्ति कलम में), काम के अवसरों और समूह कार्यक्रमों से इनकार, समूह धार्मिक सेवाओं से इनकार, और परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क यात्राओं पर प्रतिबंध सहित यात्रा प्रतिबंध है। हाल की एक जांच से पता चला है कि "अधिकांश मौत की सजा पाए कैदी. दिन में 22 से 24 घंटे के लिए छोटी कोठरी में अकेले बंद रहते हैं, जिसमें बहुत कम मानव संपर्क या बातचीत होती है; कम या कोई प्राकृतिक प्रकाश नहीं; और मिलने पर गंभीर बाधाएं, जिसमें कभी भी दोस्तों

या प्रियजनों को छूने में असमर्थता शामिल है । "

अलगाव और विशेषाधिकारों से इनकार करना कई वर्षों से मौत की सजा की सामान्य विशेषताएं रही हैं । वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय के कई मामलों से पता चलता है कि राज्यों ने 1800 के दशक के अंत में मौत की सजा पाए कैदियों पर एकांत कारावास लागू करना शुरू कर दिया था । 1900 के दशक के अंत तक, मौत की सजा पाए कैदियों को अलग-थलग करना आम बात हो गई थी । विद्वानों ने 1997 में बताया कि "जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य की नीति में कुछ परिवर्तनशीलता है, राष्ट्रीय स्तर पर मौत की सजा की स्थिति 'कठोर सुरक्षा, अलगाव, सीमित आवाजाही और कठोर परिस्थितियाँ द्वारा चिह्नित की जाती है । उन्होंने नोट किया कि "35 अधिकार क्षेत्रों में मौत की सजा पाने वाले कैदियों को अलग-अलग कोठरी में रखा गया था । 18 न्यायक्षेत्रों में ये मौत की सजा पाने वाले कैदी औसतन अपनी कोठरी के बाहर दैनिक एक घंटे से भी कम समय की गतिविधि करते हैं, और पाँच अन्य न्यायक्षेत्रों में दैनिक तीन घंटे से भी कम समय की गतिविधि करते हैं । सामाजिक दौरा [37 में से 21 क्षेत्राधिकारों में गैर-संपर्क था । अपराध विज्ञानी रॉबर्ट जॉनसन ने लिखा है कि क्योंकि मौत की पंक्तियों को "उसी तरह बनाए रखा जाता है जैसे वे

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

तब थे जब फ्रांसी से पहले मौत की सजा पर रोक न्यूनतम थी, जो पहले एक संक्षिप्त लेकिन कमजोर करने वाला अनुभव था । ..एक अंतहीन और दर्दनाक प्रतीत होने वाला बन जाता है ।

ग. मृत्युदंड पर निर्णयात्मक शक्ति का आवंटन

मृत्युदंड मौत की सजा का एक मजबूत पहलू बन गया है जो मौत के अपराधों के लिए सजा को बहुत बढ़ाता है । फिर भी अधिकांश राज्यों में मृत्युदंड का उल्लेख मृत्युदंड कानूनों में नहीं किया गया है । अधिकांश विधानसभाएँ इस प्रथा के बारे में चुप रही हैं । इसके बजाय, जेल अधिकारियों द्वारा जेल नीति के मामले में मौत की सजा दी गई है । मृत्युदंड पर अपनी पुस्तक में, गारलैंड लिखते हैं कि मृत्युदंड "एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें कोई विशिष्ट कानूनी अधिकार नहीं है । "

केवल कुछ ही राज्यों में ऐसे कानून हैं जिनमें मृत्युदंड की आवश्यकता होती है । इस लेख के लिए शोध से चार राज्यों-साउथ डकोटा, टेक्सास, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया का पता चला है जो कानून द्वारा मौत की सजा पाए कैदियों के अलगाव को निर्धारित करते हैं और इस प्रकार मौत की पंक्ति के निर्माण की आवश्यकता होती है ।

कुछ अन्य राज्यों ने मौत की सजा पाए कैदियों के लिए प्रतिबंधों को कानून बनाया है, लेकिन मौत की सजा के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, लुइसियाना ने आदेश दिया है कि मौत की सजा पाए कैदियों को "आम जनता, विभाग के कर्मचारियों और संस्थान की सुरक्षा के लिए अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने वाले तरीके से" रखा जाना चाहिए। इंडियाना और मिसिसिपी कानूनों में मौत की सजा पाए कैदियों को अधिकतम सुरक्षा सुविधाओं में रखने की आवश्यकता होती है। व्योमिंग में मौत की सजा पाए कैदियों को एकांत कारावास में रखने की आवश्यकता होती है। और डेलावेयर आगंतुकों को अधिकतम सुरक्षा में कैदियों तक सीमित करता है, जिसमें मौत की सजा पाने वाले कैदी भी शामिल हैं। इन राज्यों में कानूनों में मौत की सजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे भी जेल प्रशासकों को इसे स्थापित करने से मना नहीं करें। और व्योमिंग, लुइसियाना, इंडियाना, मिसिसिपी और डेलावेयर में जेल प्रशासकों ने मौत की पंक्ति बनाने के लिए चुना है। इसी तरह, शेष राज्यों में (जिनके लिए शोध से पता चला है कि मौत की सजा पाए कैदियों के लिए विशेष प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून नहीं है) जेल प्रशासकों द्वारा मौत की सजा स्थापित की गई है। इन राज्यों में वर्जीनिया शामिल है, जिसमें सभी मौत की सजा पाए कैदियों को जेल संचालन

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

प्रक्रियाओं के तहत अलगाव और एकांत कारावास में रखा जाता है। (फोर्थ सर्किट ने हाल ही में वर्जीनिया की मृत्युदंड नीति को बरकरार रखते हुए कहा कि "वर्जीनिया कानून यह आदेश देता है कि मृत्युदंड की सजा मिलने पर मृत्युदंड के लिए दोषी ठहराए गए सभी व्यक्ति स्वचालित रूप से मृत्युदंड तक ही सीमित हो जाएँ।" हालाँकि, यहाँ अदालत का बयान पाठक को गुमराह कर सकता है। वर्जीनिया में, अधिकांश राज्यों की तरह, मौत की सजा पाए कैदियों को रखने के लिए कोई वैधानिक आदेश नहीं है। कई अन्य राज्यों की तरह वर्जीनिया में भी मौत की सजा प्रशासनिक नीति का विषय है।

मौत की सजा वाले इकतीस राज्यों और मौत की सजा पाने वाले कैदियों के साथ अतिरिक्त राज्य में से केवल एक-मिसौरी-ने मौत की सजा को समाप्त करने और सामान्य जेल आबादी में गैर-राजधानी कैदियों के साथ मौत की सजा पाने वाले कैदियों को पूरी तरह से एकीकृत करने का विकल्प चुना है। मिसौरी के जेल प्रशासकों ने मौत की सजा के पक्ष या विपक्ष में किसी भी वैधानिक जनादेश के बिना ऐसा किया, जब एक संघीय अदालत ने एक सहमति आदेश जारी किया जिसमें उन्हें मौत की सजा की स्थितियों में सुधार करने और मौत की सजा पाए कैदियों के लिए अलग-अलग हिरासत स्तर स्थापित करने की आवश्यकता थी। अन्य सभी मृत्युदंड वाले राज्यों में, मौत की सजा पाए कैदी अलग रहते हैं क्योंकि वे फांसी

की प्रतीक्षा करते हैं।

इस प्रकार, लगभग हर मृत्युदंड वाले राज्य में मृत्युदंड के साथ मृत्युदंड भी होता है। हालांकि कुछ राज्य कानूनों में मौत की सजा की आवश्यकता होती है, अधिकांश राज्यों में जेल प्रशासकों ने इसे अपने संचालन नियमों के तहत बनाए रखा है। यह उल्लेखनीय है कि इन राज्यों में, जेल प्रशासकों ने अपने दम पर यह स्थापित किया है कि विद्वान और अदालतें तेजी से मौत की सजा पाए कैदियों के लिए एक "अतिरिक्त सजा" और यहां तक कि "सजा" के रूप में मान्यता देती हैं। इस अनुच्छेद का अगला भाग दिखाएगा कि इसके व्यापक उपयोग के बावजूद, मौत की सजा मौत की सजा का एक अपरिहार्य हिस्सा नहीं है। इसके बजाय, मौत की पंक्ति के लिए एक विकल्प की आवश्यकता होती है- कौन सी सजा उचित है, इसके बारे में मानक विकल्प। मृत्युदंड स्थापित करने के निर्णय की मानक प्रकृति को समझना भाग IV में किए गए इस अनुच्छेद के अंतिम दावे की ओर इशारा करता है: कि जेल प्रशासकों को नहीं, बल्कि विधायिकाओं को यह तय करना चाहिए कि मौत की सजा बरकरार रखी जाए या नहीं।

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

III. मृत्यु पंक्ति के लिए और उसके खिलाफ तर्क

इस लेख में मृत्युदंड की उत्पत्ति, व्यापकता और कानूनी अधिकार का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। यह भाग पूछेगा कि क्या मृत्युदंड आवश्यक है, सजा के चार पारंपरिक उद्देश्यों के आधार पर मृत्युदंड के पक्ष और विपक्ष में तर्कों पर प्रकाश डालते हुए। मौत की सजा को बनाए रखना मुख्य रूप से एक मानक प्रश्न साबित होता है, जिसके लिए आपराधिक सजा के उद्देश्यों और नुकसान को संतुलित करने की आवश्यकता होती है।

उ. क्या दोषी को अक्षम करने के लिए मृत्युदंड आवश्यक है?

मौत की सजा पाने वाले विद्वानों ने मौत की सजा की शर्तों को इस धारणा के लिए जिम्मेदार ठहराया है कि मौत की सजा पाने वाले कैदियों की प्रकृति सुधारात्मक कर्मियों और जेल में अन्य कैदियों पर हमला करने और उन्हें घायल करने की अधिक संभावना रखती है, और यह जोखिम उनके पास 'खोने के लिए कुछ नहीं' होने से बढ़ जाता है। जेल की स्थितियों पर अपने काम में, मोना लिंच ने वर्णन किया है कि कैसे इन धारणाओं ने कुछ राज्यों को मौत की सजा पाने वाले कैदियों को "सुपरमैक्स" कारावास की कठोर और बेहद अलग-थलग

स्थितियों में रखने के लिए प्रेरित किया है। वह लिखती हैं कि "[दंडात्मक प्रशासक] आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक रूप से सुपरमैक्स के उपयोग को उचित ठहराते हैं [उन] कैदियों के लिए जिन्हें 'सबसे खराब से सबसे खराब' के रूप में परिभाषित किया गया है।

कुछ मौत की सजा पाने वाले कैदियों को सजा सुनाने वाली जूरी द्वारा भविष्य में खतरे का खतरा पाया गया है। दो राज्य, टेक्सास और ओरेगन, केवल तभी मौत की सजा की अनुमति देते हैं जब जूरी ने भविष्य में खतरे का निष्कर्ष निकाला हो। वहाँ, राज्य को एक उचित संदेह से परे जूरी के सामने यह साबित करना चाहिए कि "इस बात की संभावना है कि प्रतिवादी हिंसा के अपराधिक कृत्य करेगा जो समाज के लिए एक निरंतर खतरा होगा। "एक अन्य राज्य, वर्जीनिया में, जूरी को या तो एक खतरनाक निष्कर्ष निकालना चाहिए, या वैकल्पिक रूप से एक उचित संदेह से परे यह पता लगाना चाहिए कि किया गया अपराध "अपमानजनक या अनावश्यक रूप से नीच, भयानक या अमानवीय" था।

कई अन्य राज्य घातक निष्कर्षों का उपयोग मृत्युदंड में एक उत्तेजक कारक के रूप में करते हैं।

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

मृत्युदंड में समाज के लिए भविष्य के खतरे के आकलन पर गलत, अन्यायपूर्ण और शायद प्रासंगिक भी नहीं होने के रूप में हमला किया गया है, जहां मृत्युदंड का विकल्प पैरोल के बिना आजीवन कारावास है (समाज के लिए खतरे पर ऐसे समय में विचार किया जाना शुरू हो गया है जब मृत्युदंड का विकल्प पैरोल-योग्य शब्द था)। हालाँकि, उनकी दावा की गई अशुद्धता, अन्याय और संभावित अप्रासंगिकता के बावजूद, भविष्य में इस तरह के खतरनाक निष्कर्षों को न केवल मौत की सजा का समर्थन करने के लिए बल्कि मौत की सजा की स्थितियों का समर्थन करने के लिए उद्धृत किया जाता है। वास्तव में, वर्जीनिया में जेल अधिकारियों ने हाल ही में तर्क दिया कि मौत की सजा पाए कैदी स्पष्ट रूप से कारावास की सख्त शर्तों का समर्थन करते हैं क्योंकि उनकी सजा इस निष्कर्ष पर आधारित होती है कि वे या तो फिर से हिंसक अपराध करेंगे या उनके अपराध विशेष रूप से घृणित थे।

मौत की सजा से कई उल्लेखनीय पलायन ने इस विश्वास में योगदान दिया है कि मौत की सजा पाए कैदी विशेष रूप से खतरनाक हैं और उन्हें नियंत्रित करना कठिन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्युदंड के अपने ऐतिहासिक अध्ययन में, रॉबर्ट बोहम ने पिछले पचास

वर्षों में मौत की सजा पाए कैदियों के कई अच्छी तरह से प्रचारित पलायन का वर्णन किया है: एक महिला, मैरी एरिंगटन, 1969 में फ्लोरिडा की मौत की सजा से भाग गई; 1972 में ओक्लाहोमा की मौत की सजा से छह कैदी भाग गए; 1980 में जॉर्जिया की मौत की सजा से चार कैदी भाग गए; 1984 में वर्जीनिया की मौत की सजा से छह कैदी भाग गए; 1998 में टेक्सास की हंट्सविले जेल से छह कैदियों ने भागने का प्रयास किया (और एक सफल हुआ); और मौत की सजा का एक अन्य कैदी 2005 में ह्यूस्टन की एक काउंटी जेल से भाग गया। ये पलायन बहुत खतरे का कारण बने, जो परेशान करने वाली मीडिया रिपोर्टों से प्रेरित थे। वर्जीनिया में, मेक्लेनबर्ग जेल मौत की सजा से बचने की पराजय के लिए प्रसिद्ध हो गई। इस पलायन ने कई जांचों को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप "कैदियों के लिए नौकरी, मनोरंजन और शैक्षिक अवसरों में वृद्धि" सहित उपायों के माध्यम से बेहतर जेल संगठन और मनोबल के लिए सिफारिशें की गईं। अंततः, हालांकि, वर्जीनिया जेल के अधिकारियों ने हरियाणा बनाम अरुण और अन्य के अच्छे राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें बढ़ाने के बजाय मौत की सजा पाने वाले कैदियों के लिए अवसरों को समाप्त करने का विकल्प चुना। मौत की सजा को ससेक्स। राज्य जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ मौत की सजा पाए कैदी अब एकांत कारावास में रहते हैं। वर्जीनिया के सुधारात्मक अधिकारियों ने 1984 की भागने की घटना का हवाला देते हुए बताया है कि

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

वर्तमान मौत की सजा की सख्ती क्यों आवश्यक है।

हालाँकि, इन भागने से उत्पन्न खतरे के बावजूद, भागने का जोखिम मौत की सजा पाए कैदियों की स्पष्ट रूप से कठोर कारावास की निंदा करने के लिए केवल एक कमजोर कारण प्रदान करता है। हालांकि मौत की सजा पाए कैदियों द्वारा भागने से प्रचार हो सकता है, इस लेख के लिए शोध में कोई अध्ययन या दावा नहीं मिला है जिसमें कहा गया है कि मौत की सजा पाए कैदी कम सजा पाए अन्य हत्यारों की तुलना में अधिक दर से भागने का प्रयास करते हैं, या मौत की सजा पाए कैदियों के भागने के दौरान हिंसा करने की संभावना ऐसे अन्य हत्यारों की तुलना में अधिक होती है। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में मौत की सजा पाए कैदियों के भागने के परिणामस्वरूप किसी तीसरे पक्ष की मौत नहीं हुई है। सभी को फिर से पकड़ लिया गया, सिवाय दो के जो मिलने से पहले ही मर गए थे। मौत की सजा से बचने के जोखिम के संबंध में, 2004 में अरकंसास में हुई एक घटना बता रही है। तीन मिनट के लिए, मौत की पंक्ति के सभी कोठरी के दरवाजे गलती से खोल दिए गए थे। हालांकि जाहिर तौर पर पता था, मौत की सजा पाने वाला कोई भी कैदी अपनी कोठरी से नहीं निकला।

घटना के बाद एक समाचार रिपोर्ट में उद्धृत, अर्कासस जेल प्रणाली की प्रवक्ता ने बताया: "[कैदी वहाँ बैठ गए। वे हिलते नहीं थे। मौत की सजा पाए कैदी जेल में सबसे अच्छा व्यवहार करने वाले कैदी होते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे पास जो डेटा है, वह कम से कम यह बताता है कि मौत की सजा पाने वाला हर कैदी भविष्य में भागने या हिंसा करने की संभावना वाला कैदी नहीं है। राजधानी के कैदियों द्वारा भागने का दावा किया गया जोखिम प्रत्येक मौत की सजा पाए कैदी को स्थायी अलगाव की कठोरता के अधीन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल के और चल रहे साक्ष्य इस सामान्य धारणा को और कम करते हैं कि मौत की सजा पाए कैदी हमेशा असाधारण रूप से खतरनाक होंगे। सबसे अच्छा सबूत मिसौरी जेल प्रणाली से आता है, जिसने मौत की सजा को समाप्त कर दिया और बीस साल पहले अपने अधिकतम सुरक्षा वाले पोटोसी सुधार केंद्र में गैर-राजधानी कैदियों के साथ मौत की सजा पाने वाले कैदियों को एकीकृत किया। हर मौत की सजा पाए कैदी को स्वचालित रूप से भेजने के बजाय मृत्युदंड पर उच्च-सुरक्षा अलगाव में, मिसौरी जेल के अधिकारियों ने संस्थागत हिंसा के जोखिम के लिए प्रत्येक कैदी का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना और तदनुसार हिरासत स्तर निर्धारित करना शुरू कर दिया। पहली बार, संभावित संस्थागत व्यवहार के साक्ष्य (मनोवैज्ञानिक लक्षणों और पिछले जेल व्यवहार

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

जैसे विभिन्न कारकों सहित), केवल मौत की सजा के तथ्य के बजाय, अलगाव में स्थान के लिए मायने रखते थे।

एकीकरण के परिणामस्वरूप, एक दशक के भीतर मिसौरी जेल प्रणाली में मौत की सजा पाए कैदियों में से 84 प्रतिशत (तब बासठ कैदी) को किसी न किसी रूप में सामान्य जनसंख्या आवास में रखा गया था, जिसमें 21 प्रतिशत शामिल थे जिन्हें असाधारण रूप से अच्छे व्यवहार वाले कैदियों के लिए आरक्षित "सम्मान छात्रावास" में रखा गया था। 103 ऑनर्स डॉर्म में कैदी रोल कॉल के दौरान छोड़कर हर समय अपनी कोठरी से बाहर रहते थे। मौत की सजा पाए कैदियों में से केवल पाँच प्रतिशत को दूसरों के लिए जोखिम या अनुशासनात्मक कारणों से अलग कारावास की आवश्यकता थी। मौत की सजा के उन्मूलन ने मौत की सजा पाए कैदियों के जीवन में बहुत सुधार किया, और-मिसौरी सुधार विभाग के वर्तमान निदेशक, जॉर्ज लोम्बार्डी के अनुसार-"संस्थान की सामान्य जलवायु और पर्यावरण" में भी सुधार हुआ।

मुख्यधारा में आने के ग्यारह साल बाद मिसौरी डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस की रिपोर्ट का अध्ययन करते समय, फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक मार्क कनिंघम और थॉमस रेडी ने आपराधिक न्याय के प्रोफेसर जॉन सोरेनसेन की सहायता से कई आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने पाया कि मुख्यधारा के मौत की सजा पाए कैदियों में हिंसक दुराचार करने की संभावना उसी सुविधा में वर्षों की सजा पाए कैदियों की तुलना में काफी कम थी। वास्तव में, मौत की सजा पाए कैदियों के लिए हिंसक कदाचार की दर (और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों के लिए भी (एल. डब्ल्यू. ओ. पी.)) उसी सुविधा में पैरोल-योग्य कैदियों के बीच हिंसक कदाचार की दर का केवल पांचवां हिस्सा था। उम्र और शिक्षा जैसे भविष्यवक्ता चर के लिए लेखांकन के बाद भी, चर मौत की सजा और एल. डब्ल्यू. ओ. पी. कैदियों के हिंसक कदाचार में शामिल होने की संभावना उतनी ही कम थी जितनी कि सजा पाए कैदियों को [पोटोसी सुधार केंद्र] में कारावास की समान शर्तों के तहत रखा गया था। इसके अलावा, मौत की सजा पाए कैदियों में से किसी ने भी अध्ययन अवधि के दौरान भागने का प्रयास नहीं किया, और कनिंघम ने मिसौरी में मौत की सजा पाए कैदी द्वारा भागने के किसी भी प्रयास के बारे में नहीं सुना है।

तथ्य यह है ध्यान आकर्षित करता है कि एल. डब्ल्यू. ओ. पी. और मौत की सजा पाए कैदी दोनों "हिंसक दुराचार में शामिल होने के लिए पैरोल योग्य कैदियों की तुलना में काफी कम थे"। एल. डब्ल्यू. ओ. पी. कैदियों के लिए, मौत की सजा पाए कैदियों की तरह, रिहाई की

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

बहुत कम उम्मीद है। मिसौरी के साक्ष्य इस प्रकार इस दावे को अस्थिर करते हैं कि ऐसे कैदी स्पष्ट रूप से अधिक जोखिम पैदा करते हैं और इसलिए उन्हें अधिक सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए।

कम से कम दो कारक यह समझा सकते हैं कि मुख्यधारा में मौत की सजा पाए कैदी दुराचार की अपेक्षाकृत कम दर क्यों करेंगे। पहला कारण यह है कि जब इन कैदियों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाते हैं तो उन्हें खोने के लिए कुछ मिलता है। जब मौत की सजा पाए कैदियों को स्वचालित रूप से और स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जाता है और मौत की पंक्ति पर अलग-थलग नहीं किया जाता है, तो अलगाव और अलगाव की धमकी का उपयोग उन्हें कदाचार से रोकने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि यह धमकी गैर-राजधानी कैदियों को जेल कदाचार से रोकती है। यह बताएगा कि मिसौरी के मुख्यधारा के कैदियों ने अपेक्षाकृत कम स्तर के हिंसक दुराचार क्यों किए। यह भी समझा सकता है कि उन्होंने भागने का प्रयास क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर उन्हें फिर से पकड़ लिया जाता है तो

परिणामस्वरूप उन्हें एकांत कारावास में लौटने का सामना करना पड़ता है ।

दूसरा कारण यह समझाने में मदद कर सकता है कि मिसौरी अध्ययन में मौत की सजा पाए कैदियों ने कम सजा वाले कैदियों की तुलना में कम हिंसक दुराचार क्यों किया: मौत की सजा पाए कैदी जेल को अलग तरह से देख सकते हैं क्योंकि वे अपने शेष जीवन के लिए वहां रहने की उम्मीद करते हैं । वे जेल में कम समय बिताने की उम्मीद रखने वाले कैदियों की तुलना में जेल अधिकारियों के साथ अच्छी प्रतिष्ठा और अच्छे संबंध स्थापित करने के महत्व को अधिक देख सकते हैं । वे यह मान सकते हैं कि छोटे विशेषाधिकारों का नुकसान, जैसे कि परिवार के साथ संपर्क यात्रा और मनोरंजन के लिए समय बढ़ाना, लंबे समय तक उनके जीवन की गुणवत्ता को नाटकीय रूप से प्रभावित कर सकता है । यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण यह समझा सकता है कि क्यों मौत की सजा सुनाई गई और एल. डब्ल्यू. ओ. पी. कैदी पैरोल-योग्य कैदियों की तुलना में कम हिंसक कदाचार करेंगे, और एल. डब्ल्यू. ओ. पी. कैदी सभी की तुलना में कम से कम हिंसा क्यों करेंगे ।

मिसौरी में मुख्यधारा का अनुभव इस दावे के लिए मजबूत अनुभवजन्य समर्थन प्रदान करता है कि सभी मौत की सजा पाए कैदी जेल हिंसा का अधिक खतरा पैदा नहीं करते हैं । पहले के अध्ययन उस खाते को पुष्ट करते हैं, हालांकि उन्होंने मौत की सजा के उन्मूलन के बाद कैदी आचरण का अध्ययन नहीं किया था । कुछ अध्ययनों से उन कैदियों के लिए हिंसा की अपेक्षाकृत कम दर का पता चला है जो अभी भी मौत की सजा पर थे । अन्य अध्ययनों में मौत

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

की सजा पाए पूर्व कैदियों की हिंसा की दर अपेक्षाकृत कम पाई गई, जिन्हें उनकी मौत की सजा खाली होने के बाद, सामान्य आबादी में कैद किया गया था । मिसौरी अध्ययन पुनरावृत्ति के व्यापक अध्ययनों के साथ भी मेल खाता है, जो दर्शाता है कि दोषसिद्धि का अपराध जेल में हिंसा का एक खराब भविष्यवक्ता है । विशेष रूप से, अध्ययनों ने संकेत दिया है कि "एक हत्या की सजा किसी अन्य अपराध के लिए सजा की तुलना में जेल हिंसा के अधिक जोखिम की भविष्यवाणी नहीं करती है ।" और "शोध में लगातार पाया गया है कि जेल से रिहा किए गए हत्यारों के बीच पुनरावृत्ति की वास्तविक घटना अन्य प्रकार के पैरोलियों की तुलना में बहुत कम है । इसके अलावा, अध्ययनों से पता चला है कि कैदियों द्वारा हिंसा का खतरा उम्र बढ़ने के साथ काफी कम हो जाता है । कई मौत की सजा वाले कैदी काफी पुराने हैं; हाल ही में एक सरकारी रिपोर्ट में साठ या उससे अधिक उम्र के 350 से अधिक मौत की सजा वाले कैदियों की गिनती की गई है । पिछले दशकों में, सैकड़ों लोगों की मौत फांसी की प्रतीक्षा में हुई है । जैसे-जैसे फांसी की सजा पाए कैदियों की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे

सुरक्षा कारणों से मौत की सजा पर उनका स्थायी अलगाव कम और कम उचित हो जाता है। साक्ष्यों का एक संग्रह इस प्रकार इस दावे का समर्थन करता है कि मौत की सजा पाए कैदी एक स्पष्ट मामले के रूप में असाधारण सुरक्षा खतरे पैदा नहीं करते हैं।

इस बढ़ते साक्ष्य ने मौत की सजा के लिए खतरनाक तर्क को कम कर दिया है। सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए मृत्युदंड को स्वतः और स्थायी रूप से मृत्युदंड पर रखने के लिए निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होती है। मौत की सजा पाने वाले अपराधियों के व्यक्तिगत आकलन यह निर्धारित करने का एक तरीका प्रदान करते हैं कि किन कैदियों को अधिक प्रतिबंधात्मक कारावास की आवश्यकता है-मूल्यांकन जो गैर-राजधानी कैदियों के लिए नियमित रूप से किए जाते हैं।

लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मौत की सजा कोई वैध दंडात्मक उद्देश्य पूरा नहीं करती है। अन्य पारंपरिक सजा उद्देश्यों के लिए-पुनर्वास, प्रतिशोध और निवारण-अभी भी मृत्यु पंक्ति द्वारा सेवा की जा सकती है। सजा के इन अन्य उद्देश्यों पर विचार किए बिना, कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि मौत की सजा का मौत की सजा में कोई वैध स्थान नहीं है। अनुच्छेद अब इस बात पर विचार करेगा कि क्या मौत की सजा पुनर्वास के उद्देश्य को पूरा कर सकती है।

ख. क्या दोषी के पुनर्वास के लिए मौत की पंक्ति आवश्यक है?

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

ऐतिहासिक रूप से, राज्यों को उम्मीद थी कि फांसी से पहले के कारावास से अपराधी के पुनर्वास में मदद मिलेगी। औपनिवेशिक दिनों में, फांसी की सजा पाने वाले कैदियों को उनके अपराधों और संभावित दंड पर ध्यान देने में सक्षम बनाने के लिए, और पादरी वर्ग की यात्राओं की मदद से, पश्चाताप और पश्चाताप व्यक्त करने के लिए जानबूझकर कुछ हफ्तों तक फांसी में देरी की जाती थी। इस प्रकार पूर्व-निष्पादन कारावास अपराधी की आत्मा के पुनर्वास के लिए बनाया गया था। पूर्व-निष्पादन कारावास का यह उद्देश्य 1839 में मैसाचुसेट्स के मुख्य न्यायाधीश लेमुएल शाँ के शब्दों में देखा जा सकता है, जब उन्होंने एक प्रतिवादी को चेतावनी दी थी कि वह अपने शेष समय का उपयोग "उस महान परिवर्तन की तैयारी में करने के लिए कर रहा है जो आपका इंतजार कर रहा है। पुनर्वास के ऐतिहासिक उद्देश्य के कुछ अवशेष वर्तमान मौत की सजा नीति में दिखाई देते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों ने अमेरिकी दंड नीति में धार्मिक उद्देश्यों को काफी हद तक विस्थापित

कर दिया है। कुछ क़ानून अभी भी स्पष्ट रूप से पादरी द्वारा मौत की सजा पाए कैदियों से मिलने का प्रावधान करते हैं। और कुछ जेल प्रशासकों ने मौत की सजा को एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की है जो कैदियों के विचारों को भगवान की ओर आकर्षित करता है। साहित्य और पुस्तकों में मौत की सजा पर प्रसिद्ध धर्म परिवर्तनों को दर्शाया गया है।

हालाँकि, पूर्व-निष्पादन कारावास का ऐतिहासिक पुनर्वास उद्देश्य अब मौत की सजा के लिए बहुत कम कारण प्रदान करता है। पूर्व-निष्पादन कारावास बहुत लंबे समय तक रहता है जो उस अस्थायी दबाव को प्रदान करता है जिसे ऐतिहासिक रूप से पश्चाताप को बढ़ावा देने के लिए देखा गया था। 1839 में, न्यूयॉर्क के मंत्री जॉन मैकलियोड ने पूर्व-निष्पादन कारावास की एक छोटी अवधि के महत्व को समझाया:

आइए हम मन की प्रकृति और पाप की छल के बारे में जो जानते हैं, उससे उचित रूप से तर्क न करें कि अपराधी अपने मन की सभी शक्तियों को अपने भगवान से मिलने की तैयारी के काम में लगाने की अधिक संभावना रखता है। जब वह जानता है कि उसके दिन गिने गए हैं, जब वे उसे अनिश्चित काल के लिए लंबे समय तक दिखाई देते हैं?

आज, जिन कैदियों को फांसी दी जाती है, वे औसतन डेढ़ दशक तक मौत की सजा काटते हैं-और मौत की सजा पाए अधिकांश कैदियों को फांसी नहीं दी जाती है। फांसी से पहले के कारावास का धार्मिक रूप से उन्मुख उद्देश्य जेल की विशेष स्थितियों को सही ठहराता प्रतीत होता है जो कैदी को उसकी फांसी से तुरंत पहले की सीमित अवधि के लिए उसके

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

शाश्वत भाग्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी।

एक विद्वान ने मौत की सजा पाए कैदियों को अलग-अलग कैद में रखने के लिए एक वैकल्पिक, धर्मनिरपेक्ष पुनर्वास उद्देश्य का सुझाव दिया है। अपराध विज्ञानी रॉबर्ट जॉनसन ने "मानवीय मौत की सजा" के लिए तर्क दिया है, जहां मौत की सजा पाए कैदियों को अन्य कैदियों की तुलना में अधिक देखभाल का व्यवहार मिलता है। उनका तर्क है कि जेलों में मौत की सजा पाए कैदियों के लिए एक विशेष प्रकार का कारावास प्रदान किया जाना चाहिए जो फांसी से पहले की देरी के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान को कम करेगा और उन्हें सम्मानजनक मौत के लिए तैयार करेगा। उनका तर्क है कि मौत की सजा पाए कैदी "राज्य के हाथों मरने की प्रक्रिया में व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का एक वर्ग जो घातक रूप से बीमार रोगियों के समान और मानवीय देखभाल के योग्य है। वह मौत की सजा को एक प्रकार के

धर्मशाला के रूप में देखता है। मौत की सजा के बारे में जॉनसन की दृष्टि के लिए राज्यों को गैर-राजधानी कैदियों की तुलना में मौत की सजा पाए कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार करने की आवश्यकता होगी; यह मौत की सजा के निर्माण को उचित ठहराता है, लेकिन आज हम जो कठोर मौत की सजा देखते हैं, उससे बहुत अलग है। कई विद्वानों ने तर्क दिया है कि मौत की सजा जो आज मौजूद है, पुनर्वास के बजाय घटती जाती है। मोना लिंच मौत की सजा की कठोर स्थितियों को "पुनर्वास के बाद," अपशिष्ट प्रबंधन "नई दंडात्मक व्यवस्था के हिस्से के रूप में वर्णित करती हैं। लिंच लिखते हैं कि मौत की सजा की स्थिति "शाब्दिक रूप से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से समृद्ध मनुष्यों से मरने की प्रतीक्षा करने वालों को एक प्रकार के अछूत विषाक्त कचरे में बदल रही है जिसे केवल इसके अंतिम निपटान तक सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है।"

जेल प्रशासकों के लिए जो मौत की सजा की नीति तय करते हैं, पुनर्वास व्यर्थ लग सकता है। ऊपर उल्लिखित प्रीटो मामले में वर्जीनिया की मौत की सजा की शर्तों पर मुकदमे में, राज्य के जेल अधिकारियों ने इस आधार पर कि वे सीमित जेल संसाधनों के कम योग्य हैं के स्पष्ट इनकार का बचाव किया। क्योंकि वे कभी भी समाज में फिर से प्रवेश नहीं करेंगे, मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों को काम और शैक्षिक विशेषाधिकार दिए जाते हैं। यह उपयोगितावादी तर्क उन कैदियों के मानव विकास को बहुत कम या कोई महत्व नहीं देता है जिन्हें फांसी के लिए चिह्नित किया जाता है, लिंच के शब्दों में, ऐसे कैदियों को मानव "अपव्यय" के रूप में माना जाता है।

लेकिन यह तर्क कि मौत की सजा पाए कैदियों का पुनर्वास व्यर्थ हो जाता है क्योंकि वे कभी

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

भी सामान्य समाज या जेल समाज में फिर से प्रवेश नहीं करेंगे, यह मानता है कि मौत की सजा पाए कैदियों को फांसी दी जाएगी। यह सच नहीं है। मौत की सजा पाए कई कैदियों को फांसी नहीं दी जाएगी। ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स के हालिया रिकॉर्ड बताते हैं कि 1976 और 2013 के बीच मौत की सजा पाए चालीस प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अदालत के फैसलों या परिवर्तनों के कारण मौत की सजा से हटा दिया गया था। जेम्स लिबमैन, जेफरी फेगन और वैलेरी वेस्ट द्वारा किए गए एक पहले और अधिक विस्तृत अध्ययन में पाया गया था कि 1973 से 1995 तक के आधे से अधिक मृत्युदंड को पूर्वाग्रहपूर्ण त्रुटि के आधार पर उलट दिया गया था। मौत की सजा पाए कुछ कैदियों को जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। बहुत कम संख्या को दोषमुक्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार शुरू में मौत की सजा पाए इन कैदियों में से कुछ समाज में फिर से

प्रवेश करेंगे-कम से कम बड़े जेल समुदाय में। यह दावा कि मौत की सजा पाए कैदियों के पुनर्वास को बर्बाद कर दिया जाता है क्योंकि वे कभी भी समाज में फिर से प्रवेश नहीं करेंगे, न केवल नैतिक रूप से संदिग्ध है, बल्कि अक्सर तथ्यात्मक रूप से गलत है। किसी भी मौत की पंक्ति को जो बरकरार रखा जाता है, उसे अपने कैदियों को मानव समुदाय में अंततः पुनः प्रवेश की संभावना के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसके कई कैदी ऐसा करेंगे। इस प्रकार, पुनर्वास आज प्रचलित मृत्युदंड की दुर्बल करने वाली स्थितियों के लिए कोई औचित्य प्रदान नहीं करता है।

ग. क्या प्रतिशोधात्मक न्याय के लिए मृत्युदंड आवश्यक है?

प्रतिशोधात्मक सजा के समर्थक पुनर्वासात्मक मौत की पंक्ति के विचार को देख सकते हैं- विशेष रूप से "मानवीय मौत की पंक्ति" जिसे जॉनसन-गहरा अन्यायपूर्ण मानते हैं। प्रतिशोधात्मक सजा के एक स्व-घोषित समर्थक रॉबर्ट ब्लेकर हैं, जो तर्क देते हैं कि न्याय के लिए कठोर मौत की सजा की शर्तों की आवश्यकता होती है। ब्लेकर के अनुसार, मौत की सजा की मौजूदा स्थितियां बहुत अधिक उदार हैं। अपनी 2013 की पुस्तक, द डेथ ऑफ पनिशमेंट में, ब्लेकर ने मौत की सजा पर जीवन का वर्णन किया है। उनकी पुस्तक विशेष रूप से फ्लोरिडा और टेनेसी में कैदियों के जीवन पर केंद्रित है। और फ्रांसी पर उन्होंने साक्षात्कार लिया। ब्लेकर ने मौत की सजा पाए कैदियों को खेल खेलते और टेलीविजन देखते हुए देखने का वर्णन किया है। वह मौत की सजा पाए कैदियों के जीने के तरीके और पीड़ितों को पीड़ित करने के तरीके की तुलना करते हैं। वीभत्स विवरण में, ब्लेकर बताते हैं कि कैसे फ्लोरिडा में मौत की सजा पाए एक कैदी, डैनी रोलिंग ने निर्दयता से बलात्कार

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

किया, हत्या कर दी, और एक युवा विश्वविद्यालय की छात्रा को मार डाला और चार अन्य छात्रों की हत्या कर दी। वह बताता है कि कैसे फ्लोरिडा में मौत की सजा पाए कैदी डेविड कीन ने एक आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसका जूते के फीते से गला घोट दिया और उसे, जो अभी भी जीवित है, एक नदी में फेंक दिया। और वह वर्णन करता है कि कैसे टेनेसी में मौत की सजा पाए एक कैदी डेरिल होल्टन अपने संदेहहीन बच्चों को अपने गैराज में ले गया, उन्हें एक बार में दो कतार में खड़ा कर दिया, और उन्हें गोली मार दी। ब्लेकर के लिए, इन कैदियों के अपराधों के आलोक में मौत की सजा लगभग इतनी कठोर नहीं है। ब्लेकर तर्क देते हैं कि प्रतिशोधात्मक न्याय के लिए ऐसी सजा की आवश्यकता होती है जो अपराध के लिए कहीं अधिक उपयुक्त हो। उन्होंने एक "मॉडल"

मौत की सजा के क़ानून का प्रस्ताव रखा है जिसमें मौत की सजा पाए कैदी "स्थायी दंडात्मक अलगाव" में रहते हैं:

जिन लोगों को मरने की सजा सुनाई जाती है, उन्हें स्थायी रूप से एक अलग जेल [विंग] में रखा जाएगा, उनकी दैनिक स्थिति उन कैदियों से बेहतर नहीं होगी जो पहले से ही सबसे खराब जेल उल्लंघन के लिए दंडात्मक या प्रशासनिक अलगाव के अधीन हैं। विशेष रूप से, संवैधानिक सीमाओं के भीतर, जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनके पास केवल न्यूनतम संवैधानिक रूप से अनिवार्य व्यायाम, मनोरंजन, फोन कॉल या शारीरिक संपर्क होगा। उन्हें किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक खेल की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनका एकमात्र भोजन पौष्टिक रूप से पूर्ण और स्वादहीन होगा। उनके पीड़ितों की तस्वीरें उनकी कोठरी में, पहुंच से बाहर, स्पष्ट रूप से विशिष्ट स्थानों पर पोस्ट की जानी चाहिए।

ब्लेकर ने कैदियों को संभालना आसान बनाने और इस तरह उनके अपने जीवन को आसान बनाने की स्वार्थी इच्छा से मौत की सजा पाए कैदियों को बहुत अधिक विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए जेल अधिकारियों की आलोचना की। उनके दृष्टिकोण से, मौत की सजा पाए अपराधियों के साथ उदार व्यवहार अन्यायपूर्ण रूप से उदार होता है और अपराध की प्रकृति को सजा के अनुभव से पूरी तरह से अलग कर देता है।

ब्लेकर द्वारा वर्तमान मौत की सजा की स्थितियों को उदार के रूप में चित्रित करना चौंका देने वाला और मौत की सजा की स्थितियों के प्रतिनिधित्व के साथ असंगत लगता है जो इतने सारे विद्वानों और अध्ययनों द्वारा असाधारण रूप से कठोर प्रस्तुत किया गया है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है जहां कैदियों को एकांत कारावास में रखा जाता है या अधिकांश मानवीय बातचीत से इनकार

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

किया जाता है। अपनी पुस्तक में, ब्लेकर ने मुट्ठी भर राज्यों में अपने अनुभवों का वर्णन किया है जो मौत की सजा पाए कैदियों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ व्यायाम करने का अवसर भी शामिल है, जो कई अन्य मौत की सजा वाले राज्यों में नहीं दिए जाते हैं। कम से कम ग्यारह अन्य मृत्युदंड वाले राज्य बताते हैं कि वे मौत की सजा पाए कैदियों को किसी भी सामूहिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं। एरिजोना सहित कुछ राज्य अपने मौत की सजा पाए कैदियों को सुपरमैक्स कारावास में रखते हैं, जैसा कि लिंच ने वर्णित किया है। ब्लेकर को यह जानकर खुशी हो सकती है कि, कम से कम कुछ राज्यों में, प्रतिशोधात्मक न्याय के लिए उनके तर्क अधिकांश यथास्थिति

के बचाव हैं ।

हालांकि मौत की कठोर सजा की शर्तों के लिए ब्लेकर की मांगें चरम लग सकती हैं, जेल की कठोर स्थितियों के लिए प्रतिशोधात्मक औचित्य नए नहीं हैं । अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, दंड प्रणाली के कुछ आलोचकों ने मृत्युदंड के बदले में जेल की कठोर स्थितियों की वकालत की; उन्होंने राज्यों से कैदियों को दूरदराज के स्थानों पर सील करने का आग्रह किया जहां कैदियों को बिना किसी आगंतुक के अपने अपराधों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया जाएगा । ब्लेकर बस चाहता है कि कुछ हत्यारों को कठोर शर्तों और मौत दोनों की सजा मिले । ब्लेकर मौत की सजा के बारे में एक विशेष रूप से कठोर दृष्टि प्रदान करता है; अन्य प्रतिशोधात्मक न्याय अधिवक्ता चाहते हैं कि मौत की सजा कठोर हो, लेकिन इतनी गंभीर न हो, शायद पुनर्वास के साथ प्रतिशोधात्मक न्याय के उद्देश्यों को जोड़ना चाहते हैं । स्टेफानोस बिबास ने कैदियों को उनके अपराधों द्वारा किए गए कुछ नुकसान की मरम्मत के लिए पुनर्स्थापनात्मक न्याय में शामिल करने की वकालत की है, लेकिन साथ ही उन्होंने पुनर्स्थापनात्मक न्याय के अन्य अधिवक्ताओं की आलोचना की है जो "आपराधिक न्याय के पारंपरिक लक्ष्यों और प्रक्रियाओं को मिटा देंगे" और जो "प्रतिशोध के लिए प्रतिशोध को व्यर्थ मानते हैं ।" उन्होंने लिखा है:

सजा से चोट लगनी चाहिए । सजा का दंड गलत काम करने वाला और पीड़ित को दोषमुक्त ठहराना की निंदा करते हुए एक स्पष्ट संदेश भेजता है । यह समाज के प्रति अपराधी के ऋण का भुगतान करता है । यह अपराधियों और अन्य लोगों को सिखाता है कि वे दूसरों को चोट न पहुँचाएँ, गर्वित गलत करने वालों को नीचा दिखाएँ । बहाली और जुर्माना जेल के पूरक हो सकते हैं और शायद इसकी आवश्यकता को कम कर सकते हैं । लेकिन क्योंकि उनमें निंदा और दर्द की कमी होती है, वे बहुत नरम संदेश भेजते हैं, गलत को नजरअंदाज

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

करते हैं और इसे बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं । अपराधियों को प्रायश्चित्त करने, विनम्र होने, पीड़ित होने की आवश्यकता है । यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो अपराधी कोई सबक नहीं सीखता है और पीड़ित और जनता कभी भी न्याय होते नहीं देखते हैं, जिससे वे असंतुष्ट हो जाते हैं ।

यदि राज्य कठोर मौत की सजा की शर्तों को केवल प्रतिशोध के रूप में देखते हैं, तो वे फिर भी बहाली और सुलह को प्रोत्साहित करने के लिए कैदियों के अलगाव को सीमित कर सकते हैं । उदाहरण के लिए, राज्य मौत की सजा पाए कैदियों को पश्चाताप व्यक्त करने के

लिए अपने पीड़ितों के परिवारों से मिलने की अनुमति दे सकते हैं (कुछ ऐसा जो कई वर्तमान यात्रा नीतियों के तहत विचार नहीं किया गया है)। या राज्य मौत की सजा पाए कैदियों को कार्य कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति केवल तभी दे सकते हैं जब वे अपने पीड़ितों के परिवारों को अपना मुआवजा भेजने के लिए सहमत हों। दूसरे शब्दों में, मृत्युदंड की सजा की प्रतिशोधात्मक दृष्टि ब्लेकर द्वारा प्रस्तावित स्थायी दंडात्मक अलगाव की अखंड कठोरता को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता नहीं है।

मृत्युदंड की स्थितियों के बारे में अन्य शैक्षणिक और न्यायिक विमर्शों में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत सामने आता है। यहां तक कि जब मौत की सजा की शर्तों के लिए सुरक्षा तर्कों की बात की जाती है, तो अदालतें कभी-कभी राजधानी कैदियों के नैतिक रेगिस्तान का विज्ञापन करती हैं। उदाहरण के लिए, न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस ने लिखा है: न्यायमूर्ति [जॉन पॉल] स्टीवंस जिस तरह से [मौत की सजा पाए कैदी] को कैद किया गया है, उसके "अमानवीय प्रभावों" की आलोचना करते हैं, लेकिन वह इस बात पर विचार करने के लिए कभी नहीं रुकते हैं कि क्या कुछ कैदियों को प्रतिबंधात्मक कारावास में रखने का कोई वैध दंडात्मक कारण है।

न्यायमूर्ति स्टीवंस उन अपराधों की वीभत्स प्रकृति को ध्यान में रखने से पूरी तरह इनकार करते हैं जो राज्यों को वैध रूप से मृत्युदंड और इसे लागू करने के लिए जूरी को अधिकृत करने के लिए प्रेरित करते हैं।

..... यह अपराध है-न कि जूरी द्वारा दी गई सजा या याचिकाकर्ता के निष्पादन में देरी-जो "अस्वीकार्य रूप से क्रूर" था।

ब्लेकर की तरह, न्यायमूर्ति थॉमस कठोर मृत्युदंड की स्थितियों के न्याय के अपने मूल्यांकन में मृत्युदंड के कैदी के मृत्युदंड के अपराध का आह्वान करते हैं। हाल के एक मामले में,

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

उन्होंने इस चिंता का जवाब दिया कि एक मौत की सजा पाए कैदी को दशकों से एकांत कारावास में रखा गया था, यह देखते हुए कि कैदी के "आवास उन लोगों की तुलना में अधिक विशाल हैं जिनमें उसके पीड़ित अब आराम करते हैं।" यह विचार कि प्रतिशोधात्मक न्याय कठोर मौत की सजा की शर्तों का समर्थन करता है, निचली अदालत के फैसलों में भी दिखाई दिया है, जैसे कि पेंसिल्वेनिया में मौत की सजा के बारे में एक राय जिसमें थर्ड सर्किट ने कहा: "[हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि पेनसिल्वेनिया की मौत की पंक्तियों पर शर्तों की समग्रता अपराध की गंभीरता के लिए 'घोर अनुपातहीन' सजा का गठन करती

है ।

लेकिन सभी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि प्रतिशोध मौत की सजा पर कठोर कारावास को उचित ठहराता है । रसेल किरस्टोफर का तर्क है कि पर्याप्त मौत की सजा कारावास सजा के पूर्ण अनुभव को प्रतिशोधात्मक रूप से अत्यधिक बना सकता है । यदि कोई प्रतिशोध के आधार पर मृत्युदंड का बचाव करता है, तो उनका तर्क है कि कोई व्यक्ति मृत्युदंड को कम से कम कुछ मृत्युदंड के अपराधों के समानुपाती के रूप में देखता है । मृत्युदंड कारावास तब सजा जोड़ता है और मृत्युदंड को एक प्रतिशोधात्मक गणना के तहत असमान रूप से कठोर बनाता है ।

लेकिन किरस्टोफर का यह तर्क कि मृत्युदंड कारावास प्रतिशोधात्मक न्याय के साथ असंगत है, यह मानता प्रतीत होता है कि फांसी अधिकतम सजा है जिसे एक प्रतिशोधवादी मृत्युदंड हत्या के लिए उचित समझेगा । यह स्पष्ट नहीं लगता है, कम से कम कुछ सबसे गंभीर राजधानी हत्याओं के लिए जैसे कि ब्लेकर वर्णन करता है । यदि कुछ मृत्युदंड अपराध-और केवल कुछ-कठोर मृत्युदंड की शर्तों के साथ-साथ निष्पादन को सही ठहराने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं, तो इस तरह की अतिरिक्त सजा उन अपराधियों तक सीमित हो सकती है जिन्होंने बहुत गंभीर मृत्युदंड हत्याएं की हैं (विशिष्ट उत्तेजना के जूरी निष्कर्षों के आधार पर) । इस तरह से कठोर मृत्युदंड की शर्तों को सीमित करना मृत्युदंड के अपराधों की एक श्रृंखला के अनुरूप प्रतिशोधात्मक दंड को मापने का एक तरीका हो सकता है ।

हालाँकि, कठोर मौत की सजा की स्थितियों के लिए प्रतिशोधात्मक औचित्य अभी भी एक महत्वपूर्ण चिंता पैदा करेगा । समस्या मृत्युदंड की त्रुटि की असाधारण रूप से उच्च दरों में निहित है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्याय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा प्रदान किए गए वार्षिक मृत्युदंड के आंकड़ों से पता चलता है कि मौत की सजा पाए चालीस प्रतिशत से

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

अधिक कैदियों को मौत की सजा से हटा दिया गया है । उन कैदियों के लिए जो दोषमुक्त हैं या आजीवन या कम अवधि के लिए नाराज हैं, कठोर मौत की सजा की स्थितियों के कारण होने वाली अतिरिक्त पीड़ा अन्यायपूर्ण होगी ।

अनुचित रूप से मृत्युदंड के लिए भेजे गए व्यक्तियों द्वारा अन्यायपूर्ण पीड़ा की समस्या को उन अपराधों के लिए मृत्युदंड के चयनात्मक उन्मूलन से कम किया जा सकता है जिसमें उच्चतम स्तर की दोषसिद्धि शामिल नहीं है (उदाहरण के लिए, ब्लेकर भी करता है) या मौत

की सजा की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब एक जूरी ने कई उत्तेजक कारकों को पाया हो। सजा देने में त्रुटि के एक अध्ययन से पता चला कि एक जूरी द्वारा पाए गए प्रत्येक अतिरिक्त उत्तेजक कारक के लिए, मृत्युदंड को उलट दिए जाने की संभावना में पंद्रह प्रतिशत की कमी आई। यदि यह उपाय सही है, तो सजा देने की त्रुटि को कम किया जा सकता है यदि अभियोजक एक राजधानी जूरी के सामने अधिक संख्या में उत्तेजक कारकों को साबित करते हैं (और अब मौत की सजा का पीछा नहीं करते हैं यदि जूरी को केवल कम संख्या में उत्तेजक कारक मिलते हैं)।

शायद कठोर मौत की सजा की शर्तों के संभावित अन्याय को कम करने का एक और तरीका यह होगा कि उन्हें राज्य अपीलीय और संपार्श्विक समीक्षा पर मौत की सजा को बरकरार रखने के बाद ही लागू किया जाए। लिबमैन, फेगन और वेस्ट के अध्ययन के अनुसार, अधिकांश सजा देने में त्रुटि राज्य अदालत की समीक्षा के दौरान पाई जाती है। इस प्रकार मौत की सजा पाए कैदियों को मौत की सजा देने के लिए राज्य अदालत की समीक्षा के अंत तक प्रतीक्षा करके कठोर मौत की सजा की स्थितियों के माध्यम से अन्यायपूर्ण सजा के जोखिम को कम किया जा सकता है। लेकिन चूंकि संघीय अदालतें भी सजा सुनाने में त्रुटि पाती हैं, इसलिए अन्यायपूर्ण रूप से कठोर मौत की सजा की स्थितियों की समस्या को कम करने के लिए राज्यों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि राज्य और संघीय दोनों अदालतें अपनी समीक्षा पूरी नहीं कर लेती हैं। फिर, हालांकि बाद की जांच में अभी भी वास्तविक निर्दोषता का सबूत मिल सकता है, मौत की सजा पर अन्यायपूर्ण नियुक्ति का जोखिम कम होगा।

हालांकि, जब तक ऐसा कोई समाधान नहीं मिल जाता है, तब तक मृत्युदंड की त्रुटि की उच्च घटना प्रतिशोध के आधार पर लगाई गई कठोर मृत्युदंड की शर्तों के न्याय के लिए एक गहरी चुनौती प्रस्तुत करती है। इस प्रकार प्रतिशोधात्मक सिद्धांत न केवल मृत्युदंड के पक्ष और विपक्ष में बल्कि मृत्युदंड के पक्ष और विपक्ष में भी तर्क प्रदान करता है।

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

D. क्या दूसरों को अपराध से रोकने के लिए मृत्युदंड आवश्यक है?

जो लोग यह नहीं मानते हैं कि प्रतिशोधात्मक न्याय के लिए अपने आप में कठोर मौत की सजा की शर्तों की आवश्यकता होती है, फिर भी वे पा सकते हैं कि सामान्य प्रतिरोध के लिए ऐसी शर्तों की आवश्यकता होती है (न्यायसंगत दंड द्वारा अनुमत सीमा के भीतर)। वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य निवारक के साथ-साथ प्रतिशोधात्मक

उद्देश्य के लिए कठोर मौत की सजा की शर्तें लगा सकते हैं। 1890 में, सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सजा पाए कैदियों को एकांत कारावास की आवश्यकता वाले एक कानून को "सबसे महत्वपूर्ण और दर्दनाक चरित्र की एक अतिरिक्त सजा" के रूप में वर्णित किया, जिसे "[कैदियों] को मानव जाति के सबसे खराब अपराधों की न्यायसंगत सजा के उदाहरण के रूप में चिह्नित करने के लिए" बनाया गया था।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निरोध अब मौत की सजा के अधिकांश समर्थकों को दृढ़ता से प्रेरित नहीं कर सकता है और मौत की सजा के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं कर सकता है। नवीनतम गैलप सर्वेक्षण से पता चला है कि केवल छह प्रतिशत अमेरिकियों ने कहा कि वे निरोध के आधार पर मृत्युदंड का समर्थन करते हैं, जब समर्थकों को उन आधारों की सूची दी गई थी जिनमें से चुनना है। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि आज लगभग आधे लोगों का मानना है कि मौत की सजा को रोका जा सकता है जैसा कि लोगों ने 1985 में किया था। कुछ शोध बताते हैं कि वास्तव में मृत्युदंड नहीं रोकता है, लेकिन इन निष्कर्षों का अन्य अध्ययनों द्वारा विरोध किया जाता है।

शायद निवारक तर्क अब कई मृत्युदंड समर्थकों को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि बहुत कम व्यक्ति जो मृत्युदंड के अपराध करते हैं, उन्हें वास्तव में फांसी दी जाती है। लेकिन भले ही फांसी असंभव हो, मौत की सजा की वास्तविक सजा नहीं है। सामान्य जेल आबादी में मौत की सजा पर जीवन को जीवन से कहीं बदतर बनाने से दूसरों को बड़े अपराध से रोकने में मदद मिल सकती है। निवारक प्रभाव की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, और यह इस बारे में सबूत पर निर्भर करता है कि क्या संभावित अपराधी जानते हैं कि किन अपराधों में मौत की सजा होती है और क्या वे लागतों और लाभों को तर्कसंगत रूप से तौलेंगे। लेकिन यह सोचना कम से कम प्रशंसनीय लगता है कि जेल की कठोर स्थितियों का कुछ मामूली निवारक प्रभाव हो सकता है।

क्या इस तरह के मामूली प्रतिरोध को प्राप्त करने से सभी मौत की सजा पाए कैदियों पर

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

कठोर मौत की सजा की शर्तों को लागू करना उचित होगा, यह एक अलग सवाल और एक संभावित समस्या पैदा करता है। पूंजीगत मामलों में व्युत्क्रम दर असाधारण रूप से अधिक होती है। गलती से मौत की सजा पाने वाले कैदियों के लिए, मौत की सजा कारावास उनकी अनुचित रूप से लगाई गई सजा को बढ़ाता है। इस प्रकार निरोध के उद्देश्य कठोर मौत की सजा की शर्तों के लिए तर्क को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब कोई एक

मानक मामले के रूप में, अनुचित रूप से मौत की सजा पाए कैदियों को अन्यायपूर्ण अतिरिक्त नुकसान के जोखिम को स्वीकार करता है।***

मृत्युदंड के लिए सजा के उद्देश्यों की पूर्ववर्ती चर्चा से पता चलता है कि मृत्युदंड को बनाए रखने के लिए मानक विकल्पों की आवश्यकता होती है। मौत की सजा के लिए प्रशासनिक तर्क, इन दावों पर आधारित है कि मौत की सजा पाने वाले कैदी विशेष रूप से मिसौरी के मौत की सजा के उन्मूलन का अध्ययन हैं। सुरक्षा कारणों से मौत की पंक्ति बनाए रखना आवश्यक नहीं है। तथ्य यह है कि कुछ मौत की सजा पाने वाले कैदी असाधारण रूप से खतरनाक होते हैं, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी मौत की सजा पाने वाले कैदी स्थायी अलगाव की कठोरता को सहन करें। मिसौरी के अनुभव से पता चला है कि व्यक्तिगत मूल्यांकन का उपयोग मौत की सजा पाए कैदियों के लिए उचित हिरासत स्तर निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि अन्य, गैर-राजधानी कैदियों के साथ किया जाता है।

हालाँकि, मौत की सजा को अभी भी अन्य सजा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देखा जा सकता है। प्रतिशोध और निरोध के उद्देश्य कठोर मौत की सजा की स्थितियों को बनाए रखने के लिए संभावित कारण प्रदान करते हैं, और शायद उन्हें और अधिक गंभीर बनाने के लिए। कठोर सजा के कुछ समर्थक दंडात्मक मौत की सजा की शर्तों का समर्थन कर सकते हैं, जैसा कि रॉबर्ट ब्लेकर करते हैं। अन्य लोग मान सकते हैं कि मृत्युदंड के अपराधी ब्लेकर द्वारा प्रस्तावित शर्तों की तुलना में कम कठोर शर्तों के हकदार हैं, लेकिन फिर भी गैर-राजधानी कैदियों की तुलना में अधिक कठोर शर्तों का अनुभव करते हैं। फिर भी अन्य लोग मान सकते हैं कि जूरी को यह तय करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए कि क्या कुछ विशेष रूप से जघन्य हत्यारे मौत की सजा के हकदार हैं-शायद, लेकिन आपराधिक हत्यारों को नहीं।

अंततः, मृत्युदंड को बनाए रखने के निर्णय के लिए सजा के उद्देश्यों के बारे में निर्णय की आवश्यकता होती है और सजा के उद्देश्यों के हित में संभावित रूप से अयोग्य पीड़ित समाज

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

को कितना प्रभाव डालना चाहिए। इस अनुच्छेद के अगले भाग में तर्क दिया जाएगा कि ये मानक निर्णय जेल प्रशासकों के बजाय विधायिकाओं द्वारा किए जाने चाहिए।

I. कैदियों के रूप में बर्बर

मौत की सजा पाए कैदियों को अलग करने से मौत की सजा पाए कैदियों की छवि खतरनाक

बर्बर के रूप में मजबूत होती है। न्यायमूर्ति ब्रेनन ने आम मानवता के इनकार को मृत्युदंड के एक अपरिहार्य पहलू के रूप में देखा। फुरमैन बनाम जॉर्जिया में सहमति व्यक्त करते हुए, उन्होंने लिखा कि "उन्होंने गणना की कि राज्य द्वारा एक इंसान की हत्या में, अपने स्वभाव से, निष्पादित व्यक्ति की मानवता का खंडन शामिल है।" उन्होंने तर्क दिया कि मृत्युदंड ने दोषी को अन्य कैदियों से स्पष्ट रूप से अलग के रूप में चिह्नित किया और अब "मानव परिवार के सदस्य" नहीं हैं।

वास्तव में, शोधकर्ताओं ने पाया है कि जिन व्यक्तियों को फांसी देने में सहायता करनी चाहिए, वे बड़े हत्यारों को "अमानवीय" करके मनोवैज्ञानिक आत्म-सुरक्षा में संलग्न होते हैं क्योंकि वे "किसी भी मानवीय गुणों से रहित" होते हैं। अमानवीकरण को इस दावे से व्यक्त किया जा सकता है कि, "जिन हत्यारों को मौत की सजा मिलती है, वे पूर्ण मानव माने जाने का अधिकार खो देते हैं।" सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि हत्या में भागीदारी भारी मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करती है, भले ही पूरी तरह से कानूनी हो। निष्पादक (और अन्य जिन्हें मारना चाहिए, जैसे कि सैनिक) मनोवैज्ञानिक मुकाबला तंत्र विकसित करते हैं जो उनके अवरोधों और उनकी घातक भूमिकाओं के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव या "नैतिक चोट" को सीमित करते हैं।

शोधकर्ताओं ने निष्पादन प्रक्रिया में शामिल जेल कर्मियों द्वारा नियोजित मुकाबला तंत्र के प्रकारों का अध्ययन किया है। 2005 में प्रकाशित एक अध्ययन में, स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने तीन जेलों का दौरा किया जहां फांसी दी गई थी, और निष्पादन दल के सदस्यों के नैतिक विघटन के स्तर का अध्ययन किया, पीड़ितों के परिवारों और दोषी कैदियों को सांत्वना देने वाले दल के सदस्यों का समर्थन किया, और निष्पादन प्रक्रिया में कोई संलिप्तता नहीं रखने वाले जेल गार्ड नहीं हैं।

। शोधकर्ताओं ने पाया कि "[नैतिक आत्म-प्रतिबंधों को नकारने के लिए, जल्लाद जीवन लेने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि प्रक्रिया की गरिमा में सांत्वना चाहते हैं और इस विचार से कि दोषी हत्यारों का उनके स्वभाव के लिए एक उत्तम प्रकृति है और उन्हें

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

निष्पादित करना जनता की रक्षा करेगा। "तीनों समूहों-जल्लादों, समर्थकों और गार्डों-ने कुछ हद तक कैदियों को "अमानवीय" बना दिया, और जल्लादों ने ऐसा सबसे अधिक किया। पहले के अध्ययनों के आधार पर, शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि "अपराधियों को उन लोगों द्वारा अमानवीय बनाया जाता है जिन्हें मानव जीवन लेना पड़ता है।" स्टैनफोर्ड

अध्ययन ने जल्लादों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को उजागर किया, और इसके निष्कर्षों से पता चल सकता है कि जल्लादों को निर्देशित करने वाले जेल प्रशासक भी मौत की सजा पाए कैदियों के साथ ऐसे तरीके से व्यवहार कर सकते हैं जो उन्हें अमानवीय बनाते हैं। जैसा कि ल्योन और कनिंघम ने नोट किया है, मौत की सजा पर अलगाव मौत की सजा वाले कैदी को एक दुष्चक्रपूर्ण अपराधी के रूप में लेबल करता है जिसने एक घृणित अपराध किया है जिसके लिए उसे निष्पादन की प्रतीक्षा करते हुए दूसरों से स्थायी रूप से अलग रहना चाहिए। उसका अलगाव और अलगाव इस भावना की पुष्टि करता है कि वह खतरनाक, दुष्चक्रपूर्ण और मानव संपर्क के लिए अयोग्य है। अलगाव, व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रतिबंध, और शारीरिक और मानसिक ठहराव मौत की सजा पाने वाले प्रतिवादियों की भावना को बढ़ाता है क्योंकि वे पशु हैं और उन मनुष्यों से अलग हैं जो जीवन का अधिकार बनाए रखते हैं। वास्तव में, इस तरह का व्यवहार कैदियों को वास्तव में मानवता का दुश्मन बनने के लिए प्रेरित कर सकता है जिसे उन्हें पहले लेबल किया गया था।

कुछ जेलों में मौत की सजा पाए कैदियों को अलग करने के लिए अतिरिक्त दृश्य मार्करों के साथ-साथ शारीरिक बाधाओं का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, फ्लोरिडा में, मौत की सजा पाए कैदियों को अन्य कैदियों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाता है क्योंकि उन्हें नारंगी टी-शर्ट पहनना चाहिए। ये सतही भेद इन कैदियों द्वारा किए गए अपराधों की याद दिलाते हैं, जो उन्हें बाकी मानवता और यहां तक कि जेल समुदाय से अलग करते हैं।

मृत्युदंड की नीतियों को अपनाकर जिनके लिए व्यक्तिगत मूल्यांकन के बिना कैदियों के स्वचालित अलगाव की आवश्यकता होती है, जेल अधिकारी व्यक्तिगत संपर्कों की आवश्यकता से बचते हैं जो इन कैदियों के बारे में उनके दृष्टिकोण पर संदेह पैदा कर सकते हैं और उनकी सामान्य मानवता को प्रकट कर सकते हैं। मौत की सजा पाए कैदियों को जिन्हें दूसरों की सुरक्षा के लिए अलग और अलग किया जाना चाहिए, जेल प्रशासकों को असमर्थता के आधार पर कर्तव्यों के रूप में चिह्नित करके, या यहां तक कि प्रतिशोध या सामान्य प्रतिरोध के कारणों से उनकी हत्या को उचित ठहराना आसान लग सकता है। इसके अलावा, जिस हद तक दोषी कैदियों को दूसरों से अलग किया जाता है और वे समाज

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

(यहां तक कि जेल समाज) में योगदान करने में असमर्थ होते हैं, उनका निरंतर अस्तित्व व्यर्थ लग सकता है और उनके निष्पादन को आर्थिक आधार पर भी तर्कसंगत बनाया जा सकता है।”

(83) हार्वर्ड लॉ रिव्यू में प्रकाशित लेख में शीर्षक के तहत "क्रूरता का मनोविज्ञान: अमेरिकी जेलों में गंभीर मानसिक नुकसान को पहचानते हुए, विद्वान लेखक ने "एकांत कारावास" के निम्नलिखित गंभीर संवैधानिक/कानूनी मुद्दों से निपटा है:-

पिछले चालीस वर्षों में, अमेरिकी जेलों ने तेजी से कैद के एक क्रूर तरीके पर भरोसा किया है जो कैदियों को गंभीर पीड़ा देता है। इस तरह से सीमित कैदियों ने मतिभ्रम और अवधारणात्मक विकृतियों से लेकर आत्म-विच्छेदन और आत्महत्या के विचारों तक के लक्षणों को सहन किया है। इन कैदियों के पास से चलते हुए, कोई भी कैदियों के शवों को उनकी कोठरी की दीवारों पर लड़खड़ाते, चिल्लाते और पीटते हुए देख सकता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कारावास की इस विधि का कैदियों के कल्याण पर भयानक प्रभाव पड़ता है, और फिर भी क्योंकि यह शारीरिक नुकसान के बजाय मानसिक नुकसान पहुंचाती है, अदालतों ने काफी हद तक आंखें मूंद ली हैं।

एकांकी कारावास-सामाजिक संपर्क या पर्यावरणीय उत्तेजना के लिए सीमित अवसर के साथ अलगाव में एक कैदी का कारावास-सदियों से अमेरिका में मौजूद है, लेकिन बीसवीं शताब्दी के अंत तक, इसका शायद ही कभी उपयोग किया जाता था। 1970 और 1980 के दशक में, एकांत कारावास का उपयोग बढ़ने लगा, क्योंकि जेलों ने इसे न केवल अनुशासन और सुरक्षा के लिए, बल्कि अमेरिका की सुपरमैक्स जेलों में भी, दीर्घकालिक कारावास की एक विधि के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। सुपरमैक्स जेल-ऐसी जेल जहाँ कैदियों को एकांत कारावास की स्थायी स्थितियों में रखा जाता है-1983 में पहली बार खोले जाने के बाद से पूरे देश में फैली हुई है। आज, लगभग चालीस राज्यों में कम से कम एक सुपरमैक्स जेल है, और देश भर में लगभग साठ कुल सुविधाएं संचालित हैं। हालांकि अनुमान अलग-अलग हैं, अधिकांश का निष्कर्ष है कि वर्तमान में लगभग 25,000 कैदी सुपरमैक्स में सुविधाओं में सुपरमैक्स सेटिंग के बाहर एकांत कारावास में अन्य 55,000 के साथ कैद हैं। हालांकि एकांत कारावास के लिए आठवें संशोधन की चुनौतियों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन वे शायद ही कभी सफल हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कारावास की शर्त एक कैदी को "एकल, पहचान योग्य मानव आवश्यकता" से असंवैधानिक होने से वंचित करती है

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

और मुट्ठी भर अदालतों ने उन जरूरतों को उन चीजों तक सीमित कर दिया है जिनसे एक व्यक्ति को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुँचाए बिना वंचित नहीं किया जा सकता है-इस नोट के उद्देश्यों के लिए, "शारीरिक आवश्यकताएँ।" पर्याप्त मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका

वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि सामाजिक संपर्क से वंचित होने से गंभीर नुकसान होता है, लेकिन यह नुकसान मानसिक है, शारीरिक नहीं-जिसका अर्थ है कि सामाजिक संपर्क एक "मानसिक आवश्यकता" होगी-और यह अंतर काफी हद तक दुर्गम साबित हुआ है। निचली अदालतों ने कारावास की स्थितियों में गंभीर मानसिक नुकसान को शायद ही कभी मान्यता दी है, और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कभी नहीं किया है। हालाँकि, पिछले पंद्रह वर्षों में, न्यायालय ने एक और आठवें संशोधन परीक्षण, आनुपातिकता जांच के अपने आवेदन को सूचित करने के लिए हाल के मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक साक्ष्य पर भरोसा किया है। यदि न्यायालय गंभीर मानसिक नुकसान और इसके कारण होने वाले असंवैधानिक मानसिक अभावों की पहचान करने के लिए एक आधार के रूप में मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग करता है, तो कारावास मूल्यांकन की शर्तें भी इसी तरह अधिक व्यापक और मजबूत हो जाएंगी। इस जानकारी से खुद को लैस करके, न्यायालय यह पूरी तरह से सुनिश्चित करेगा कि वह क़रूरता को रोकने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करे, चाहे उसका कोई भी रूप हो।

यह नोट चार भागों में आगे बढ़ता है। भाग I आनुपातिकता और कारावास पूछताछ की शर्तों के सैद्धांतिक ढांचे को प्रस्तुत करता है और दोनों परीक्षणों को सूचित करने के लिए मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक अनुसंधान के न्यायालय के पिछले उपयोग की जांच करता है। भाग II में पहले वर्णन किया गया है कि किशोर दोष के संबंध में मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक अनुसंधान के न्यायालय के उपयोग ने आनुपातिकता मूल्यांकन को कैसे मजबूत किया। इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि यदि न्यायालय मानसिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग करता है तो न्यायालय इसी तरह कारावास जांच की स्थितियों में सुधार करेगा। यह भाग विशेष रूप से सामाजिक संपर्क के बारे में अनुसंधान की मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक स्थिति पर केंद्रित है। भाग III मानसिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक अनुसंधान के न्यायिक उपयोग के खिलाफ तर्कों पर विचार करता है और उन्हें अस्वीकार करता है। भाग IV निष्कर्ष निकलता है।

I. आठवें संशोधन पूछताछ के लिए मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका संबंधी अनुसंधान लागू

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

करना।

क़रूर और असामान्य दंड पर आठवें संशोधन का निषेध एक विकसित मानक है, जो

"शारीरिक रूप से बर्बर दंड" से अधिक को प्रतिबंधित करता है जो गणतंत्र के शुरुआती दिनों में इसका केंद्र था। जबकि न्यायालय का आठवां संशोधन सिद्धांत विकसित हो रहा है, आज यह दो शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा उन दंडों को नियंत्रित करती है जो किसी अपराध के जवाब में दिए जाते हैं, इस क्षेत्र में प्राथमिक जांच यह है कि क्या दंड "अपराध की गंभीरता के अनुपात से बहुत अधिक है।" 24 आठवें संशोधन न्यायशास्त्र की दूसरी शाखा जेलों के भीतर स्थितियों को नियंत्रित करती है।

A. असंवैधानिक दंड: आनुपातिकता जांच

1. सैद्धांतिक ढांचा। — आनुपातिकता जांच का उपयोग करके दंड की सर्वोच्च न्यायालय की जांच आम तौर पर मामलों के दो समूहों में विभाजित होती है। पहला समूह इस बात पर विचार करता है कि क्या वर्ष की सजा की अवधि किए गए अपराध के लिए असमान है। इस मूल्यांकन को करने में, न्यायालय पहले यह निर्धारित करने के लिए सजा की एक सीमा जांच करता है कि क्या यह किए गए अपराध के लिए "अत्यधिक असमान" है। यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसा है, तो न्यायालय प्रारंभिक निर्णय को "मान्य" करने के लिए अंतर-न्यायिक और अंतर-न्यायिक "तुलना करता है। हालाँकि अदालत ने कभी-कभी असमान होने के लिए साल की सजा सुनाई है, लेकिन प्रतिवादियों के लिए जीत दुर्लभ रही है। मामलों का दूसरा समूह यह आकलन करता है कि क्या कोई विशेष सजा किसी निश्चित अपराध या अपराधियों के वर्ग के लिए स्पष्ट रूप से असमान है। कोकर बनाम जॉर्जिया पूर्व का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। वहाँ, अदालत ने माना कि मृत्युदंड एक वयस्क महिला के बलात्कार के अपराध के लिए एक असमान दंड था। रोपर बनाम सिमंस उत्तरार्द्ध का एक उदाहरण दिखाता है। रोपर में, अदालत ने माना कि मौत की सजा उन लोगों के लिए एक असमान दंड था जिन्होंने अठारह वर्ष से कम उम्र में अपने अपराध किए थे। चाहे कोई अपराध हो या अपराधियों का एक वर्ग मुद्दा हो, न्यायालय उन्हीं कदमों का पालन करता है। यह पहले उस अपराध या अपराधियों के वर्ग पर सजा लागू करने के लिए सामाजिक अनुमोदन के वस्तुनिष्ठ संकेत को देखता है और फिर अपने स्वयं के स्वतंत्र निर्णय का उपयोग करके सजा की जांच करता है। उदाहरण के लिए, कोकर में, न्यायालय ने पहले यह निर्धारित किया कि राज्य विधानसभाओं ने शायद ही कभी बलात्कार के अपराध के लिए मृत्युदंड को मंजूरी दी थी, और जूरी ने कभी-कभी इसे लागू किया था। इसके बाद इसने

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

अपने स्वतंत्र निर्णय का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया कि मृत्यु एक वयस्क महिला के बलात्कार के लिए एक असमान दंड था, मुख्य रूप से क्योंकि पीड़ित की मृत्यु नहीं होती

है। हाल के वर्षों में, न्यायालय ने सामाजिक अनुमोदन के वस्तुनिष्ठ संकेत के बावजूद स्पष्ट रूप से असमान दंड खोजने के लिए अपने स्वतंत्र निर्णय का उपयोग करने की अधिक इच्छा दिखाई है।”

2. मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग। — 2000 के दशक की शुरुआत में, अदालत ने मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान को देखना शुरू किया जब यह जांच की गई कि क्या कोई सजा कुछ वर्गों के अपराधियों के लिए किए गए अपराध के अनुपात में थी। वस्तुनिष्ठ संकेत में प्रारंभिक जांच करने के बाद, न्यायालय ने अपनी स्वतंत्र जांच के हिस्से के रूप में मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक साक्ष्य पर विचार किया है। मुख्य रूप से, न्यायालय ने इस तरह के साक्ष्य का उपयोग यह दिखाने के लिए किया है कि अपराधियों के एक वर्ग के पास किसी विशेष सजा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दोष नहीं है। लेकिन न्यायालय ने ऐसे साक्ष्य को अन्य कारणों से आनुपातिकता के लिए भी प्रासंगिक पाया है: क्योंकि कम मानसिक क्षमता वाला प्रतिवादी एक दुर्जेय बचाव प्रस्तुत करने में कम सक्षम हो सकता है और क्योंकि, ऐसे प्रतिवादी के लिए, सजा के लिए केंद्रीय औचित्य-प्रतिरोध और प्रतिशोध-कम प्रभावी हैं।

न्यायालय आनुपातिकता जांच करते समय हमेशा मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक साक्ष्य का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं रहा है। 1989 के स्टैनफोर्ड बनाम केंटकी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह आकलन करने में मनोविज्ञान को देखने से इनकार कर दिया कि क्या किशोर प्रतिवादियों के पास मृत्युदंड के साथ दंडित किए जाने के लिए आवश्यक दोष है या नहीं। मृत्युदंड। उसी वर्ष, पेनरी बनाम लिनाँघ, 45 में न्यायालय ने न्यायमित्त्र द्वारा प्रस्तावित एक अभिनिर्णय को अपनाने से इनकार कर दिया कि बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के पास कभी भी मृत्युदंड के योग्य होने के लिए आवश्यक दोष नहीं होता है। न्यायालय ने एटकिंस बनाम वर्जीनिया में रास्ता बदल दिया। वहाँ, उस वस्तुनिष्ठ संकेत को निर्धारित करने के बाद-पेशेवर मनोवैज्ञानिक संगठनों की राय सहित-बौद्धिक अक्षमता वाले प्रतिवादियों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की ओर इशारा किया, अदालत ने अपनी स्वतंत्र जांच के दौरान मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक शोध पर ध्यान दिया, जिसने पुष्टि की कि मृत्युदंड अनुचित था। न्यायालय ने एटकिंस के बाद के निर्णयों की एक श्रृंखला में इसी दृष्टिकोण को लागू किया जिसमें किशोर अपराधियों के लिए कुछ दंडों की

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

आनुपातिकता की जांच की गई थी। इनमें से पहले मामले में, रोपर, न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक साक्ष्य पर भरोसा किया कि

किशोर अपराधियों पर लागू होने पर मृत्युदंड असंवैधानिक है। अदालत ने ग्रा-हैम बनाम फ्लोरिडा में इसी तरह के साक्ष्य का हवाला दिया, जहां उसने माना कि पेट्रोल के बिना जीवन (एल. डब्ल्यू. ओ. पी.) एक किशोर के लिए एक असमान सजा है जो हत्या नहीं करता है। न्यायालय ने रोपर में अपने विश्लेषण और बाद के साक्ष्य दोनों की ओर इशारा किया जो किशोरों की घटती दोषिता को दर्शाते हैं। इनमें से सबसे हाल के मामलों में, मिलर बनाम अलबामा, अदालत ने मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक साक्ष्य की ओर रुख किया जब उसने माना कि अनिवार्य एल. डब्ल्यू. ओ. पी. असंवैधानिक है जब किशोरों पर लागू किया जाता है, चाहे कोई भी अपराध हो। अपने पहले के निर्णयों के दृष्टिकोण से हटकर, न्यायालय ने पहले विज्ञान पर विचार किया और फिर विधायी अनुमोदन जैसे वस्तुनिष्ठ संकेत की ओर रुख किया। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह अधिकांश राज्य विधानसभाओं के निर्णय से बाध्य नहीं है कि एल. डब्ल्यू. ओ. पी. हत्या करने वाले किशोरों के लिए एक स्वीकार्य सजा है।

(84) फोर्डहैम लॉ रिव्यू में अपने खंड 85 अंक 6 में "किंग्सले के बाद जेल अलगाव" शीर्षक के तहत प्रकाशित लेख में कहा गया है:

विद्वतापूर्ण लेखिका दीमा ने कहा कि प्रीट्रायल कैद और उभरते वयस्कता के बीच में एकांत कारावास को समाप्त करना।

नगीब ने "एकान्त कारावास" के मुद्दे पर नीचे विस्तार से चर्चा की है:-

एकान्त कारावास: पागलपन पैदा करना

एकांत कारावास में आम तौर पर प्रति दिन बाईस से चौबीस घंटे के लिए "खिड़की रहित कोठरी [जो कि एक विशिष्ट पार्किंग स्थान से बड़ी नहीं है]" में अलगाव होता है। अभ्यास की एक सर्वोत्कृष्ट विशेषता "अत्यधिक संवेदी अभाव" है। "एकान्त कारावास में रखे गए व्यक्तियों को अक्सर सीमित समय में "किसी के साथ बातचीत या बातचीत के लिए बहुत कम या कोई अवसर नहीं दिया जाता है" जब उन्हें अपनी कोठरी के बाहर जाने की अनुमति दी जाती है।

प्रारंभ में 2017 के आपराधिक न्याय मर्डर रेफरेंस No.03 और अन्य संबंधित अपील

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

88 सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में स्थापित, एकांत कारावास का उपयोग अब मुख्य रूप से सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जेल और जेल प्रशासकों के प्रति न्यायिक

सम्मान के बावजूद, शोध से पता चलता है कि यह प्रथा संस्थागत व्यवस्था और सुरक्षा को बढ़ाने की तुलना में लंबे समय तक चलने वाले, कभी-कभी स्थायी, प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव पैदा करने की अधिक संभावना है।

1. संस्थागत हिंसा पर औचित्य और प्रभाव एकल कारावास को पहली बार आपराधिक सजा में सुधार के लिए पेश किया गया था। इस प्रथा के समर्थक एक सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में आपराधिक सजा की बर्बर प्रकृति से चिंतित थे। उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में, अलगाव का उद्देश्य "शांत चिंतन के माध्यम से आत्मा को मुक्त करना था।" हालाँकि, समय के साथ इस प्रथा के औचित्य बदल गए हैं। जैसा कि एक विद्वान ने उल्लेख किया, एकांत कारावास "सामाजिक सुधार में एक खुले, आशावादी प्रयोग से सजा और नियंत्रण के एक गुप्त, गुप्त स्थान में बदल गया है।"

आज, जेल प्रशासक मुख्य रूप से सुरक्षा उपाय के रूप में एकांत कारावास के उपयोग का समर्थन करते हैं। प्रशासकों और अधिकारियों को अपनी सुविधाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में सक्षम होना चाहिए, और एकांत कारावास अधिकारियों को अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन के लिए आसान-से-लागू मंजूरी प्रदान करता है। जेलों प्रवेश से इनकार नहीं कर सकती हैं। वे ऐसी आबादी को घर देते हैं जो क्षणिक और अक्सर संकट में होती हैं। इस प्रकार, सुधार अधिकारियों को इस बारे में चुनाव करने के लिए मजबूर किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की देखभाल कैसे की जाए जो संस्थागत सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, अक्सर विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय के बिना।

सुधार अधिकारी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, कर्मचारियों और अन्य लोगों पर हमलों से चिंतित हैं जो जेल में हैं। करेक्शन ऑफिसर्स बेनेवोलेंट एसोसिएशन के कानूनी मामलों के निदेशक मार्क स्टीयर ने यह समझाते हुए एकांत कारावास को उचित ठहराया कि उन्हें 20,40,60 बार कर्मचारियों पर हमला करने वाले लोगों से निपटने का कोई दूसरा तरीका नहीं पता है। उनका मानना है कि समाधान सरल है: "[अगर मैं आपसे संपर्क नहीं कर सकता, तो मैं आप पर हमला नहीं कर सकता।

स्टेयर के दिमाग में अलगाव, यह सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक तंत्र है कि सबसे खतरनाक लोगों की दूसरों तक पहुंच न हो। हालांकि, संस्थागत हिंसा के स्तर को कम

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

करने के लिए आवश्यक साधन के रूप में एकांत कारावास को उचित ठहराना संभवतः "अप्रमाणित" है। सबसे पहले, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि एकांत कारावास का

उपयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए आरक्षित नहीं है जो संस्थागत सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। दूसरा, शोध से पता चलता है कि एकांत कारावास संस्थागत हिंसा के स्तर को कम नहीं करता है। एक शोधकर्ता ने पाया है कि एकांत कारावास का हिंसा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है-उनके अध्ययन में हिंसा का समग्र स्तर न तो बढ़ा और न ही कम हुआ। अन्य लोगों ने पाया है कि एकांत कारावास वास्तव में हिंसा को बढ़ाता है। कुछ मामलों में, अलगाव लोगों को अधिकारियों पर "मल, मूत्र और/या वीर्य" फेंकने के लिए प्रेरित करेगा। अलगाव से "क्रोध, क्रोध और आक्रामकता के अनियंत्रित प्रकोप" भी हो सकते हैं।" इस तरह के व्यवहार के लिए दंडात्मक प्रतिक्रिया एकांत कारावास में अधिक समय होती है, जिससे एक प्रतिक्रिया लूप बनता है जहां संस्थागत रूप से अस्वीकार्य आचरण को एक मंजूरी के साथ पूरा किया जाता है जो इस संभावना को बढ़ाता है कि आचरण की पुनरावृत्ति होगी।

2. एकान्त कारावास के प्रभावः एकांत कारावास के संभावित हानिकारक प्रभावों को 1890 की शुरुआत में जाना जाता था। इन री मेडले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एकांत कारावास में रहते हुए,

[क] काफी संख्या में कैदी, यहां तक कि एक छोटे से कारावास के बाद भी, एक अर्ध-कठिन स्थिति में गिर गए, जिससे उन्हें जगाना असंभव था, और अन्य हिंसक रूप से पागल हो गए; अन्य ने अभी भी आत्महत्या कर ली; जबकि जो लोग अग्निपरीक्षा को बेहतर तरीके से सहन करते थे, उनमें आम तौर पर सुधार नहीं किया गया था, और ज्यादातर मामलों में समुदाय की किसी भी बाद की सेवा के लिए पर्याप्त मानसिक गतिविधि ठीक नहीं हुई थी।

डॉ. स्टुअर्ट ग्रासियन, एकान्त कारावास के प्रभावों के विशेषज्ञ, ने इस चिंता को संबोधित किया और फटकार लगाई कि आमतौर पर एकान्त कारावास अनुसंधान की विशेषता वाली स्व-रिपोर्ट अतिरंजित हो सकती हैं। उन्होंने पाया कि उनके साक्षात्कारकर्ता वास्तव में तर्कसंगत थे और जब तक उन्होंने आगे की जांच नहीं की, तब तक वे पूरी तरह से शामिल होने से बच रहे थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने बताया कि उनके साक्षात्कारकर्ताओं में से एक ने छोड़ने की इच्छा के साथ एकांत कारावास में रहते हुए अपने आत्म-नुकसान को तर्कसंगत बनाया।

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

ग्रासियन ने प्रारंभिक इनकार और तर्कसंगतकरण का एक पैटर्न पाया, जो पूछताछ के

माध्यम से विषयों को दबाए जाने के बाद अत्यधिक चिंता की ओर बढ़ रहा था। कुछ साक्षात्कारकर्ताओं ने डर व्यक्त किया कि गार्ड अपनी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे या वे वास्तव में "पागल हो रहे हैं।" इस शोध से पता चलता है कि साक्षात्कारकर्ताओं के संभावित पूर्वाग्रह आमतौर पर अतिशयोक्ति के विपरीत अभ्यास के प्रभावों की स्वीकृति की कमी की ओर इशारा करते हैं।

अपने अध्ययनों में, ग्रासियन ने एकांत कारावास से जुड़े एक अलग मनोरोग सिंड्रोम की पहचान की, जिसमें बताया गया कि इससे जुड़े कई लक्षण या तो दुर्लभ हैं या कहीं और नहीं पाए जाते हैं। पेलिकन बे स्टेट जेल की एकान्त कारावास इकाई में कैद उनतालीस व्यक्तियों के अपने मूल्यांकन में, उन्होंने पाया कि "कम से कम सत्रह सक्रिय रूप से मनोवैज्ञानिक और/या तीव्र रूप से आत्मघाती थे।....., और तेइस अन्य लोगों को एकांत कारावास के लिए गंभीर मनोरोग संबंधी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा।" एकान्त कारावास से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोग अक्सर प्रलाप, मतिभ्रम और भटकाव से पीड़ित होते हैं। इन मानसिक अवस्थाओं में, व्यक्ति अक्सर अलग हो जाते हैं और याद नहीं कर पाते कि क्या हुआ था। ग्रासियन के नमूने में अधिक लचीला के बीच-जिसे उन्होंने उच्च शिक्षित और उच्च कार्यशीलता के रूप में वर्णित किया-उन्होंने "अवधारणात्मक गड़बड़ी, मुक्त-तैरने की चिंता, और आतंक के हमलों" के लक्षण पाए।" ग्रासियन ने निष्कर्ष निकाला कि एकांत कारावास में निहित स्थितियां "मानसिक कार्यप्रणाली के लिए आश्चर्यजनक रूप से विषाक्त हैं, जो अवधारणात्मक और संज्ञानात्मक हानि और भावात्मक गड़बड़ी से जुड़ी एक मूर्खतापूर्ण स्थिति पैदा करती हैं।"

डेनमार्क में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि एकांत कारावास में रखे गए व्यक्तियों जो सामान्य जनसंख्या आवास में हैं। ने की तुलना में मनोवैज्ञानिक विकारों की काफी अधिक घटनाओं का अनुभव किया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि एकांत कारावास में व्यक्तियों को मनोदैहिक लक्षणों के साथ अवसाद और चिंता जैसे समायोजन विकारों के विकास का अधिक खतरा था। पैनिक अटैक, पोस्टट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, "क्रोनिक हाइपर-विजिलेंस" और जुनूनी विचार भी लक्षणात्मक हैं। एकान्त कारावास में व्यक्ति का भावनात्मक कल्याण भी प्रभावित होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, और स्वस्थ मस्तिष्क की कार्यप्रणाली "सामाजिक सोच और संवेदी व्याख्या" पर पनपती है।" लोगों को काम करने के लिए "बाहरी दुनिया के साथ निरंतर सार्थक संपर्क" की आवश्यकता होती

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

है। "घनिष्ठ सामाजिक संबंधों और समृद्ध सामाजिक नेटवर्क" तक पहुंच के साथ स्वास्थ्य

और कल्याण में सुधार होता है, जिससे एकांत कारावास में लोगों को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। पूर्ण अलगाव, कई मायनों में, नकारात्मक सामाजिक संपर्क से भी बदतर हो सकता है।

जो लोग अलग-थलग हैं, वे कड़वाहट और निराशा के बीच रहते हुए बहुत अधिक भावनात्मक क्षति का सामना कर सकते हैं।” उन्हें लगता है कि कारावास उन्हें "तोड़ने" की कोशिश कर रहा है और "उनकी भावनाओं पर नियंत्रण के पूर्ण नुकसान का वर्णन करता है।” इन विचारों से उत्पन्न होकर, वे भारी मात्रा में क्रोध, आक्रोश और निराशा भी महसूस करते हैं। डॉ. क्रेग हैनी ने पांच सामाजिक विकृतियों की पहचान की जो अलगाव से निकलती हैं: संस्था पर निर्भरता, व्यवहार शुरू करने में असमर्थता, एक व्यापक "अवास्तविकता की भावना", हताशा और क्रोध, और सामाजिक वापसी। एकान्त कारावास भी प्राथमिक प्रक्रियाओं में प्रतिगमन का कारण बन सकता है, जिसमें "अवास्तविक, विचार के पूर्ववर्ती तरीके, या [विचार] शामिल हैं जिनमें अनुचित ड्राइव घुसपैठ शामिल हैं।” इस प्रतिगमन के अनुरूप आवेग नियंत्रण की कमी, बदला लेने की कल्पनाएँ और व्यामोह हैं।

एकान्त कारावास बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता को भी प्रभावित करता है। अलगाव के दौरान पर्यावरण और सतर्कता के स्तर पर किसी का ध्यान कम हो जाता है। जो लोग अलग-थलग हैं वे "अवधारणात्मक स्थिरता" खो सकते हैं, जिसकी विशेषता है "वस्तुएँ बड़ी और छोटी होती जा रही हैं, 'पिघलती' या रूप बदलती प्रतीत होती हैं, [और] आवाज़ें जोर से और नरम होती जा रही हैं।” इसके अलावा, वे उत्तेजनाओं के प्रति अत्यधिक अति-संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, जो "अत्यधिक अप्रिय हो जाते हैं", और बताते हैं कि "छोटी चिड़चिड़ाहट भयावह हो जाती है।”

इसके अलावा, एकान्त कारावास के प्रभाव शारीरिक होते हैं। एकान्त कारावास "के लिए एक मजबूत जोखिम कारक हो सकता है। धूम्रपान, मोटापा, एक गतिहीन जीवन शैली और उच्च रक्तचाप के रूप में मृत्यु दर।” एकांत कारावास से नींद में गड़बड़ी, सिरदर्द, सुस्ती, चक्कर आना, दिल की धड़कन, भूख न लगना, वजन कम होना, पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं, डायफोरेसिस, पीठ और जोड़ों में दर्द, दृष्टि में गिरावट, हिलना और टंड लगना और पहले से मौजूद चिकित्सा समस्याओं में वृद्धि भी होती है।”

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

एकान्त कारावास का नुकसान अक्सर स्थायी होता है, भले ही किसी की रिहाई के बाद

समय के साथ लक्षण कम हो जाएं। समाज में सफल पुनः प्रवेश के लिए इसके निहितार्थ हो सकते हैं। वास्तव में, लंबे समय तक अलगाव स्थायी हानिकारक भावनात्मक क्षति और सबसे खराब मामलों में, स्थायी "कार्यात्मक अक्षमता" का कारण बन सकता है।" एकान्त कारावास से जुड़े नुकसान थोड़े समय के बाद भी स्थायी हो सकते हैं।

अलगाव से मुक्त होने के तुरंत बाद, चाहे सामान्य जनसंख्या आवास या समाज में, व्यक्ति समायोजन के साथ कठिनाइयों का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार एकांत कारावास का सार्वजनिक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जेल, विशेष रूप से पूर्व-परीक्षण निरोध, अल्पकालिक कारावास के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मुकदमे से पहले जेल में बंद अधिकांश लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, और वे "सामाजिक परिवेश में लौटने के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं होंगे।"

हानि के स्थायी होने और व्यक्तियों में मनोरोग विकार विकसित होने की संभावना उभरते हुए वयस्कों को विशेष रूप से अभ्यास के प्रति संवेदनशील बनाती है। इसके अलावा, उभरते हुए वयस्क जेल में एकांत कारावास के संपर्क में आने की सबसे अधिक संभावना वाले आयु जनसांख्यिकीय हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में किशोरों के लिए एकांत कारावास को "निर्वासित" करने के अपने आह्वान में, प्रोफेसर इयान एम. किसेल ने सुझाव दिया कि बच्चों को वयस्कों से अलग देखने के लिए व्यावहारिक और न्यायशास्त्रीय दोनों कारण हैं जब यह मूल्यांकन करने की बात आती है कि संविधान उनकी रक्षा कैसे करता है जब वे जेल में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता से वंचित होते हैं। निम्नलिखित खंड, उभरते वयस्कता के आसपास अनुभवजन्य अनुसंधान की चर्चा के माध्यम से, दर्शाता है कि उभरते वयस्कों को अलग तरह से देखने के लिए समान व्यावहारिक और न्यायशास्त्र संबंधी कारण हैं।"

(85) शेरोन शैलेव द्वारा लिखित "एकांत कारावास" पर एक स्रोत पुस्तक में, एकान्त कारावास के निम्नलिखित नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है:-

शारीरिक प्रभाव

हालांकि मनोवैज्ञानिक प्रभाव सबसे आम और आमतौर पर प्रमुख होते हैं, फिर भी शारीरिक प्रभाव आमतौर पर रिपोर्ट किए जाते हैं। इनमें से कुछ मनोवैज्ञानिक तनाव की शारीरिक

हरियाणा राज्य बनाम अरुण और अन्य

अभिव्यक्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन ताजी हवा और सूरज की रोशनी तक पहुंच की कमी

और लंबे समय तक निष्क्रियता के शारीरिक परिणाम भी होने की संभावना है। ग्रासियन एंड फ्रीडमैन (1986) ने गैस्ट्रो-आंत्र, हृदय और जननांग-मूत्र संबंधी समस्याओं, माइग्रेन सिरदर्द और गहरी थकान को सूचीबद्ध किया है। ऊपर समीक्षा किए गए कुछ अध्ययनों द्वारा दर्ज किए गए अन्य संकेत और लक्षण हैं:

- दिल की धड़कन (आराम करते समय तेज और/या तेज दिल की धड़कन के बारे में जागरूकता)
- डायफोरेसिस (अचानक अत्यधिक पसीना आना) • अनिद्रा
- पीठ और अन्य जोड़ों का दर्द • दृष्टि में गिरावट
- खराब भूख, वजन में कमी और कभी-कभी दस्त • सुस्ती, कमजोरी
- कंपन (हिलाना) • ठंड लग रही है।
- पहले से मौजूद चिकित्सा समस्याओं का बढ़ना।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव

एकान्त कारावास के सबसे व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए प्रभाव इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। ये व्यक्ति के पूर्व-रुग्ण समायोजन और संदर्भ, अवधि और कारावास की स्थितियों के साथ भिन्न होंगे। पिछले आघात का अनुभव व्यक्ति को अधिक असुरक्षित बना देगा, साथ ही कारावास की अनैच्छिक प्रकृति को सजा के रूप में, और कारावास जो एक निरंतर अवधि तक बना रहता है। यदि कारावास बना रहता है तो प्रारंभिक तीव्र प्रतिक्रियाओं के बाद अधिक पुराने लक्षण हो सकते हैं। जबकि एकान्त कारावास में रखे गए लोगका बहुमत किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना देंगे, ऐसे कैदियों की एक छोटी संख्या हो सकती है जो कुछ संकेत और लक्षण दिखाते हैं और एकान्त कारावास के नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक लचीला हो सकते हैं। लक्षण निम्नलिखित क्षेत्रों में होते हैं और तीव्र से लेकर दीर्घकालिक तक होते हैं।

चिंता, तनाव की भावनाओं से लेकर पूरी तरह से घबराए हुए हमलों तक

- निरंतर निम्न स्तर का तनाव • चिड़चिड़ापन या चिंता • आसन्न मृत्यु का भय • दहशत के हमले

अवसाद, निम्न मनोदशा से नैदानिक अवसाद तक भिन्न होता है• भावनात्मक सपाटपन/धुंधलापन-किसी भी 'भावनाओं' को महसूस करने की क्षमता का नुकसान ।

- भावनात्मक क्षमता (मनोदशा में बदलाव) • निराशा ।
- सामाजिक वापसी; गतिविधि या विचारों की शुरुआत का नुकसान; उदासीनता; सुस्ती
- प्रमुख अवसाद

क्रोध, चिड़चिड़ापन से लेकर पूर्ण क्रोध तक• चिड़चिड़ापन और शत्रुता,

- खराब आवेग नियंत्रण
- दूसरों, स्वयं और वस्तुओं के खिलाफ शारीरिक और मौखिक हिंसा के प्रकोप
- बिना उकसावे के क्रोध, कभी-कभी क्रोध के रूप में प्रकट होता है

संज्ञानात्मक गड़बड़ी, एकाग्रता की कमी से लेकर भ्रमित अवस्थाओं तक

- कम ध्यान अवधि• खराब एकाग्रता
- खराब याददाश्त
- भ्रमित विचार प्रक्रियाएँ; भटकाव ।

अतिसंवेदनशीलता से लेकर मतिभ्रम तक की अवधारणात्मक विकृतियाँ

- शोर और गंध के प्रति अतिसंवेदनशीलता
- सनसनी की विकृतियाँ (जैसे दीवारें बंद हो रही हैं) • समय और स्थान में भटकाव
- अव्यक्तिकरण/अव्यक्तिकरण
- सभी पाँच इंद्रियों को प्रभावित करने वाले मतिभ्रम, दृश्य, श्रवण, स्पर्श, घ्राण और स्वाद (कोशिका में दिखाई देने वाली वस्तुओं या लोगों का e.g.hallucinations, या जब कोई वास्तव में बोल नहीं रहा हो तो आवाजें सुनना) ।

व्यामोह और मनोविकृति, जुनूनी विचारों से लेकर पूर्ण विकसित मनोविकृति तक

- अक्सर एक हिंसक और प्रतिशोधी चरित्र के बार-बार और लगातार विचार (अफवाहें)

(जैसे जेल कर्मचारियों के खिलाफ निर्देशित)

- विभ्रान्त विचार-अक्सर उत्पीड़नकारी
- मनोवैज्ञानिक प्रकरण या अवस्थाएँ: मनोवैज्ञानिक अवसाद, सिज़ोफ़रेनिया ।

आत्मघात और आत्महत्या

19 वीं शताब्दी की अलगाव जेलों की ऐतिहासिक रिपोर्ट बार-बार स्वतः-आक्रामकता, आत्म-विच्छेदन और आत्महत्या के कृत्यों का वर्णन करती हैं। समकालीन अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जेल की आम आबादी (हैनी एंड लिंच 1997:525). उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया में, 2005 में जेल आत्महत्याओं का 69 प्रतिशत अलग-अलग आवास इकाइयों (यूएसए टुडे, 27/12/2006) में हुआ, और इंग्लैंड और वेल्स में 2004/5 में जेल आत्महत्याओं का पांचवां हिस्सा अलगाव इकाइयों (राष्ट्रीय अपराधी प्रबंधन सेवा, सुरक्षित अभिरक्षा समूह) में हुआ। स्व-प्रेरित मृत्यु वार्षिक रिपोर्ट, 2004/5)।

एकान्त कारावास में आत्म-हानि के अन्य रूप भी प्रचलित हैं। शोधकर्ताओं ने नोट किया है कि आत्म-विच्छेदन या काटना अक्सर "स्थितिजन्य तनाव से अचानक निराशा का परिणाम होता है जिसमें कोई अनुमत शारीरिक outlet. Self-addressed आक्रामकता एकमात्र गतिविधि आउटलेट नहीं होती है" (स्कोट और जेंड्रेउ, 1969:341). एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि आत्म-विकृति "स्वयं को असहनीय तनाव से मुक्त करने का एक साधन था-शारीरिक दर्द मानसिक दर्द या शर्म के लिए एक प्रतिपूरक विकल्प बन जाता है" (डाब्रोवस्की (1937), मैकक्लेरी, 1961 में उद्धृत किया गया:303). पूर्व कैदियों ने गवाही दी है कि आत्म-हानि ने उनके लिए एक और भूमिका निभाई जब उन्हें अलगाव में रखा गया था-यह दावा करता है कि वे अभी भी जीवित थे।

मैं पूरी तरह से निराश हो गया था। मैंने कोठरी को तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने खाना खाने से मना कर दिया। मैं पानी लेने से मना करने लगा। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने अपना पेशाब खुद पीना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि वे मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने खुद को चोट पहुँचाई, मुझे बॉडी बेल्ट में डाल दिया गया। आप इतने गुस्से में हो जाते हैं। यह एक निकास है, लेकिन आपको इसे बाहर निकालना होगा। यहाँ तक कि आपका अपना खून भी कुछ वास्तविक है [पूर्व कैदी, यू. के., आने वाले सालेव में उद्धृत]। मैंने खुद को एक भ्रूण की स्थिति में मुड़ा हुआ पाया जो खुद को आगे-पीछे हिला रहा था और दीवार

से अपना सिर टकरा रहा था। सनसनी की अनुपस्थिति में, कभी-कभी खुद को यह समझाना मुश्किल होता है कि आप वास्तव में वहाँ हैं [पूर्व कैदी, यू. एस., ने आई. बी. आई. डी. का हवाला दिया।]।

आत्म-क्षति के उन रूपों के लिए आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है जिनके परिणामस्वरूप मृत्यु नहीं होती है। फिर भी, इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि अलगाव और अलगाव इकाइयों में ऐसी घटनाओं का प्रसार विशेष रूप से अधिक है।

2.4 एकांत कारावास को क्या हानिकारक बनाता है?

एकान्त कारावास में निहित तीन मुख्य कारकों में से प्रत्येक-सामाजिक अलगाव, कम पर्यावरणीय उत्तेजना और दैनिक जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर नियंत्रण का नुकसान-संभावित रूप से परेशान करने वाला है। एक साथ वे एक शक्तिशाली मिश्रण बनाते हैं। इसके अलावा, कैदियों के मनोरोग संबंधी अध्ययनों से संकेत मिलता है कि वे विशेष रूप से कमजोर आबादी हैं, भले ही वे एकांत कारावास में न हों। इंग्लैंड और वेल्स में, 1998 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए कैदियों के एक रुग्णता सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 10 प्रतिशत न्यूरोटिक विकार, मनोवैज्ञानिक विकार, व्यक्तित्व विकार या मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के किसी भी इतिहास के बिना थे, और कई ने इनमें से कुछ या सभी का अनुभव किया (ओ. एन. एस. मनोरोग रुग्णता सर्वेक्षण, 1998)। यह भी ज्ञात है कि लगभग 7 प्रतिशत कैदियों में सीखने की गंभीर अक्षमता होती है, जिनका आई. क्यू. 70 या उससे कम होता है, और यह कि सीखने की अक्षमता वाले लोगों को अलगाव का सामना करने में विशेष रूप से मुश्किल होती है। के लिए जेल में रहने के दौरान लगभग 12 प्रतिशत को मनोरोग गंभीर और स्थायी मानसिक बीमारी उपचार काभी प्राप्त होगा। (एच. एम. सी. आई. पी., कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य, 2007)। इन उच्च स्तर की अशांति का एक कारण प्रारंभिक जीवन के आघात का अनुभव और इसके परिणामस्वरूप खराब व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन है। ये सभी विशेषताएं कैदियों को विशेष रूप से अलगाव, कम गतिविधि, कम उत्तेजना और अपने जीवन पर नियंत्रण खोने के प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाने की साजिश करती हैं। इसके विपरीत, उपाख्यानात्मक साक्ष्य बताते हैं कि कुछ कैदियों को एकांत कारावास के सबसे बुरे प्रभाव से उस अर्थ से बचाया जाता है जो वे अनुभव को बनाने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राजनीतिक कैदियों ने लंबे समय तक कारावास में रहने के दौरान उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। इसका मतलब

यह नहीं है कि अनुभव कठिन नहीं था। रोबेन द्वीप में अपने समय का वर्णन करते हुए, नेल्सन मंडेला लिखते हैं: “मुझे एकांत कारावास जेल जीवन का सबसे निषेधात्मक पहलू लगा। कोई अंत और कोई शुरुआत नहीं है; केवल एक मन है, जो चालें खेलना शुरू कर सकता है। यह सपना था या सच में हुआ? हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं।” (नेल्सन मंडेला, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 1995)। उरुग्वे में टुपामारो आंदोलन के नेता, जिन्हें 1970 के दशक के दौरान कई वर्षों तक सख्त एकांत कारावास में कैद किया गया था (उन्हें किसी के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं थी, गार्डों द्वारा उन्हें कोठरी के दरवाजे में एक हैच के माध्यम से भोजन दिया गया था, जिन्हें उनके साथ एक शब्द का आदान-प्रदान नहीं करने का निर्देश दिया गया था), ने बताया कि एकांत कारावास यातना का सबसे बुरा रूप था; एक कैदी ने कहा कि “लंबे समय तक एकांत की तुलना में बिजली [यातना] केवल बच्चों का खेल है” (रेयेस, 2007:607 में उद्धृत)।

सामाजिक अलगाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सामाजिक कल्याण को 'स्वास्थ्य' की अपनी परिभाषा के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। एकान्त कारावास व्यक्ति को दूसरों की संगति से हटा देता है और उसे अधिकांश प्रकार के सार्थक और सहानुभूतिपूर्ण सामाजिक संपर्क के साथ-साथ शारीरिक संपर्क से वंचित कर देता है। ज्यादातर मामलों में अलग-थलग व्यक्ति साथी कैदियों के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत से वंचित रहता है, और कभी-कभी यात्राओं पर प्रतिबंधों के माध्यम से परिवार और दोस्तों के साथ। जहाँ भेंट होती है वहाँ उन्हें बंद किया जा सकता है, एक बाधा के साथ जो कैदी को उसके आगंतुकों से अलग करती है, उनके बीच किसी भी शारीरिक संपर्क को रोकती है। सामाजिक शिक्षा के सिद्धांत दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क के महत्व को न केवल आनंद और खेल के लिए बल्कि व्यक्ति की स्वयं की भावना जो सामाजिक बातचीत के माध्यम से आकार लेती है के लिए और बनाए रखी जाती है। धारणाओं, अवधारणाओं को बनाने, वास्तविकता की व्याख्या करने और समर्थन प्रदान करने के लिए सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है। स्वयं अनिवार्य रूप से एक सामाजिक संरचना है और यह सामाजिक अनुभव में उत्पन्न होती है। एक आत्म के उत्पन्न होने के बाद, यह एक निश्चित अर्थ में अपने लिए अपने सामाजिक अनुभव प्रदान करता है, और इसलिए हम एक पूरी तरह से एकान्त आत्म की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक अनुभव से बाहर उत्पन्न होने वाले आत्म की कल्पना करना असंभव है। जब यह उत्पन्न हो जाता है तो हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो अपने शेष जीवन के लिए एकांत कारावास में

रहता है, लेकिन जो अभी भी खुद को एक साथी के रूप में रखता है, और अपने साथ सोचने और बातचीत करने में सक्षम है जैसा कि उसने दूसरों के साथ संवाद किया था।

अमूर्तता की इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

अनिश्चित काल के लिए। (मीड, 1934, जोर दिया गया)।

विरोधाभासी रूप से, सामाजिक अलगाव आगे वापसी का कारण बन सकता है। एक अध्ययन में इस परिकल्पना के लिए समर्थन पाया गया कि "बंद-इन" या "एकांत" व्यक्तित्व, जिसे आम तौर पर सिज़ोफ्रेनिया का आधार माना जाता है, "सांस्कृतिक अलगाव" की एक विस्तारित अवधि का परिणाम हो सकता है, यानी अंतरंग और सहानुभूतिपूर्ण सामाजिक संपर्क से अलगाव "(फारिस, 1962:155)। फारिस कहते हैं कि "एकांतता अक्सर एक प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है जो बहिष्करण या अलगाव के साथ शुरू होता है जो रोगी की पसंद नहीं थी" (आई. बी. आई. डी. एट पी. 159)।

अर्थपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण सामाजिक संपर्क और दूसरों के साथ बातचीत से वंचित, एकांत कारावास में कैदी पीछे हट सकता है और पीछे हट सकता है। यहां तक कि जब अलग-थलग किए गए कैदी कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाते हैं, तो अलगाव से रिहा होने पर वे सामाजिक स्थितियों में असहज हो सकते हैं और उनसे बच सकते हैं, जिसके बाद जेल समुदाय और बाहरी समुदाय दोनों में बाद के सामाजिक कामकाज के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जो फिर से सफल पुनर्वास की संभावना को कम कर सकते हैं।

गतिविधि और उत्तेजना में कमी

एकरसता और कम संवेदी उत्तेजना अलगाव के अनुभव का हिस्सा हैं। 19 वीं शताब्दी की पृथक-वास जेलों में, जहां कैदियों की काम तक पहुंच थी, यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरती गई थी कि उन्हें जानबूझकर थकाऊ और सुस्त काम दिए जाएं जो आमतौर पर मौन में किए जाते हैं। जेल, कार्य, शिक्षा या अन्य मोड़ जैसे पढ़ने की सामग्री, रेडियो या टेलीविजन के अलगाव अनुभागों को सजा की प्रणाली के हिस्से के रूप में रोका या प्रतिबंधित किया जा सकता है। जब काम आवंटित किया जाता है, तो यह अक्सर सेल के अंदर आयोजित किया जाता है और, 19 वीं शताब्दी की तरह, सरल और नीरस हो सकता है, उदाहरण के लिए लिफाफे भरना। कैदियों को कम संवेदी या मानसिक उत्तेजना के साथ दिन में 23 घंटे तक कम सुसज्जित कोठरी में रखा जा सकता है।

कैदियों के विवरण अलगाव की अवधि के दौरान उनकी मानसिक स्थिति पर एकरसता और ऊब के प्रभावों को दर्शाते हैं:

ऊब एक बड़ा दुश्मन है। संवेदी अभाव जीवन का एक तरीका है। बस करने के लिए कुछ नहीं है। अपने बाथरूम में अकेले बैठें और अपनी कोई अंतरंग संपत्ति न रखें और सप्ताह दर सप्ताह इसके वर्षों की कल्पना करने की कोशिश करें। धीरे-धीरे यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से निराश कर देता है। थोड़े समय के अलगाव के बाद जो घोर और राक्षसी ऊब इतनी स्पष्ट हो जाती है, वह सर्वशक्तिमान है। पूर्ण आलस्य की प्रवृत्ति से लड़ने और इंदिरियों पर पकड़ बनाए रखने के लिए, बहुत परिश्रम करना आवश्यक है। फिर भी एक कैदी अलगाव के प्रभावों को रोकने में कितना भी सफल क्यों न हो, यह केवल कुछ समय की बात है जब वह उसे पकड़ लेता है (वेकफील्ड 1980:28)।

...आप एकांत कारावास में शून्य में बैठे हैं, न केवल अपनी शून्यता, बल्कि समाज, दूसरों, दुनिया की शून्यता। महीनों की सुस्ती जो एक कोशिका में वर्षों तक जोड़ती है, अकेले, जीवित शरीर की हर 'शारीरिक' गतिविधि के बारे में खुद को उलझा लेती है और इसे धीरे-धीरे मौत के लिए गला घोंट देती है, जो वास्तव में जीवित मृत्यु का भयानक क्षय है। आप अब अपनी छोटी कोशिका में पुश-अप या अन्य शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं; आप अब अपनी कोशिका में चार कदम आगे-पीछे नहीं करते हैं। आप अब हस्तमैथुन नहीं करते हैं; आप अपनी कोठरी में किसी भी form.time में कामुकता की कोई दृष्टि नहीं देख सकते हैं जैसे कि एक ताबूत का ढक्कन जिसमें आप लेटते हैं और इसे देखते हैं क्योंकि यह धीरे-धीरे आपके ऊपर बंद हो जाता है। जेल में एकांत कारावास एक पत्थर के ऑन्टोलॉजिकल मेकअप को बदल सकता है (एबॉट 1982:44-45)।

इन व्यक्तिगत खातों को अध्ययनों द्वारा समर्थित किया जाता है जो अंकित करते हैं कि कम संवेदी इनपुट से मस्तिष्क की गतिविधि कम हो सकती है। इनपुट-आउटपुट सिद्धांत के आधार पर, एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि संवेदी इनपुट और मोटर-मानसिक आउटपुट समानांतर रूप से काम करते हैं:

संवेदी प्रतिबंध के माध्यम से संवेदी इनपुट में गिरावट मानसिक सतर्कता में गिरावट, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, योजना और प्रेरणा में गिरावट, भाषण और मोटर प्रणालियों में शारीरिक गतिविधि में गिरावट के साथ पैदा करती है। जेल जीवन में ऊब ऊब पैदा करती है। प्रोत्साहन इनपुट में गिरावट के परिणामस्वरूप मानसिक सुस्ती, सीखने की अनिच्छा

और योजना, प्रेरणा और शारीरिक गतिविधि में सहसंबद्ध गिरावट आती है (स्कॉट एंड जेंड्रेउ, 1969:338).

इस परिकल्पना का मूल्यांकन करने के लिए, अलग-थलग कैदियों की मस्तिष्क गतिविधि को दैनिक रूप से मापा गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि सात दिनों के अलगाव के बाद मस्तिष्क की गतिविधि में गिरावट आई। यह गिरावट "उदासीन, सुस्त व्यवहार के साथ सहसंबद्ध थी। और व्यवहार की मांग करने वाली उत्तेजना में कमी के साथ सात दिनों तक ई. ई. जी. में गिरावट प्रतिवर्ती है, लेकिन अगर लंबे समय तक वंचित रहता है तो ऐसा नहीं हो सकता है" (स्कॉट एंड जेंड्रेउ, आई. बी. आई. डी.)।

नियंत्रण की कमी

अलग-अलग कारावास का एक तीसरा पहलू कठोर शासन और कैदियों के जीवन के सभी पहलुओं पर असाधारण रूप से उच्च स्तर का नियंत्रण है, या जिसे "सामाजिक नियंत्रण की एक सत्तावादी प्रणाली" (मैकक्लेरी, 1961:272), या "नियंत्रण की समग्रता" (हैनी, 1993) कहा गया है। किसी भी विशेष नियंत्रण या अनुशासनात्मक उपाय से गुजरते समय, अधिकारियों से कुछ हद तक बढ़े हुए नियंत्रण और सतर्कता अपरिहार्य है। हालांकि, एकांत कारावास के मामले में, यह नियंत्रण चरम है और कैदियों के पास कुछ रास्ते या क्षेत्र हैं जहां वे व्यक्तिगत स्वायत्तता का प्रयोग कर सकते हैं, और अपनी सभी बुनियादी जरूरतों के प्रावधान के लिए पूरी तरह से कर्मचारियों पर निर्भर हैं। जब नियंत्रण की इस डिग्री का लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव आनुपातिक रूप से अधिक होता है।

विभिन्न अध्ययनों ने अत्यधिक नियंत्रित वातावरण में दीर्घकालिक कारावास के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक पहलुओं की जांच की है और कुछ सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की पहचान की है। ये आम तौर पर उदासीनता से लेकर आक्रामकता तक होते हैं: "या तो कठोर अनुशासन की प्रणाली के प्रति प्रतिक्रिया कुछ हद तक पागलपन की तरह हो जाती है- उदासीनता, लापरवाही, अनियमितताएं, या फिर चिड़चिड़ापन, घृणा और घबराहट अस्थिरता" (सदरलैंड क्रेसी, 1955:473)। एक अन्य अध्ययन में इसी तरह उल्लेख किया गया है कि समय के साथ, अलग-थलग किए गए कैदियों के द्वारा अनुभव किए गए लक्षण "हत्या या आत्मघाती व्यवहार में परिपक्व होने की संभावना है" (मैकक्लेरी, 1961:265)।

इस प्रकार, एक कैदी पर शांति और नियंत्रण लागू करने के उद्देश्यों के विपरीत, एकांत कारावास अधिक चिड़चिड़ापन और यहां तक कि हिंसक प्रकोप भी पैदा कर सकता है, जो अक्सर बिना उकसावे के होता है। इस तरह के हिंसक प्रकोप कर्मचारियों के खिलाफ निर्देशित किए जा सकते हैं, लेकिन स्वयं कैदी पर आत्म-नुकसान या आत्महत्या के रूप में भी किए जा सकते हैं। जहाँ कैदी अधिक विनम्र हो जाता है और स्पष्ट रूप से नियमों का पालन करता है, यह वास्तव में वापसी, भावनात्मक सुन्नता और उदासीनता के रूप में एक रोगजनक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके अलावा, 'नियंत्रण की संपूर्णता' का मतलब है कि कुछ कैदी अपने जीवन और दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए जेल पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि वे व्यक्तिगत स्वायत्तता का प्रयोग करने की क्षमता खो देते हैं। यह, फिर से, उनकी रिहाई पर उन्हें समाज में निष्क्रिय बना सकता है और कुछ जेल लौटने की कोशिश करेंगे।

2.5 एकान्त कारावास की अवधि

दस दिनों से अधिक समय तक नियमित जेल व्यवस्थाओं में एकान्त कारावास में अनैच्छिक रूप से हिरासत में रखे गए कैदियों के सभी अध्ययनों ने कुछ नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों का प्रदर्शन किया है (हैनी, 2003), और यहां तक कि इस प्रथा के समर्थक भी इस बात से सहमत हैं कि लंबे समय तक दंडात्मक एकांत कारावास "कैदियों के लिए काफी जोखिम प्रस्तुत करता है" (जेंड्रेउ और बॉटा, 1984:475)।

अन्य कैदियों के साथ रखे गए कैदियों की तुलना में एकांत कारावास में रखे गए कैदियों के लिए डेनमार्क के मनोरोग अस्पतालों में बाद में प्रवेश की तुलना करने वाले एक अध्ययन में पाया गया कि चार सप्ताह के बाद अस्पताल में भर्ती होने की दर में काफी अंतर आया। "मनोवैज्ञानिक कारणों से भर्ती होने की संभावना उसी अवधि के लिए गैर-एकांत कारावास में भेजे गए व्यक्ति की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक थी" (सेस्टॉफ्ट एट अल। 1998:105)। सीगल (1984) के 31 लोगों के अध्ययन में, जो अलग-अलग स्थितियों (बंधकों, पी. ओ. डब्ल्यू., कैदियों) में शारीरिक गतिविधि पर अलगाव, दृश्य अभाव और संयम के अधीन थे और अलग-अलग समय के लिए अलग-थलग होने के घंटों के भीतर दृश्य और श्रवण संबंधी मतिभ्रम की सूचना दी गई, जो समय के साथ अधिक गंभीर हो गए दस दिनों तक की अवधि के लिए अलग-थलग किए गए स्वयंसेवी कैदियों के साथ अध्ययन ने आमतौर पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभावों की सूचना दी है। वाल्टर्स एट अल (1963:772) ने नोट किया कि कनाडा में 20 दीर्घकालिक कैदियों के लिए संघीय जेल

जो चार दिनों के लिए एकांत कक्षों में रहने के लिए स्वेच्छा से आया था, जबकि सामाजिक अलगाव व्यक्तिपरक भावनाओं में कुछ बदलाव पैदा कर सकता है, इसके परिणामस्वरूप मानसिक या मनोप्रेरक गिरावट या सामाजिक प्रभाव के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि नहीं होती है।" इसी तरह 1974 में एक्लेस्टोन, जेंड्रेउ और नॉक्स ने बताया कि 10 दिनों की एकांत कारावास की अवधि में आठ स्वयंसेवकों के लिए सामान्य संस्थागत जीवन की तुलना में अधिक तनावपूर्ण नहीं था।" लेकिन इन परिणामों का हिसाब अलगाव में रहने की छोटी अवधि और इस तथ्य से किया जा सकता है कि इन अध्ययनों में भाग लेने वाले कैदियों ने सामान्य जेल की आबादी से दूर समय बिताने के अवसर का स्वागत किया।

स्वयंसेवकों के साथ प्रायोगिक अध्ययनों ने अलगाव के लिए अपेक्षाकृत अल्पकालिक सहिष्णुता की सूचना दी है। हालांकि इस तरह के अध्ययन जेल के संदर्भ में लागू अलगाव के बराबर नहीं हैं, जहां कैदी किसी भी समय प्रयोग को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, निष्कर्ष मानव विषयों पर अलगाव के शक्तिशाली प्रभाव को स्पष्ट करने का काम करते हैं। अलगाव के प्रति सहिष्णुता के स्तर को मापने के उद्देश्य से एक अध्ययन में, लगभग दो-तिहाई स्वयंसेवक तीन से चौदह दिनों तक की अवधि के लिए एक अलग कमरे में रहने में सक्षम थे (जुकरमैन, 1964:255-276)। एक अन्य में, बीस स्वयंसेवकों को एक मूक कमरे में अलग से रखा गया था, और जब तक वे कर सकते थे तब तक उसमें रहने के लिए कहा गया था। छोड़ने का औसत समय पुरुषों के लिए 29.24 घंटे और महिलाओं के लिए 48.70 घंटे था। प्रतिभागियों में से किसी ने भी चार दिनों से अधिक समय तक 'साइलेंट रूम' को सहन नहीं किया (स्मिथ एंड लेवी, 1959:342-345)। जहाँ अलगाव की अवधि अनिर्दिष्ट थी, वहाँ दो घंटे भ्रम पैदा करने और पागल होने का डर पैदा करने के लिए पर्याप्त थे (सोलोमन एट अल, 1961)।

अन्य अध्ययनों ने यह भी प्रदर्शित किया है कि एकान्त कारावास की सहनशीलता के स्तर में एक महत्वपूर्ण तत्व इसकी अवधि का पूर्व ज्ञान है। इसकी अवधि के बारे में अनिश्चितता "असहायता की भावना को बढ़ावा देती है। स्वीकृत कृत्यों के लिए लगाए गए सीमित वाक्य घबराहट को प्रेरित करने के लिए कम प्रवण प्रतीत होते हैं" (टोच, 1992:250)। एक अन्य अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि अनिश्चितता शत्रुता और आक्रामकता (मैकक्लेरी 1961:303) के परिणाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण कारक है। यह जानना कि अनुभव कितना लंबा चलेगा, इसलिए एक कैदी को अलगाव में रखने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए एक स्पष्ट शमन कारक उपलब्ध है।

2.6 अलगाव का क्रम: एकान्त कारावास के स्थायी प्रभाव

एकान्त कारावास के प्रभावों के बारे में कुछ अनुदैर्घ्य अध्ययन हैं और जेल से रिहा होने के बाद पूर्व में अलग-थलग पड़े कैदियों का कोई अनुवर्ती अध्ययन नहीं है। पुनः, कोई भी दीर्घकालिक प्रभाव व्यक्ति, कारावास के प्रकार और इसकी अवधि पर निर्भर होने की संभावना है। कोपनहेगन में पश्चिमी जेल में एकांत कारावास में रिमांड पर रखे गए बंदियों के एक अध्ययन, जिसमें उनके अलगाव के दूसरे से चौथे दिन और उसके बाद मासिक अंतराल पर उनकी जांच की गई, सामान्य आबादी में स्थानांतरण के तुरंत बाद लक्षणों में कमी पाई गई, जो दर्शाता है कि "एकांत कारावास की स्थिति परेशान करने वाली और शायद अस्थायी है, कम से कम आंशिक रूप से" (एंडरसन एट अल। 2003:174)। हालांकि, लेखकों ने नोट किया कि "यह निष्कर्ष कि कैदियों को एकांत कारावास से गैर-एकान्त कारावास में स्थानांतरित करने पर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ है, यह इंगित करता है कि एकांत कारावास एक ऐसी स्थिति लागू करता है जिसे यकीनन इसे समाप्त करके टाला जा सकता है" (पृष्ठ 175 पर इबिद)।

इसी तरह, मैसाचुसेट्स में वालपोल जेल में एकांत कारावास में रखे गए कैदियों के बारे में ग्रासियन (1983) के अध्ययन में, जहां कानूनी कानून के अनुसार अलग-थलग कैदियों को हर 15 दिनों में कम से कम 24 घंटे के लिए उनकी स्थिति से मुक्त किया जाना आवश्यक था, कारावास में विराम के दौरान लक्षणों में तेजी से कमी की सूचना दी गई।

हालांकि, अन्य अध्ययनों में नींद की गड़बड़ी, बुरे सपने, अवसाद, चिंता, भय, भावनात्मक निर्भरता, भ्रम, खराब स्मृति और एकाग्रता (हॉकिंग, 1970) की सूचना दी गई है। ये लक्षण अलगाव में कैदियों द्वारा अनुभव किए गए लक्षणों के समान हैं और कुछ हद तक अपरिवर्तनीयता का संकेत दे सकते हैं। लेकिन एकांत कारावास के स्थायी प्रभाव शायद सामाजिक व्यवस्थाओं और पारस्परिक संबंधों के साथ सबसे अधिक स्पष्ट हैं: हालांकि कैदियों द्वारा पीड़ित कई तीव्र लक्षण एकांत कारावास की समाप्ति पर कम होने की संभावना है, कई [कैदी], जिनमें कुछ ऐसे भी शामिल हैं जो एकांत में कारावास के दौरान खुले तौर पर मानसिक रूप से बीमार नहीं हुए थे, को स्थायी नुकसान होने की संभावना है। यह नुकसान आमतौर पर सामाजिक संपर्क के प्रति निरंतर असहिष्णुता से प्रकट होता है, एक बाधा जो अक्सर कैदी को सफलतापूर्वक सामान्य जनसंख्या जेल और अक्सर गंभीर रूप से में पुनः समायोजित करने से रोकती है। कारावास से रिहा होने पर कैदी की व्यापक समाज में फिर

से शामिल होने की क्षमता को बाधित करता है (ग्रासियन, 2006:332)। लंबे समय तक एकांत कारावास में रहने वाले पूर्व कैदियों ने अपनी रिहाई के लंबे समय बाद सामाजिक स्थितियों में कठिनाइयों का सामना करने की गवाही दी है:

मेरा मतलब है कि अभी भी ऐसे समय हैं जब मैं वॉक-इन में जा सकता हूँ और फिल्म खत्म होने के बाद, आप जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं अंधेरे में था और अचानक रोशनी आती है और मेरे चारों ओर के इन लाखों लोगों को देखते हुए, मुझे लगता है, आप जानते हैं, जैसे, ठीक है, ठीक है, मुझे कौन मारने वाला है, क्या होने वाला है। मेरा मतलब है, आप वास्तव में असहज महसूस करते हैं और फिर अचानक आप हिलने लगते हैं, आप जानते हैं, आप अपने दिल की धड़कन महसूस करते हैं और फिर आपको एहसास होता है, एक मिनट रुकिए, मैं एक थिएटर में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ कोई भी पागल नहीं है। मैं जेल में नहीं हूँ। यह वास्तव में असहज हो जाता है जब मैं एक बड़ी भीड़ के आसपास होता हूँ। जैसे कभी-कभी किराने की दुकान पर जाने से भी मुझे असहज महसूस होता है, आप जानते हैं, जब लोग मुझे देखते हैं, और मैं सोच रहा हूँ, आप जानते हैं, वाह, वे क्या देख रहे हैं? [पूर्व कैदी, अमेरिका। शैलेव में उद्धृत, आगामी]।

मेरे चरित्र और व्यक्तित्व में कई नकारात्मक बदलाव आए हैं और अब मैं एक बहुत ही डरपोक और संदिग्ध व्यक्ति हूँ। व्यामोह इतना व्यापक हो गया है कि मुझे अब किसी पर भरोसा करना असंभव लगता है और मैंने बिना किसी स्पष्ट कारण के लोगों से नफरत करने की प्रवृत्ति विकसित कर ली है (वेकफील्ड, 1980:30)।

'सामान्य' जीवन जीने के लिए आवश्यक सामाजिक कौशल हासिल करने में असमर्थ, कुछ लोग अपनी रिहाई के बाद सापेक्ष सामाजिक अलगाव में रहना जारी रख सकते हैं। इस अर्थ में, एकांत कारावास जेल के मुख्य उद्देश्यों में से एक के खिलाफ काम करता है जो अपराधियों का पुनर्वास करना और समाज में उनके पुनर्एकीकरण की सुविधा प्रदान करना है।”

(86) ऊपर उद्धृत पैराग्राफ 368 के अनुसार, मौत की सजा के तहत प्रत्येक दोषी को अन्य सभी कैदियों के अलावा एक कोठरी में रखा जाना है और उसे दिन और रात में एक विशेष गार्ड के प्रभार में रखा जाना है। उसे अपनी कोठरी के सामने बरामदे में रहने के लिए सुबह और शाम को केवल आधे घंटे की अनुमति है। इस अवधि के दौरान, दोषी को हथकड़ी लगाकर रहना पड़ता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मौत की सजा के तहत दोषी को एक

अलग कोठरी में रखा जाना है। उसे अपनी कोठरी से बाहर आने के लिए केवल आधे घंटे की अनुमति है। उसे प्रकाश की नज़रों के नीचे रखा जाता है। उसे हमेशा पहरेदारों की निगरानी में रखा जाना चाहिए।

(87) जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, एक दोषी को एक अलग कोठरी में रखने से उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण दिल की धड़कन (आराम करते समय तेज और/या तेज दिल की धड़कन के बारे में जागरूकता), डायफोरेसिस (अचानक अत्यधिक पसीना आना), अनिद्रा, पीठ और अन्य जोड़ों में दर्द, दृष्टि में गिरावट, खराब भूख, वजन कम होना और कभी-कभी दस्त, सुस्ती, कमजोरी, कंपकंपी (हिलना), ठंड लगना, पहले से मौजूद चिकित्सा समस्याओं में वृद्धि, चिंता, तनाव की भावनाओं से लेकर पूरी तरह से पैनिक अटैक, लगातार निम्न स्तर का तनाव, चिड़चिड़ापन या चिंता, आसन्न मृत्यु का डर, पैनिक अटैक, अवसाद, कम मनोदशा से लेकर नैदानिक अवसाद तक, भावनात्मक सपाटपन/धुंधलापन-किसी भी 'भावनाओं' को महसूस करने की क्षमता का नुकसान, भावनात्मक क्षमता (मनोदशा में बदलाव), आशा दीवारें बंद हो रही हैं), समय और स्थान में भटकाव, व्यभिचारीकरण/अवास्तविकता, सभी पाँच इंद्रियों को प्रभावित करने वाले मतिभ्रम, दृश्य, श्रवण, स्पर्श, घ्राण और स्वाद (कोशिका में दिखाई देने वाली वस्तुओं या लोगों का, या जब कोई वास्तव में बोल नहीं रहा होता है तो आवाज़ें सुनना), व्यामोह और मनोविकृति, जुनूनी विचारों से लेकर पूर्ण विकसित मनोविकृति तक, बार-बार और लगातार विचार (अफवाहें) अक्सर हिंसक और प्रतिशोधी चरित्र (जैसे। जेल कर्मचारियों के खिलाफ निर्देशित), पागल विचार-अक्सर उत्पीड़न, मनोविकृत प्रकरण या कहते हैं: मनोवैज्ञानिक अवसाद, सिज़ोफ्रेनिया, आत्म-क्षति और आत्महत्या आदि, ये सब परेशानियां हो सकती हैं।

(88) कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों में कहा गया है कि एकांत कारावास का उपयोग केवल असाधारण मामलों में अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। यह किसी कैदी की सजा के आधार पर नहीं लगाया जाएगा। एकांत कारावास का अर्थ है अर्थपूर्ण मानव संपर्क के बिना एक दिन में 22 घंटे या उससे अधिक समय तक कैदियों को कैद करना। लंबे समय तक एकांत कारावास लगातार 15 दिनों से अधिक की अवधि एकांत कारावास को संदर्भित करेगा।

ए (89) पंजाब जेल नियमावली में कहा गया है कि वार्डर किसी भी व्यक्ति को अधिकृत

व्यक्ति के अलावा कैदी के पास जाने या उससे बात करने की अनुमति नहीं देगा। उन्हें एक दिन में 23 घंटे से अधिक समय तक पृथक-वास में रहना चाहिए। यह नेल्सन मंडेला के नियमों के खिलाफ है। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। उसे तब तक एकांत कारावास में रखा जाता है जब तक कि वह बरी नहीं हो जाता या उसे क्षमा नहीं कर दिया जाता या फांसी नहीं दी जाती। ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कि मौत की सजा पाए दोषी को अनिश्चित काल के लिए अलग-थलग क्यों रखा जाना चाहिए जब तक कि वह अपने सभी संवैधानिक और कानूनी उपायों को समाप्त नहीं कर देता। यह दोषी को अत्यधिक पीड़ा, पीड़ा और चिंता का कारण बनता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन है। एक व्यक्ति, जिसे मौत की सजा भी सुनाई गई है, उसके पास कुछ विशेषाधिकार और अधिकार हैं जिन्हें औपनिवेशिक मानसिकता के कारण उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। पंजाब जेल नियमावली के प्रावधान अराजक, क्रूर और असंवेदनशील हैं।

(90) मौत की सजा पाए कैदी को कानून के अनुसार उसकी फांसी की तारीख के बारे में सूचित किया जाना है। दोषी को अनिश्चित काल के लिए अलगाव/अलगाव में रखने से कभी भी कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कानून मानवीय और सुधारात्मक होना चाहिए।

(91) कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए और दमनकारी और मनमाना नहीं होनी चाहिए। कानून न तो हिमनदीय होना चाहिए और न ही दूरस्थ। कानून सभ्यता का ढांचा और गारंटर होना चाहिए।

(92) दोषी को उसके संवैधानिक, कानूनी और मौलिक अधिकारों के समाप्त होने से पहले हिरासत में अलग/एकांत कारावास में रखने की प्रथा कानून के अधिकार के बिना है। यह अतिरिक्त सजा होगी। यह उनके मूल मानवाधिकारों को प्रताड़ित करने और उनका उल्लंघन करने के बराबर भी है।

(93) तदनुसार, हम हरियाणा राज्य में जेल अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रथा को समाप्त करते हैं, जिसमें निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद और उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि के बाद मौत की सजा पाए दोषी को अलग करने की प्रथा असंवैधानिक है। दोषी को तब तक अलग/अलग नहीं किया जाएगा जब तक कि मौत की सजा अंतिम, निर्णायक और अक्षम्य नहीं हो जाती जिसे किसी भी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा रद्द या रद्द नहीं किया जा सकता है। मृत्युदंड की सजा पाए दोषी को अलगाव/अलगाव में रखने की अवधि

कम से कम संभव समय यानी 2 से 3 दिनों के लिए होनी चाहिए ।

(94) विद्वत विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के सही मूल्यांकन के आधार पर संजय चौधरी को बरी कर दिया है जो अपराध के आयोग के साथ से संबंधित नहीं थे । । इस प्रकार विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसे बरी कर दिया गया है ।

(95) नतीजतन, अपील बीयरिंग एन. ओ. एस. । अरुण, राजेश और दीपक द्वारा दायर सी. आर. ए.-डी.-98-डी. बी.-2017, सी. आर. ए.-डी.-104-डी. बी.-2017, सी. आर. ए.-डी.-187-डी. बी.-2017 को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और अपीलार्थियों को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें से अपीलार्थियों को अनिवार्य रूप से छूट का दावा किए बिना कम से कम 20 साल की सजा काटनी होगी । आई. पी. सी. की धारा 366-ए के तहत दीपक को दी गई सजा बरकरार है । हत्या का संदर्भ सं no. 3 /2017 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है । इंदु द्वारा दायर अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है ।

जे. एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा ।

अनुवादक

गरिमा गिलानी